चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

01 दिसंबर-07 दिसंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

अखिलेश सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड

फोटो-प्रभात पाण्डेय

कुछ में है दम बाकी सब बेदम

मार्च 2012 में सत्ता में आने के बाद दो साल विश्राम की मुद्रा में चले जाने वाले विभागों में अल्पसंख्यक कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण, कारागार, पर्यटन, परिवहन, होमगार्ड, वस्त्र उद्योग एवं रेशम, खादी एवं ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, प्राविधिक शिक्षा, ग्रामीण अभियंत्रण (स्वतंत्र प्रभार) और खनन आदि शामिल हैं. इनमें से कई विभाग 2014 में सक्रिय हुए, लेकिन इनमें से भी कुछ विभागों की सक्रियता औपचारिक रही. कई विभागों के 2012 एवं 2013 के काम महज घोषणात्मक रहे हैं, जिनका क्रियात्मकता से कोई लेना-देना नहीं है.

प्रभात रंजन दीन

बीते अक्टूबर में समाजवादी पार्टी के लखनऊ में हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश सरकार के मंत्रियों के कामकाज के तौर-तरीके, उनके भ्रष्टाचार और उनके जन-विरोधी रवैये पर ही चर्चा मुख्य रूप से घूमती रही. यह चर्चा केंद्र में इसलिए रही, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इस पर अपनी चिंता जताई थी. यह ऐसा विषय था, जिस पर मुलायम सिंह लगातार बोलते रहे हैं और अब भी बोल रहे हैं. हालांकि, मुलायम की इस चिंता में गद्दार सपाइयों का मसला घुसाकर घालमेल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन मुलायम की बातें जनता में तीर की तरह घुस गईं, घालमेल की कोशिशें चाहे जितनी भी होती रहें. अब यह बात साफ़ हो गई कि अखिलेश सरकार के मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर ही 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा. अधिवेशन में ही वरिष्ठ सपा नेता नरेश अग्रवाल ने मंच से कहा था कि मंत्रियों के पास कहने के लिए अपना कुछ भी नहीं है, अखिलेश यादव के सिवाय. सही भी है कि कुछ खास वरिष्ठ मंत्रियों को छोड़ दिया जाए, तो काम के दृष्टिकोण से अखिलेश के कामों के सिवाय कहने के लिए कुछ है भी नहीं.

मंत्रियों के कामकाज एवं उनके जन-विरोधी क्रियाकलापों पर बात आई और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न किए जाने की मुलायम सिंह यादव ने मंच से शिकायत की, तो अखिलेश ने क़रीब सात दर्जन उन मंत्रियों की लालबत्ती छीन ली, जो केवल दर्जा प्राप्त मंत्री थे. उनका भ्रष्टाचार भी उनके दर्जे जैसा ही था, जिनके पास लालबत्ती के सिवाय कुछ था भी नहीं. जबकि मुलायम की शिकायत के दायरे में दर्जा प्राप्त मंत्री नहीं, बल्कि वे मंत्री थे, जो कैबिनेट या राज्य मंत्रियों की सूची में शामिल थे. वैसे मंत्री, जिनके हाथ में उनका विभाग और सत्ता का अधिकार था तथा वे अपने निजी हित में उसका पूरा उपभोग कर रहे थे (हैं). मुलायम की मंचीय शिकायतों के ज़रिये सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन ने यह रास्ता खोला कि भ्रष्टाचार के आरोपों एवं शिकायतों के बरक्स हम अखिलेश सरकार के मंत्रियों के परफॉर्मेंस का भी हिसाब-किताब लें, ताकि सक्रिय-निष्क्रिय मंत्री का स्पष्ट विभाजन कर सकें. सक्रिय एवं निष्क्रिय मंत्रियों के बीच में हम सामान्य चाल वाले मंत्रियों की एक कैटेगरी और बना सकते हैं, ताकि वह बीच की विभाजक रेखा के बतौर बनी रहे. मंत्रियों की सक्रियता एवं निष्क्रियता तय करने के लिए उनके विभागवार कामकाज का ब्यौरा खंगाला गया और ज़मीनी स्तर पर उस ब्यौरे के साथ उनकी छवि की तुलना की गई. कई मंत्रियों के कामकाज का दस्तावेजी रिकॉर्ड बिल्कुल नगण्य मिला. जाहिर है, अखिलेश सरकार के कई मंत्री ज़मीनी स्तर पर केवल बात-बहादुरी से काम चलाते रहे, व्यवहारिकता के धरातल पर उनका काम लचर रहा. स्पष्ट है कि ऐसे मंत्रियों की रुचि भ्रष्टाचार एवं जन-विरोधी कार्यकलापों में ही रही, जैसा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव लगातार कहते रहे या अब भी कह रहे हैं.

विकास दर में राज्य सबसे पिछड़ा क्यों

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की विकास कार्यों में दिलचस्पी और उनकी प्राथमिकता का ही नतीजा है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मामले में सालाना विकास दर (सीएजीआर) के लिहाज से चार पिछड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश आख़िरी पायदान पर आ गया. एसोचैम का यह आधिकारिक खुलासा है. एसोचैम ने बीमार राज्यों मसलन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश को लेकर एक अध्ययन कराया था, जिसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश जीएसडीपी में मात्र 6.9 फ़ीसद की सीएजीआर हासिल कर सका है, जो इन चार पिछड़े राज्यों में सबसे कम है. औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश मात्र 6.9 फ़ीसद की सीएजीआर हासिल कर सका, जबकि इसी अवधि में पूरे देश में 7.4 फ़ीसद के हिसाब से विकास हुआ. प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी उत्तर प्रदेश 4.8 फ़ीसद सीएजीआर के साथ सबसे पीछे रहा. ■

सरकारी रिकॉर्ड पर मंत्रियों का जो कामकाज दिखता है, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद तक़रीबन दो साल तक तो अखिलेश सरकार के अधिकांश मंत्री सत्ता का आनंद ही लेते रहे. कुछ ही मंत्री ऐसे थे, जो सत्ता में आने के फौरन बाद या मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ही सक्रियता से काम में जुट गए, लेकिन अधिकांश मंत्री वर्ष 2012 एवं 2013 में आराम फरमाते रहे. अखिलेश यादव ने जब सत्ता पर अपनी पूरी पकड़ बना ली, तब उनके मंत्री काम पर जुटे. मंत्रियों के कामकाज के सरकारी रिकॉर्ड देखें, तो उसकी समीक्षा से कई रोचक पहलू उजागर हो रहे हैं. मसलन, जो मंत्री कहीं बयानों में नहीं रहते, जो खुद को विवादों से अलग रखते हैं, जो खुद को बिल्कुल लो-प्रोफाइल में रखते हैं, वे अपने काम में सक्रिय पाए गए हैं. उनका काम दस्तावेजी प्रमाण के साथ दिखता है. आरोप एवं शिकायतें तो मंत्रियों के साथ चलते ही हैं, इसमें कुछ शिकायतें सही भी होती हैं, लेकिन काम भी चलता रहता है. ऐसे मंत्रियों में समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद, पंचायतीराज मंत्री कैलाश, श्रम मंत्री शाहिद मंजूर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली, स्वतंत्र प्रभार वाले ग्राम्य विकास राज्य मंत्री अरविंद सिंह गोप के नाम खास तौर पर उल्लेखनीय हैं. राजा भैया जैसे मंत्री, जिन्हें तमाम किस्म के विवादों में घसीटा जाता रहा है, उन्हें देखें, तो किसी भी सक्रिय मंत्री के काम से उनकी तुलना की जा सकती है. सक्रिय मंत्रियों की सूची में शिवपाल यादव, आजम खान एवं अहमद हसन जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के नाम लिए जा सकते हैं. ये मंत्री चर्चा और सुर्ख़ियों में रहते हैं पर इनका विभागीय काम भी अपनी गति से चलता रहता है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नेशनल कांफ्रेंस की साख कैसे ख़त्म हुई पेज-03

मेवात में कौन बो रहा है नफरत के बीज पेज-04

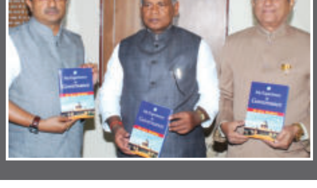

बिहार की राजनीति में जातिवाद सबसे महत्वपूर्ण है : इब्राहिमी पेज-07

साईं की महिमा पेज-12

अखिलेश सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड

कुछ में है दम, बाकी सब बेदम

पृष्ठ एक का शेष

ऐसे मंत्री भी हैं, जो अपने साथ केवल आरोप एवं शिकायतें ही लेकर चलते हैं. काम-धाम बिल्कुल नहीं करते और अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं. सामान्य सक्रिय मंत्रियों में परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी, कारागार मंत्री बलराम यादव, बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी, लघु सिंचाई मंत्री राज किशोर, लघु उद्योग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भगवत सरन गंगवार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मनोज पांडेय के नाम लिए जा सकते हैं. जिन मंत्रियों के नाम सक्रिय एवं सामान्य सक्रिय मंत्रियों की सूची में नहीं हैं, उनकी कैटेगरी के बारे में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं. इसमें रेखांकित करने वाली बात यह भी है कि इन सक्रिय एवं सामान्य सक्रिय मंत्रियों में भी कई ऐसे हैं, जिनका विभाग तक़रीबन दो साल तक विश्राम करता रहा और 2014 में अचानक सक्रिय हो गया. 2012 एवं 2013 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा उंगली पर गिने जाने लायक कैबिनेट मंत्री ही अपने काम में सक्रिय रहे. कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अखिलेश सरकार के 25 कैबिनेट मंत्रियों की टीम में यदि आठ-नौ मंत्री ही सक्रिय हैं, तो उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों के बारे में आसानी से सोचा-समझा जा सकता है. स्वतंत्र प्रभार वाले पांच मंत्रियों में से केवल एक अरविंद सिंह गोप का नाम सक्रिय मंत्रियों में शुमार है. 25 राज्य मंत्री जिन मंत्रियों के साथ संबद्ध हैं, उनकी सक्रियता का आकलन उनके बॉस मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर किया जा सकता है.

मार्च 2012 में सत्ता में आने के बाद दो साल विश्राम की मुद्रा में चले जाने वाले विभागों में अल्पसंख्यक कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण, कारागार, पर्यटन, परिवहन, होमगार्ड, वस्त्र उद्योग एवं रेशम, खादी एवं ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, प्राविधिक शिक्षा, ग्रामीण अभियंत्रण (स्वतंत्र प्रभार) और खनन आदि शामिल हैं. इनमें से कई विभाग 2014 में सक्रिय हुए, लेकिन इनमें से भी कुछ विभागों की सक्रियता औपचारिक रही. कई विभागों के 2012 एवं 2013 के काम महज घोषणात्मक रहे हैं, जिनका क्रियात्मकता से कोई लेना-देना नहीं है. समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जो विभाग अपने काम में सक्रिय हो गए, उनमें पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, समाज कल्याण, लघु सिंचाई, राजनीतिक पेंशन, पंचायती राज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बेसिक शिक्षा और श्रम अव्वल रूप से शामिल हैं. सरकार बनने के बाद एक से डेढ़ साल तक विश्राम करने के बाद सक्रिय हुए विभागों में उद्यान, दुग्ध विकास, खाद्य एवं रसद, मत्स्य और महिला कल्याण आदि उल्लेखनीय हैं. सरकार बनने के बाद से आज तक कामकाज में नगण्य साबित होने वाले विभागों में धर्मार्थ कार्य, नागरिक सुरक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पर्यटन, खादी एवं ग्रामोद्योग, खनन और प्राविधिक शिक्षा आदि शामिल किए जा सकते हैं. जिन विभागों के नाम सूची में कहीं भी नहीं हैं, उनके काम किस लायक हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं.

कामकाज में नगण्य विभागों में भी कुछ विभाग संबद्ध मंत्रियों की गतिविधियों के कारण शिकायतों-आरोपों के केंद्र में रहे. इनमें खनन विभाग अव्वल है. खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री एवं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खास गायत्री प्रसाद प्रजापति अपनी गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध हो चुके हैं. उनका बेटा अनिल प्रजापति भी उन्हीं के नक्शेक़दम पर चलकर नाम कमा रहा है. अमेठी ज़िले में तहसील की सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किए जाने के मामले में कैबिनेट मंत्री के बेटे का नाम आया. मंत्री के बेटे पर बैनामे के कागजात में हेराफेरी, स्टांप चोरी के साथ ही तहसील की खाली पड़ी ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा करके निर्माण करने का आरोप है. यह मामला इतना गंभीर है कि स्थानीय अधिवक्ता संघ भी इस पर आधिकारिक नाराज़गी व्यक्त कर चुका है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. मंत्री के बेटे पर ज़मीन कब्जाने का यह कोई पहला आरोप नहीं था, इसके पहले अमेठी की एक विधवा की ज़मीन पर कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति द्वारा कब्ज़ा किए जाने के ख़िलाफ़ पीड़ित विधवा महिला अपने परिवार के साथ लखनऊ में धरने पर बैठ चुकी है.

अमेठी तहसील के पास टाउन एरिया में रहने वाले प्रदीप श्रीवास्तव से कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति ने लाइफ क्योर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर नामक एनजीओ के नाम पर ज़मीन खरीदी. इस एनजीओ का डायरेक्टर खुद अनिल प्रजापति है. खरीदी गई ज़मीन के बगल में खाली पड़ी अमेठी तहसील की ज़मीन पर कब्जा करके अनिल प्रजापति ने निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया. तहसील के वकीलों ने इसकी शिकायत अमेठी के उप-ज़िलाधिकारी आरडी राम से की, लेकिन मामला कैबिनेट मंत्री के बेटे से जुड़ा होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई. वकीलों ने इसके ख़िलाफ़ कार्य बहिष्कार कर दिया और सुल्तानपुर ज़िला न्यायालय पहुंच गए. अदालत ने उस भूखंड पर निर्माण कार्य फौरन रोकने का आदेश दे दिया.

प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की आर्थिक ताकत देखते-देखते इतनी बढ़ गई कि उनका ऐश्वर्य और आधिपत्य दोनों ही सड़क पर दिखने लगा है. अमेठी में मंत्री ने एक सिनेमा हॉल ही खरीद लिया. विमल पिक्चर हॉल खरीदने के बाद अब उन्हें उस परिसर के इर्द-गिर्द की सारी इमारतें एवं ज़मीनें चुभने लगीं. मंत्री ने विमल सिनेमा हॉल के बगल में विधवा शिवदेवी गुप्ता की ज़मीन पर भी जबरन कब्जा जमा लिया. प्रशासन ने बाकायदा बुल्डोजर लगाकर ज़मीन की चाहरदीवारी ढहा दी. दीवार गिराए जाते वक्त मंत्री का कथित पीआरओ भी वहीं मौजूद था. इसकी सूचना अमेठी के ज़िलाधिकारी और उप-ज़िलाधिकारी (सदर) को दी गई. ज़िलाधिकारी ने एसओ को कब्जा हटवाने का आदेश दिया, लेकिन प्रशासन मंत्री का कब्जा नहीं हटवा पाया. क़ानून हाथ में रखने वाले मंत्री के आगे पूरा ज़िला प्रशासन बेचारा और नाकाम साबित हुआ.

दूसरी तरफ़ खनन विभाग के कारनामों की अभी भी प्रदेश में चर्चा सर्वाधिक है. जानकारों का कहना है कि सबसे अधिक पैसा खनन से ही आता है, जिससे मालामाल होने वाले लोगों की कतार काफी लंबी है. अवैध खनन का पूरे उत्तर प्रदेश में बोलबाला है. मौरंग खनन में पट्टा कहीं का है, रॉयल्टी चल रही है कहीं और की. प्रदेश की वन भूमि में भी अवैध खनन का धंधा बेतहाशा चल रहा है. एक-एक बैरियर से कम से कम 40 लाख रुपये की वसूली होती है. नेता-नौकरशाह-माफिया की तिकड़ी सिंडिकेट की शक्ल में यह धंधा चला रही है. जालौन एवं उरई जैसे इलाकों में लाल सोने के नाम से मशहूर मौरंग खनन का अवैध कारोबार सिंडिकेट द्वारा चलाया जा रहा है. एक खदान के मौरंग प्रपत्र एमएम-11 दूसरी अवैध खदानों पर भी बखूबी चल रहे हैं. फिर भी खनिज विभाग के अफसर इसकी चेकिंग नहीं करते. स्पष्ट है कि उन्हें इसकी एवज में हर माह मोटी रकम मिल रही है.

अवैध मौरंग खनन के काले कारोबार में सत्ता शीर्ष से जुड़े लोगों द्वारा बेखौफ होकर खनन किया जा रहा है. वैसे तो जनपद जालौन में उरई एवं कालपी तहसील में ही सर्वाधिक मौरंग खदानें हैं, जिनमें उरई तहसील में सिमिरिया, खरका, मुहाना हैदलपुर, ददरी, अमरौड़ जैसी प्रमुख खदानें चल रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि ददरी एवं अमरौड़ के पट्टाधारकों द्वारा दूसरी ऐसी खदानों के लिए अवैध रूप से एमएम-11 दे दिया गया, जहां किसी कारण से खनन पर रोक लगी थी या पट्टा था ही नहीं. जब इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ, तो प्रशासन ददरी की मौरंग खदान के पट्टाधारक पर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात-बहादुरी करने लगा. सत्ता शीर्ष के एक मंत्री के मुंहबोले नेता ने खनिज अधिकारी को अपना फरमान भी जारी कर दिया कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. नेता के फरमान पर खनिज अधिकारियों की बोलती बंद हो गई और उन्होंने चुप बैठने में ही भलाई समझी. इसी तरह कालपी तहसील में हिमनपुरा, समसी, मोहरदेवी, भेंड़ी खुर्द जैसी खदानें चल रही हैं. खास बात यह है कि मोहरदेवी एवं समसी मौरंग खदान का न तो पट्टा स्वीकृत है, न ही निजी भूमि के रूप में ही खनन के लिए स्वीकृति है, फिर भी सत्ता शीर्ष के नेताओं और खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से यहां दूसरे पट्टाधारकों के एमएम-11 का प्रयोग कर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है. खनन के गोरखधंधे से आने-वाले अनाप-शनाप पैसे को बटोरने के लिए सत्ता शीर्ष ने मंत्री के साथ-साथ एक और खास व्यक्ति को लगा रखा है.

सीसीटीवी कैमरे से घबराते क्यों हैं मंत्री

अखिलेश सरकार ने मंत्रियों के आवास पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फ़ैसला किया, तो मंत्रियों में घबराहट फैल गई. कई मंत्रियों ने अपनी नाखुशी सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर दी. मुख्यमंत्री तो कैमरे लगवाने पर दृढ़ थे, लेकिन आख़िरकार कैमरे लगवाने का उत्साह ढीला पड़ गया. उल्लेखनीय है कि जबसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तबसे विधायकों एवं मंत्रियों के बारे में तमाम शिकायतें सरकार से लेकर पार्टी तक पहुंच रही हैं. इस पर पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह अपनी नाराज़गी कई बार जाहिर कर चुके हैं. इसे देखते हुए अखिलेश यादव ने मंत्रियों के घरों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय किया. मंत्री इसे निजी जीवन में दखल बता रहे हैं. ■

मंत्रियों के कारनामों के ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं. प्रदेश के कपड़ा एवं रेशम मंत्री शिवकुमार बेरिया की अपनी ही सरकार व प्रशासन के ख़िलाफ़ बेलगाम बयानबाजी और फूहड़ हरकतें अखिलेश सरकार को शर्मसार चुकी हैं. सीएमओ का अपहरण कराने वाले विधायक विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल करने की घटना भी अखिलेश सरकार की छवि में चार चांद लगाने वाली साबित हुई. सीएमओ के अपहरण के मामले में पंडित सिंह को अक्टूबर 2012 में मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अखिलेश ने उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में वापस ले लिया. याद करते चलें कि पंडित सिंह ने एनआरएचएम भर्ती में अपने लोगों की नियुक्ति का दबाव बनाने के लिए तत्कालीन सीएमओ एसपी सिंह का अपहरण कर लिया था. पंडित सिंह की दबंगई का हाल यह है कि अपहरण मामले में न केवल संबंधित सीएमओ, बल्कि तत्कालीन डीएम अभय, एसपी कृपा शंकर, सीडीओ अरविंद सिंह तक को भूमिगत हो जाना पड़ा. बाद में शासन ने 13 अक्टूबर को इन सभी अधिकारियों का वहां से तबादला कर दिया. मामले की जांच लखनऊ के मंडलायुक्त को सौंपी गई, लेकिन तत्कालीन मंडलायुक्त संजीव मित्तल ने आरोपी पंडित सिंह को ही जांच की परिधि से बाहर रख दिया. पिछली सपा सरकार के दौरान हुए 35 हज़ार करोड़ रुपये के खाद्यान्न घोटाले में भी पंडित सिंह का नाम उजागर हुआ था.

मस्ती और उत्सव से विकास को सद्गति

काम-धाम छोड़कर मंत्रियों के उत्सव मनाने, मस्ती करने और विदेश घूमने के मामले अख़बारों में आ चुके हैं. मस्ती और फिजूलखर्ची का आलम यह है कि स्टडी टूर के नाम पर विदेश घूमने गए मंत्रियों ने एमस्टरडम के सात सितारा होटल में तीन लाख रुपये एक रात के किराए पर कमरे लिए थे. अखिलेश सरकार के 17 मंत्री एवं विधायक इंटरनेशनल स्टडी टूर के नाम पर विदेश तफरीह के लिए गए थे. 20 दिनों के स्टडी टूर में ब्रिटेन, यूएई, नीदरलैंड, ग्रीस एवं तुर्की के सैर-सपाटे की योजना थी. अखिलेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मंडल में राजा भैया, अंबिका चौधरी, शिवकांत ओझा एवं शिवकुमार बेरिया समेत कई मंत्री और विधायक शामिल थे. आलीशान सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपये खर्च कर मस्ती करने में अखिलेश सरकार भी देश भर में नाम कमा चुकी है. ■

अखिलेश सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों की नैतिक-प्रतिबद्धता जांचने के लिए एक मीडिया संस्थान ने सत्ता से जुड़े क़रीब एक दर्जन लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया था और सत्ता के गलियारे में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की छोटी-सी कोशिश की थी. पैसा लेकर काम कराने का वादा करने वाले लोगों में राज्य के श्रम एवं रोज़गार विभाग में एडवाइजर और राज्य मंत्री की हैसियत में रहे हाजी मोहम्मद अब्बास, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के चेयरमैन एवं राज्य मंत्री के दर्जे में रहे श्रीप्रकाश राय, राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त आवश्यक वस्तु निगम के चेयरमैन रहे हाजी इकराम कुरैशी, सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री शाकिर अली, पूर्व राज्यमंत्री आनंद सेन यादव, सपा विधायक चंद्रा रावत, सपा विधायक शारदा प्रताप शुक्ला, सपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य राम प्रकाश यादव, सपा के युवा मोर्चा के सचिव सतीश यादव, सपा के संभल ज़िला सचिव उरमान सिंह यादव, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित अग्रवाल उर्फ अमित जानी और लखनऊ के पूर्व पार्षद अयाज अहमद आदि के नाम शामिल हैं. इन नेताओं ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग में वीडीओ की भर्ती के लिए लोगों से आठ से तेरह लाख रुपये तक की रिश्वत मांगी. कई जगह रिश्वत का आधा हिस्सा टोकन मनी के रूप में पहले मांगा गया. यह भी दावा किया गया कि पंचायतीराज विभाग में भी नियुक्तियां इसी तर्ज पर हो रही हैं. इनमें से कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि पुलिस विभाग में भी नियुक्तियां इसी तर्ज पर तय होने लगी हैं. कई लोगों ने यह दावा किया कि उनकी सपा के वरिष्ठ नेताओं एवं मंत्रियों से साठगांठ है.

दो बार मंत्री रह चुके सपा विधायक शाकिर अली को छोड़कर इन सभी नेताओं ने पैसा लेकर भर्ती कराने का भरोसा दिलाया. सिर्फ़ शाकिर अली अकेले ऐसे नेता निकले, जिन्होंने पैसा लेकर काम करने से मना कर दिया. विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों की फौज से पहले 35 और फिर दूसरी खेप में 82 मंत्रियों को निकाल कर सुर्खियां तो बटोर लीं, लेकिन असलियत यह है कि बर्खास्त मंत्रियों की बैकडोर से वापसी के इंतजाम भी हो रहे हैं. कई परोक्ष रूप से ताकतवर हो भी चुके हैं. प्रदेश में मंत्री का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पुलिस अधिकारी का तबादला कर दिए जाने जैसे मामले भी सरकार की प्राथमिकताएं उजागर कर चुके हैं. आपको याद होगा कि चीनी निगम के अध्यक्ष रहे केसी पांडेय के भ्रष्टाचार और उनके द्वारा पशु तस्करी को संरक्षण दिए जाने का प्रमाण पेश करने वाले गोंडा के पुलिस अधीक्षक नवनीत राणा का तबादला कर दिया गया था. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्तर के दो दर्जन मंत्रियों पर गंभीर अपराध के मामले भी विचाराधीन हैं और इन्हीं छवियों के आधार पर समाजवादी पार्टी को 2017 के चुनाव में उतरना है.

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस दौरान अपने द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों का बखान मौक़े-बेमौक़े करते रहते हैं. और, काम हो भी रहे हैं. लेकिन, सरकार और समाजवादी पार्टी के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि राज्य मंत्रिमंडल में कुछ गिने-चुने नामों को छोड़कर शेष मंत्री निहायत नाकारा साबित हुए हैं. समाजवादी पार्टी एक तरफ़ राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव की ओर देख रही है, वहीं दूसरी तरफ़ अपने इर्द-गिर्द मौजूद और सत्ता पर काबिज चेहरे भी, जिनके भरोसे उसे जनता की अदालत में जाना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 39
दिल्ली, 01 दिसंबर-07 दिसंबर 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

> राज्य में लागू अफ्सपा के तहत यहां सेना एवं सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसे ख़त्म करने के मामले पर उमर के अनावश्यक बयानों पर भी उन्हें कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी. अपने कार्यकाल के दौरान उमर इस सच्चाई के बावजूद कि केंद्र अफ्सपा को ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है, बार-बार इसे ख़त्म कराने का वादा करते रहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से नाकाम हो गए. 21 अक्टूबर, 2011 को उन्होंने एक बेहद ग़ैर-जिम्मेदाराना बयान दिया कि वह अफ्सपा को केवल दो दिनों के अंदर हटाएंगे. कुछ समय बाद उन्होंने फिर बयान दिया कि अफ्सपा दरबार मूव (अक्टूबर में सरकार का जम्मू स्थानांतरित हो जाना) के बाद अवश्य हटेगा.

जम्मू-कश्मीर

नेशनल कांफ्रेंस की साख कैसे ख़त्म हुई

मोहम्मद हारून रेशी

जिस तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने जनता के बीच अपनी साख खोई और उसकी जगह भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी, ठीक उसी तरह जम्मू-कश्मीर की सबसे पुरानी सियासी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से गुम होती नज़र आ रही है. नेशनल कांफ्रेंस, जो कई दशक तक जम्मू-कश्मीर की सत्ता पर काबिज़ रही है, अब हर बीते दिन के साथ अपना महत्व और अस्तित्व खोती नज़र आ रही है. बीते दिनों नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉ. महबूब बेग पार्टी से किनारा कर गए. पिछले कुछ महीनों के दौरान कई वरिष्ठ नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता नेशनल कांफ्रेंस छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) या अन्य दलों का दामन थाम चुके हैं. महबूब बेग से दक्षिणी कश्मीर की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन अब अचानक उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी और कहा कि वह विधानसभा चुनाव में मुफ्ती मोहम्मद सईद के समर्थन में मुहिम चलाएंगे. महबूब के जाने से नेशनल कांफ्रेंस को दोहरा झटका लगा है. पहला यह कि पार्टी अब उनकी सीट से कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती और दूसरा यह कि महबूब का वोट बैंक मुफ्ती के खाते में चला गया.

महबूब बेग ने पार्टी छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि नेशनल कांफ्रेंस की साख इस हद तक खराब हो चुकी है कि उन्हें लोगों के पास जाकर वोट मांगने में शर्म आ रही थी. बेग के पिता स्वर्गीय मिर्ज़ा अफज़ल बेग नेशनल कांफ्रेंस के संस्थापक नेताओं में से एक थे और नेशनल कांफ्रेंस की स्थापना करने वाले स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के क़रीबी साथियों में शुमार किए जाते थे. ज़ाहिर है, इन परिस्थितियों में महबूब बेग का नेशनल कांफ्रेंस छोड़ना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है. जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस की लोकप्रियता इस हद तक तबाह हो चुकी है कि इस वर्ष हुए संसदीय चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. एक जमाने में लोकप्रिय रहे नेशनल कांफ्रेंस के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्लाह को भी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा. पिछले छह दशकों के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब नेशनल कांफ्रेंस संसदीय चुनाव में पूरी तरह साफ़ हो गई. अब जबकि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो नेशनल कांफ्रेंस निराश-हताश नज़र आ रही है. न तो राज्य के अख़बारों में नेशनल कांफ्रेंस के चुनावी विज्ञापन छप रहे हैं और न पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी रैलियों में नज़र आ रहे हैं.

विश्लेषकों का कहना है कि नेशनल कांफ्रेंस विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत हार से पहले ही हताश नज़र आ रही है. विश्लेषक रियाज़ मसरूर कहते हैं कि उमर अब्दुल्लाह अध्यक्ष के रूप में पार्टी में जारी गतिरोध ख़त्म करने में विफल साबित हुए. हालांकि, उनके पास मुख्यमंत्री का पद था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वह पिछले छह वर्षों में पार्टी की जड़ें मज़बूत करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे. लेकिन, हुआ यह कि उनके दौर में जम्मू-कश्मीर में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि लोगों को आंतरिक सुरक्षा के नाम पर अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ा. इस वजह से लोग मुफ्ती की तारीफ़ करने लगे, क्योंकि मुफ्ती ने अपने कार्यकाल में जनता को पुलिस टास्क फोर्सेज एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए कई क़दम उठाए थे. नेशनल कांफ्रेंस के अंदर एक आम राय यह भी है कि पार्टी को राजनीतिक दृष्टि से अनुभवहीन उमर अब्दुल्लाह ने बहुत नुक़सान पहुंचाया. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उमर ने 2009 में मुख्यमंत्री का पद संभालते ही नासिर असलम वानी, तनवीर सादिक़ एवं जुनैद मट्टू जैसे नए और राजनीति में अनुभवहीन लोगों को अपना क़रीबी साथी-हमराज़ बना लिया. उमर ने उन्हें न सिर्फ़ महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर बैठाया, बल्कि पार्टी के महत्वपूर्ण कार्य भी सौंप दिए.

उमर के इसी व्यवहार के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिन्होंने अपनी सारी उम्र पार्टी को मज़बूत बनाने में लगा दी, का मोहभंग हो गया. वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के मामलों में आयु एवं अनुभव के लिहाज से खुद से छोटे लोगों के इमले (डिक्टेशन) सुनने पड़ते हैं. यही वजह है कि उनकी भावना आहत हुई और उनमें पार्टी के प्रति दिलचस्पी कम होती गई. नतीजा सामने है. आज वरिष्ठ नेता चुनावी सभा करने के लिए बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं. पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि 1989 में जब राज्य में मिलिटेंसी शुरू हुई, तो उसके शुरुआती कुछ वर्षों में ही नेशनल कांफ्रेंस के हज़ारों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई. खुद अब्दुल्लाह परिवार के सारे सदस्य कश्मीर छोड़कर विदेश चले गए थे. उन मारे जाने वाले ग़रीब एवं आम कार्यकर्ताओं का अब्दुल्लाह परिवार की नज़रों में कितना महत्व है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि आज पार्टी के पास उनके नामों की कोई सूची तक नहीं है. होना तो यह चाहिए था कि 1996 में सत्ता में आने या फिर 2009 में सरकार बनाने के बाद नेशनल कांफ्रेंस उन कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद करती, उनके लिए शोक सभाएं करती और उनके बच्चों के रोज़गार की व्यवस्था करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. नतीजतन, नेशनल कांफ्रेंस, जो पूरे राज्य में एकमात्र ग्रास रूट लेवल पार्टी थी, की साख आज ख़त्म हो गई. कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए बलिदान का सिलसिला बंद कर दिया. यही कारण है कि जो पार्टी कभी विधानसभा में दो तिहाई से अधिक बहुमत रखती थी, वह केवल 28 सीटों पर सिमट गई है और अब उसकी सीटें और घटने की संभावना है.

> *पिछले छह वर्षों से नेशनल कांफ्रेंस के सांगठनिक ढांचे और राज्य सरकार की बागडोर पूरी तरह उमर अब्दुल्लाह के हाथों में है. इस अवधि में उमर पर बार-बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नज़रअंदाज़ करने और बचकाना हरकतों के आरोप लगते रहे. उमर अब्दुल्लाह के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद जब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दल पीडीपी के एक नेता ने उन पर पुराने सेक्स स्कैंडल में आरोप लगाया, तो उमर ने तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर उसकी घोषणा भी कर दी.*

पिछले छह वर्षों से नेशनल कांफ्रेंस के सांगठनिक ढांचे और राज्य सरकार की बागडोर पूरी तरह उमर अब्दुल्लाह के हाथों में है. इस अवधि में उमर पर बार-बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नज़रअंदाज़ करने और बचकाना हरकतों के आरोप लगते रहे. उमर अब्दुल्लाह के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद जब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दल पीडीपी के एक नेता ने उन पर पुराने सेक्स स्कैंडल में आरोप लगाया, तो उमर ने तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर उसकी घोषणा भी कर दी. बाद में पिता फ़ारूक़ अब्दुल्लाह एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें समझा-बुझाकर फ़ैसला वापस लेने पर राज़ी किया. हालांकि, 2005 में सामने आए उक्त सेक्स स्कैंडल की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने तुरंत बयान जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उस स्कैंडल के आरोपियों में उमर का नाम शामिल नहीं है. समीक्षकों का कहना है कि अगर उनकी जगह कोई अनुभवी नेता होता, तो वह विपक्षी नेता पर कोई जवाबी आरोप लगाकर या खामोश बैठकर यह बात वहीं पर ख़त्म कर देता, लेकिन उमर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार छोड़ने की घोषणा कर दी और उस आरोप को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अख़बारों की सुर्खियां बना दिया.

उमर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर यह भी आरोप लगा था कि वह महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों और पार्टी की सभाओं में अपने मोबाइल फोन पर खेलते रहते हैं. तब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ली गई उनकी एक तस्वीर कई अख़बारों में प्रकाशित हुई थी, जिसमें वह अपने मोबाइल फोन पर ताश (गेम) खेलते हुए देखे गए. उनकी सरकार बनने के कुछ महीने बाद जब दक्षिण कश्मीर के शोपियां में दो महिलाओं के साथ कथित रूप से बलात्कार के बाद उनकी हत्या की गई, तो उमर के उस बयान की कड़ी आलोचना हुई थी कि उक्त महिलाओं की मौत नाले में डूब जाने से हुई. हालांकि, बाद में उमर ने अपना बयान वापस ले लिया था. सीबीआई ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त महिलाओं की मौत का कारण डूबना बताया. इसी तरह 2010 में घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में 120 लोगों, जिनमें अधिकतर मासूम बच्चे शामिल थे, की पुलिस और सुरक्षाबलों के हाथों मौत पर भी उमर अब्दुल्लाह को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा और नेशनल कांफ्रेंस की लोकप्रियता को नुक़सान हुआ.

हाल में जब घाटी के एक पूर्व पुलिस अधिकारी, जिस पर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों के दौरान कई लोगों को मारने का आरोप है, ने पीडीपी में शामिल होने की कोशिश की थी, तो पीडीपी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. पीडीपी ने फौरन उक्त अधिकारी के पार्टी में शामिल होने की ख़बर का खंडन किया. इसके बाद उमर ने बेहद बचकाना बयान दिया कि उक्त पुलिस अधिकारी 2010 में हुईं नागरिकों की हत्याओं में शामिल था. उमर के बयान पर राजनीतिक समीक्षकों एवं आलोचकों ने सवाल उठाया कि जब उक्त पुलिस अधिकारी लोगों को मार रहा था, तो उमर मुख्यमंत्री होते हुए भी खामोश क्यों बैठे थे? 2010 में जनता द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरी घाटी में पांच हज़ार युवाओं के ख़िलाफ़ शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में मामले दर्ज किए गए. विरोध प्रदर्शन ख़त्म होने पर उमर ने घोषणा की कि उक्त सभी मामले वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका. इस वजह से भी राज्य की जनता उमर अब्दुल्लाह और नेशनल कांफ्रेंस से नाराज़ है.

राज्य में लागू अफ्सपा के तहत यहां सेना एवं सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसे ख़त्म करने के मामले पर उमर के अनावश्यक बयानों पर भी उन्हें कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी. अपने कार्यकाल के दौरान उमर इस सच्चाई के बावजूद कि केंद्र अफ्सपा को ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है, बार-बार इसे ख़त्म कराने का वादा करते रहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से नाकाम हो गए. 21 अक्टूबर, 2011 को उन्होंने एक बेहद ग़ैर-जिम्मेदाराना बयान दिया कि वह अफ्सपा को केवल दो दिनों के अंदर हटाएंगे. कुछ समय बाद उन्होंने फिर बयान दिया कि अफ्सपा दरबार मूव (अक्टूबर में सरकार का जम्मू स्थानांतरित हो जाना) के बाद अवश्य हटेगा. अफ्सपा न हटाया जाना था और न हटा, लेकिन ऐसे बयानों से उमर की विश्वसनीयता प्रभावित हुई. आलोचकों का कहना है कि उमर को ऐसा वादा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, जिसे पूरा करना उनके वश में नहीं है. राज्य में लागू अफ्सपा हटाने या न हटाने का निर्णय भारत सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं. इसलिए उमर को एक हद से आगे बढ़कर बयानबाज़ी नहीं करनी चाहिए थी. हाल में उमर ने कहा कि वह अफ्सपा ख़त्म कराने में इसलिए नाकाम हुए, क्योंकि सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया. इस बयान पर भी विरोधियों ने यह कहकर आलोचना की कि अब सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो जाने पर ही उमर को यह ख़ुलासा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उनकी सहयोगी पार्टी ने सहयोग नहीं किया, जबकि पिछले छह वर्षों के दौरान दोनों पार्टियां एक साथ सरकार चला रही हैं.

उमर की वजह से नेशनल कांफ्रेंस को सबसे अधिक नुक़सान उस समय उठाना पड़ा, जब 30 सितंबर, 2011 को पार्टी के वरिष्ठ सदस्य सैयद यूसुफ की संदेहजनक स्थितियों में मौत हो गई. दरअसल, सैयद यूसुफ पर नेशनल कांफ्रेंस के दो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उसने उमर की सरकार में मंत्री बनाने के लिए उनसे पैसे लिए थे. उमर ने आरोप की जांच के लिए सैयद यूसुफ को अपने घर बुला लिया. वहां अचानक सैयद यूसुफ की हालत बिगड़ गई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. सैयद यूसुफ के परिवार का कहना है कि उसे उमर के घर में शारीरिक यातनाएं दी गई थीं, जिससे उसकी मौत हो गई. बाद में इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएस भेदी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसने जांच के बाद उमर अब्दुल्लाह को क्लीन चिट दे दी. इसके बावजूद पार्टी में सैयद यूसुफ की मौत को लेकर गहरा आक्रोश है और कार्यकर्ताओं के बीच अफरातफरी का माहौल भी. पिछले दिनों आई बाढ़ में श्रीनगर, ख़ासकर औद्योगिक केंद्र लाल चौक को बचाने में नाकामी के कारण भी जनता उमर सरकार से नाराज़ है. सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की पुनर्वास प्रक्रिया में ढीलेपन का भी आरोप है. घाटी में एक आम राय यह है कि उमर की अनुभवहीनता के चलते न केवल राज्य सरकार बदनाम हुई, बल्कि नेशनल कांफ्रेंस की साख भी प्रभावित हुई. बहरहाल, जो होना था, हो चुका है, लेकिन समीक्षकों को यकीन है कि नेशनल कांफ्रेंस की मौजूदा बदहाली में उसके नेतृत्व के लिए काम करने की संभावना पैदा हो गई है. अगर नेशनल कांफ्रेंस विधानसभा चुनाव हार भी जाती है, तो पार्टी को पुन: संगठित करने का एक मौक़ा उनके हाथ आएगा. नेशनल कांफ्रेंस आने वाले छह वर्षों तक सरकार के झंझट से दूर रहकर स्वयं को मज़बूत बना सकती है. यही सुझाव समीक्षक कांग्रेस को भी दे रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सबसे बड़ी बात है, पार्टी के अघोषित सुप्रीमो नीतीश कुमार की खामोशी. नीतीश का मीडिया से कभी कटु रिश्ता नहीं रहा. मीडिया के लिए वह सदैव अपनी शैली में उपलब्ध रहे. हालांकि, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद इसमें थोड़ा खिंचाव आया, लेकिन राजद के साथ गठबंधन या उपचुनाव के दौरान और उसके बाद भी वह मीडिया को एक सीमा में उपलब्ध रहे. लेकिन, मांझी में सत्ता-बोध जगने और उसकी खुली अभिव्यक्ति के बाद से मीडिया से नीतीश अघोषित तौर पर परहेज करने लगे.

मेवात में कौन बो रहा है नफरत के बीज

शशि शेखर

हरियाणा और राजस्थान के एक खास क्षेत्र को मेवात का इलाका कहा जाता है, जो गुड़गांव के नज़दीक नूह से लेकर राजस्थान के अलवर तक फैला हुआ है. यह मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां के मुसलमानों को मेव मुसलमान कहते हैं. मेव मुसलमानों का एक लंबा इतिहास रहा है. बाबर की सेना से लोहा लेने वाले इस समुदाय को जब आज़ादी के वक्त, बंटवारे के बाद जबरन पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही थी, तब खुद महात्मा गांधी इस इलाके में आए और उन्होंने कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं और कोई भी इन्हें यहां से नहीं हटा सकता. इस क्षेत्र के मेव मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति भी देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले अल्पसंख्यकों जैसी ही है. अशिक्षा और ग़रीबी यहां की बड़ी समस्या है. लेकिन, इससे भी बढ़कर एक और समस्या है, यहां के सामाजिक ताने-बाने को समय-समय पर कमजोर और शांति-सद्भाव को भंग करने की कोशिश करना. पिछले कुछ समय से यह इलाका सांप्रदायिक तनाव की जद में आता रहा है.

2011 में गोपालगढ़ की हिंसा, जिसमें पुलिस ने मस्जिद में घुसकर फायरिंग की थी, के दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी. इस साल भी रमजान के दौरान अलवर ज़िले के सिरमौली गांव में राजस्थान की स्पेशल पुलिस कोबरा ने घरों में घुसकर मुस्लिम महिलाओं एवं बच्चों को पीटा. कारण यह बताया गया कि इलाके के लोग पत्थर की चोरी कर रहे थे. हालांकि, स्थानीय निवासियों के मुताबिक, इस इलाके में बड़े लोगों के इशारे पर पत्थरों का अवैध खनन होता है. गांव के ग़रीब लोग अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कभी-कभी यहां से पत्थर ले जाते हैं. ऐसी ही एक घटना में गांव के लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद सारे पुरुष तो भाग निकले, लेकिन उसका बदला पुलिस ने महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर लिया.

इस मामले को जद (यू) सांसद अली अनवर अंसारी ने संसद में उठाया और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्लाह एवं गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने का अनुरोध किया है. बीते 10 सितंबर को लिखे गए इस पत्र का अभी तक गृह मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की ओर से सिर्फ़ इतना ही जवाब आया है कि मामले को देखा जा रहा है. दो महीने से भी अधिक समय बीतने के बावजूद न तो कोई जांच हुई है और न कोई कार्रवाई. इस घटना के अलावा, पलवल के हथीन ब्लॉक में भी लगातार माहौल को तनावग्रस्त बनाने की कोशिश की जा रही है. यहां की सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को लेकर स्थानीय नेता विवाद पैदा करने की न सिर्फ़ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बीते 11 नवंबर को तो बाकायदा मस्जिद पर हमले हुए, दुकानों में आग लगाने से लेकर लूटपाट तक की घटनाएं हुईं.

इस बारे में हथीन निवासी जमालुद्दीन बताते हैं कि मस्जिद के सामने एक टीनशेड था, जिसे हटाकर पक्का निर्माण कराया जा रहा था. इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, तो स्थानीय पंचायत की बैठक के बाद पक्का निर्माण बंद कर दिया गया. जितना निर्माण हुआ था, उसे भी तोड़ने की बात मान ली गई और बाकायदा उसे तोड़ा भी जाने लगा, लेकिन इसी बीच कुछ शरारती एवं उपद्रवी तत्वों ने हिंसा शुरू कर दी. 11 नवंबर की रात को मारपीट, आगजनी एवं लूटपाट की कई घटनाएं हुईं. स्थानीय निवासी दबे स्वरों में बताते हैं कि इस मामले को हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय से ही गर्माने की कोशिश की जा रही थी. इस मामले में कुछ उपद्रवी युवकों एवं संगठनों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसकी जांच चल रही है, लेकिन इस सबके बीच इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द्र ज़रूर बिगड़ा है.

मेवात के इन मुद्दों को लेकर 15 नवंबर को दिल्ली में जद (यू) सांसद अली अनवर अंसारी ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके सारी बातें मीडिया के सामने रखीं. इसमें मेवात के कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिनमें रमजान चौधरी, डॉ. अब्दुल बहाव, याहिया सैफी, डॉ. मुंशी खान, अकबर कासमी, खान बाबा एवं सुभान खान आदि प्रमुख थे. अली अनवर अंसारी ने स्पष्ट कहा कि मेव मुसलमान एक देशभक्त कौम है और यह किसी से डरने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ संगठन एवं लोग इस इलाके में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे और लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेंगे. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

“मेव मुसलमान एक देशभक्त कौम है और यह किसी से डरने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ संगठन एवं लोग इस इलाके में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे और लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेंगे.

-अली अनवर अंसारी, सांसद, जद (यू).”

मांझी की घेराबंदी

सुकांत

बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने ही विधायकों के निशाने पर हैं. जनता दल (यू) के विधायकों-नेताओं का एक बड़ा तबका उन्हें अब किसी भी तरह बख्शने के मूड में नहीं है. उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तक उनसे दूरी बरत रहे हैं और इस्तीफ़ा मांग रहे हैं. पार्टी के अघोषित सुप्रीमो नीतीश कुमार के प्रति हद से अधिक निष्ठावान विधायक एवं नेता मांझी के बयानों को लेकर उन्हें सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से भी अधिक सख्त रुख के साथ अखाड़े में उतर आए हैं. बाहुबली विधायक अनंत सिंह एवं सुनील पांडेय सहित भाजपा से जद (यू) में आए संजय झा आदि ने मांझी के ख़िलाफ़ जैसे बयान दिए हैं, वैसे तो भाजपा ने भी नहीं दिए. नीतीश राज में आतंक के पर्याय रहे अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री मांझी को पागल करार दिया और उन्हें पागलखाने भेजकर इलाज कराने की सलाह दे डाली. दूसरे बाहुबली विधायक सुनील पांडेय की राय इससे बहुत भिन्न नहीं रही. जबकि संजय झा ने मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ अनुशासनिक कार्रवाई की मांग की है. इनके अलावा पार्टी के कुछ अन्य नेताओं-विधायकों ने भी राजनीतिक शब्दावली के साथ परोक्ष तौर पर मांझी के वक्तव्यों पर विस्मय जताया है. कुछ लोगों ने (जिनमें अधिकांश 2005 के पहले या उसके कई साल बाद तक दूसरे दलों के बयानबाज़ थे) पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी राजनीति और शैली में अपनी अगाध निष्ठा का बखान कर परोक्ष तौर पर मांझी को आगाह किया है. उधर मांझी इन पर कतई ध्यान देने को तैयार नहीं दिखते. वह अपनी गति से अपना काम कर रहे हैं.

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण है, जद (यू) का आधिकारिक रवैया. वस्तुत: पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं है कि वह मुख्यमंत्री की निंदा करे या उनका बचाव. यदि कुछ दिखता है, तो वह है असलियत छिपाने का विफल प्रयास. जब-जब ऐसी नौबत आती है, नीरज कुमार जैसे प्रखर प्रवक्ता सामने आते हैं और पार्टी को अलग कर लेने की बात कहकर मौन हो जाते हैं. हालांकि, मांझी के आदिवासियों को भारत का मूल वासी बताने वाले बयान पर उन्होंने कुछ अधिक बात की और उसमें भी मांझी का विरोध अधिक था. पार्टी का स्टैंड गायब था. कई अवसरों पर अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने, बहुत घेरे जाने के बाद, मांझी के चर्चित बयानों को उनकी निजी राय बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने एक-दो अवसरों पर मांझी के बयानों पर अपनी असहमति जाहिर की. अपने पिछले पटना प्रवास के दौरान उन्होंने मांझी से बंद कमरे में बातचीत की और उन्हें अपने बयानों में संयम बरतने की नसीहत दी. ऐसी नसीहत उन्होंने पार्टी के दीगर नेताओं, मंत्रियों एवं विधायकों दी या नहीं, यह किसी को पता नहीं है. हां, उनकी इस पहल के बाद मांझी बनाम जद (यू) का विवाद ज़्यादा असभ्य तरीके से सामने आया और मांझी को पागलखाने भेजने या उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की मांग की गई.

सबसे बड़ी बात है, पार्टी के अघोषित सुप्रीमो नीतीश कुमार की खामोशी. नीतीश का मीडिया से कभी कटु रिश्ता नहीं रहा. मीडिया के लिए वह सदैव अपनी शैली में उपलब्ध रहे. हालांकि, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद इसमें थोड़ा खिंचाव आया, लेकिन राजद के साथ गठबंधन या उपचुनाव के दौरान और उसके बाद भी वह मीडिया को एक सीमा में उपलब्ध रहे. लेकिन, मांझी में सत्ता-बोध जगने और उसकी खुली अभिव्यक्ति के बाद से मीडिया से नीतीश अघोषित तौर पर परहेज करने लगे. दशहरा हादसे के बाद तो मीडिया से वह मिले ही नहीं. मिलने के मीडिया के प्रयास वह नाकाम करते रहे. नीतीश ने इन दिनों एक नीति तय कर ली है और उस पर वह बड़ी निष्ठा के साथ अमल कर रहे हैं कि मीडिया से बात नहीं करनी. नीतीश अब फेसबुक एवं ट्वीटर के ज़रिये अपनी बात कहते हैं और वह भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में. बिहार की समस्याओं, जनता की खुशी-नाखुशी, सरकार के कामकाज, पार्टी की रीति-नीति आदि के बारे में उनकी किसी राय के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. इसी महीने के पहले पखवाड़े में मांझी और नीतीश के बीच बातचीत हुई और मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह अक्सर नीतीश कुमार से टिप्स लेते रहे हैं, पर दोनों नेताओं को एक मंच पर आए अर्सा हो गया. दोनों में संवाद की कोई ख़बर बिहार की राजनीति और शासन तंत्र को नहीं है. पार्टी की बैठकों या कार्यक्रमों में मांझी की अनदेखी, उन्हें ख़बर न देने या न बुलाने की अघोषित नीति बदस्तूर जारी है. भावी विधानसभा चुनाव में अपने मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए इन दिनों नीतीश की संपर्क यात्रा चल रही है. वह बिहार के क़रीब तीन दर्जन ज़िलों में दल के निष्ठावान एवं चुनिंदा कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं. इस कार्य में वशिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री एवं सांसद उनके साथ होते हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं समझी गई.

दिलचस्प तो यह है कि इस दौरान जद (यू) में नकली मुख्यमंत्री बनाम असली मुख्यमंत्री का मुहावरा भी चलाया गया है. मांझी कुछ भी बोलें, उस पर नीतीश कुमार की राय आप कतई नहीं जान सकेंगे. मांझी को उनके प्रिय विधायक पागल कहें, उनका खास आदमी मांझी को अनुशासनहीन बताए, सरकार का कोई मंत्री अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा मांगे, लेकिन नीतीश को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. दल और सरकार के संदर्भ में, बिहार की समस्याओं के संदर्भ में खामोशी उनका स्थायी भाव-सा बन गई है. यह उस दल के सबसे बड़े नेता की बात है, जहां अनुशासन के नाम पर चार-चार विधायकों की विधायकी ख़त्म कराने की जी-तोड़ कोशिश की गई और उसमें सफलता भी मिली. चार और विधायकों की विधायकी ख़त्म कराने की चेष्टा की जा रही है. अनुशासन का ऐसा मानदंड और सुप्रीमो की ऐसी अनुशासनप्रियता किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती है.

तो, क्या जद (यू) को मांझी की ज़रूरत नहीं है? बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गंभीरता से पूछा जा रहा है. इसका उत्तर तो जद (यू) नेतृत्व विशेषकर, नीतीश कुमार एवं शरद यादव जैसे शिखर व्यक्तित्व दे सकते हैं. लेकिन, यदि पार्टी के राजनीतिक आचरण में इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाए, तो यह हां में दिखता है.

मांझी के ख़िलाफ़ गोलबंद राजनीतिक चेहरे ऐसे नहीं हैं, जो मुख्यमंत्री (विधायक दल के नेता) के ख़िलाफ़ स्वत: अभियान शुरू करें और जिन पर लगाम लगाने की ताकत पार्टी के नेताओं में न हो. ये चेहरे वस्तुत: राजनीति में दया के पात्र रहे हैं और ग़ैर-राजनीतिक कारणों से पाल-पोसकर इन्हें हैसियत अता की गई है. अब एक बार फिर इन बदनाम ग़ैर-राजनीतिक चेहरों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसा जद (यू) के उन लोगों का मानना है, जो दल के बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए मांझी की ज़रूरत महसूस करते हैं. जद (यू) नेताओं की यह जमात दलित-महादलित एवं अति पिछड़ों में मांझी के बढ़ते राजनीतिक आकर्षण को महसूस कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों की सुनता कौन है? वस्तुत: अनेक सुप्रीमोवादी पार्टियों की तरह इस दल में भी संवाद की स्थिति निरंतर समाप्त होती जा रही है. पार्टी के कामकाज, राजनीतिक कार्यक्रमों के निर्णय और नीति-निर्धारण में जनतांत्रिक व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है. एक या दो व्यक्ति मिलकर नीति ही नहीं, सारा कुछ तय कर लेते हैं, चुनाव के लिए उम्मीदवार तक. चुनाव आने पर कार्यकर्ताओं की बात शुरू हो जाती है और चुनाव के बाद ख़त्म. ऐसी संवादहीनता और कामकाज की ग़ैर-जनतांत्रिक व्यवस्था में जो कहें नेता, जो करें नेता वाला माहौल बनता है. जद (यू) में भी यही माहौल है, जो निरंतर मजबूत होता जा रहा है. ऐसे में मांझी को तो निशाने पर आना ही था और वह आ गए. अब देखना है कि मांझी कैसे-कैसे पैंतरे बदलते हैं और उन पर अपनों के विष-बाण किस हद तक चलते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> भाजपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक के नाराज होने से नुकसान उठाना पड़ सकता है. अभी तक भाजपा ने ऐसे वोट बैंकों को अपने पक्ष में करने की कोई कोशिश नहीं की है, जबकि भाजपा की इस उपेक्षा से नाराज वोट बैंक विकल्पों की तलाश प्रारंभ कर चुका है. ऐसी स्थिति में पहले चरण के चुनाव में ही भाजपा को कुछ स्थानों पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

मिशन-44 के लिए भाजपा ने उतारे 32 मुस्लिम उम्मीदवार

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी को देश के एकमात्र राज्य जम्मू-कश्मीर में सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ मुस्लिम चेहरों की तलाश है, जो उसके मिशन-44 के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग दे सकें. मिशन-44 यानि 87 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में सत्ता प्राप्ति के लिए कम से कम 44 सीटों का लक्ष्य भाजपा ने कई महीने पहले ही शुरू किया था. दरअसल, संसदीय चुनावों में राज्य की कुल 6 में से 3 सीटें जीतने के बाद भाजपा के हौसले इतने बुलंद हुए कि वह राज्य विधानसभा में जीत का परचम लहराकर सरकार बनाने का सपना देखने लगी. संसदीय चुनावों के दौरान हिन्दू बाहुल्य जम्मू क्षेत्र और लद्दाख़ में भाजपा के पक्ष में वोटरों का असाधारण जोश देखने को मिला. भाजपा को लगभग 30 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों पर भाजपा का जादू बरक़रार रहा तो इसके लिए विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दरकार और 14 सीटों की व्यवस्था करना कोई असंभव बात नहीं होगी. पहले चरण में भाजपा ने घाटी में सोनावार, हबाकदल, अमीराकदल, तराल और सुपोर जैसे इन विधानसभा चुनाव क्षेत्रों पर तवज्जो देनी शुरू कर दी, जहां प्रवासी कश्मीरी पंडितों का बड़ा वोट बैंक है. चूंकि घाटी में अधिकतर मुस्लिम मतदाता चुनाव का बहिष्कार करते हैं, इसलिए भाजपा को उम्मीद है कि वह मुसलमानों के इस चुनावी बहिष्कार का फ़ायदा उठाते हुए कश्मीरी पंडितों के दम पर चंद सीटें जीत सकती है, लेकिन अगर भाजपा कश्मीरी पंडितों के दम पर घाटी में कुछ सीटें जीत भी लेती है तब भी सत्ता के सुख के लिए उसे और जोड़ तोड़ करनी होगी. यही वजह है कि अब भाजपा घाटी में कुछ प्रभावी मुस्लिम चेहरों का साथ लेना चाहती है जो जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के उसके सपने को साकार करने में मदद कर सकें.

अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या भाजपा को घाटी में किसी प्रभावशाली नेता का साथ मिल गया है? 10 नवंबर को सज्जाद ग़नी लोन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाक़ात और उसके बाद सज्जाद की ओर से मोदी के पक्ष में तारीफ़ों के पुल बांधने के बाद विश्लेषकों को विश्वास हो चला है कि सज्जाद ही भाजपा का वह मोहरा बन सकते हैं जो उसे जम्मू-कष्मीर में सत्ता की दहलीज़ तक पहुंचा सकता है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सज्जाद लोन और मोदी की मीटिंग की व्यवस्था आरएसएस नेता राज माधो और वर्तमान केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने करायी थी. ये दोनों नेता कुछ दिन पहले श्रीनगर में सज्जाद लोन से मिले थे. सज्जाद अभी तक घाटी में पृथकतावादी दल के गठबंधन हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता थे. उनके बड़े भाई बिलाल ग़नी लोन अभी भी मीर वाइज़ उमर फारूक़ के नेतृत्व वाली हुर्रियत कांफ्रेंस के एक धड़े के कार्यकारी सदस्य हैं. चौथी दुनिया से बात करते हुए सज्जाद लोन ने इस बात का खंडन किया कि वह चुनाव के बाद भाजपा से हाथ मिलाएंगे. हालांकि उनका कहना था कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि चुनावों में हमें क्या पोज़ीशन मिलती है. 47 वर्षीय सज्जाद लोन का उत्तरी कश्मीर के कई विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में ख़ासा प्रभाव है. इस बार उन्होंने उत्तरी कश्मीर के हिन्दुवाड़ा और कुपवाड़ा के 12 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिये हैं.

> विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से चार-पांच सीटों पर सज्जाद की जीत निश्चित है. पत्रकार अज़हर रफ़ीक़ी कहते हैं कि 2008 के विधानसभा चुनावों के अलावा 2009 और 2014 के संसदीय चुनावों में उत्तरी कश्मीर के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दर का जायज़ा लेने से पता चलता है कि सज्जाद लोन को यहां चार-पांच सीटें जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर सज्जाद लोन पांच सीटें भी ले आते हैं कि उनकी सहयोग से भाजपा मिशन-44 के बहुत क़रीब पहुंच सकती है.

विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से चार-पांच सीटों पर सज्जाद की जीत निश्चित है. पत्रकार अज़हर रफ़ीक़ी कहते हैं कि 2008 के विधानसभा चुनावों के अलावा 2009 और 2014 के संसदीय चुनावों में उत्तरी कश्मीर के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दर का जायज़ा लेने से पता चलता है कि सज्जाद लोन को यहां चार-पांच सीटें जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर सज्जाद लोन पांच सीटें भी ले आते हैं कि उनकी सहयोग से भाजपा मिशन-44 के बहुत क़रीब पहुंच सकती है. आश्चर्यजनक रूप से अतीत में भाजपा को एक सांप्रदायिक और मुस्लिम दुश्मन पार्टी बताने वाले सज्जाद लोन ने मोदी के साथ मुलाक़ात के बाद उनकी शान में तारीफ़ें करते हुए ज़मीन आसमान एक कर दिये. उन्होंने मोदी को अपना 'बड़ा भाई' बताते हुए कहा कि मैंने मोदी को एक महान व्यक्ति के रूप में महसूस किया. सज्जाद की सोच में अचानक यह बदलाव कैसे आया, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मैंने मोदी के साथ मुलाकात के दौरान उनके व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ महसूस किया, वही बयान किया है. मुझे वह एक गंभीर और चिंतक नेता लगे. मैं कोई तंगनज़र आदमी नही हूं. मैं यह भी जानता हूं कि अब्दुल्लाह और मुफ्ती ख़ानदानों ने हमेशा कश्मीर और कश्मीरियों का शोषण किया है. कांग्रेस भी कुछ अलग नहीं है. ऐसी स्थिति में अगर भाजपा के नाम से एक विकल्प मिलता है तो हमें उसे पर विचार करना चाहिए. इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बाढ़ पीड़ितों का पुर्नवास है. यह एक बहुत बड़ा काम है और भाजपा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. मोदी के साथ मुलाक़ात के दौरान बाढ़ पीड़ितों के पुर्नवास और जम्मू-कश्मीर के निर्माण व विकास पर बात की. मैंने उनका व्यवहार बहुत ही सकारात्मक पाया. ज़ाहिर है कि अगर सज्जाद लोन ने चुनावों में कुछ सीटें जीत लीं तो वह भाजपा के साथ हाथ मिलाने में ज़रा देर नहीं लगाएंगे. दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सज्जाद लोन को मिलने वाली सीटें भाजपा के मिशन 44 का हिस्सा होंगी.

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार भाजपा में और मुस्लिम नेताओं का साथ पाने की कोशिशें जारी हैं और इस संबंध में वह डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के अध्यक्ष गुलाम हसन मीर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हकीम मोहम्मद यासीन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर अब्दुल रशीद के साथ लगातार संपर्क में हैं. अज़हर रफ़ीक़ी का मानना है कि अगर भाजपा को सज्जाद लोन के साथ-साथ कामयाब हो जाने वाली कुछ छोटी पार्टियों और कुछ कामयाब उम्मीदवारों का सहयोग मिल जाता है तो उसे जम्मू-कश्मीर में अगली सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है. देश में मोदी सरकार के गठन के बाद भाजपा जम्मू-कश्मीर में बड़ी तेज़ी से अपनी जड़ें मज़बूत करने की काशिशें कर रही है. यह पार्टी जहां हिन्दू बाहुल्य जम्मू क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए राम मंदिर का निर्माण, समान सिविल कोड के लागू करने और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली दफ़ा 370 के ख़ात्मे का वादा करती नज़र आती है. वहीं यह पार्टी 'चित भी मेरी पट भी मेरी' की तरह घाटी में कुछ मुस्लिम नेताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विकास और बाढ़ पीड़ितों के पुर्नवास के नारे को भी बुलंद कर रही है, लेकिन भाजपा के इस दोहरे मापदंड के बावजूद राज्य की सत्ता पर उसकी पहुंच संभव है, क्योंकि लोकतंत्र तो बहरहाल नंबरों का खेल है. यह बात भी भाजपा के पक्ष में जाती है कि राज्य की सबसे पुरानी पार्टी यानी नेशनल कांफ्रेंस राज्य में अपनी साख बुरी तरह खो चुकी है. राज्य कांग्रेस का भी बुरा हाल नज़र आ रहा है, जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी केवल घाटी में सक्रिय नज़र आ रही है. दूसरी ओर जम्मू और लद्दाख़ में मतदाता भाजपा के पक्ष में नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा घाटी में सज्जाद लोन जैसे नेताओं का साथ पाकर भाजपा अन्य दलों के मुक़ाबले बेहतर पोज़ीशन में नज़र आ रही है. वर्तमान राजनीतिक परिदृष्य में भाजपा अपने 'मिषन 44' के नज़दीक आती लग रही है. तो क्या जम्मू-कश्मीर में आने वाली सरकार भाजपा की होगी, इस सवाल का जवाब पाने के लिए डेढ़ महीने का इंतेज़ार करना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड: भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता है

आखिर ऐसी कौन सी बात है, जो एक साथ पार्टी के अंदर इतना बड़ा भूचाल आ गया और एक साथ कई लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? बीते विधान सभा चुनाव (2009) में बरकट्ठा से भाजपा अमित कुमार यादव ने 39485 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, जबकि अमित कुमार यादव के चाचा जानकी प्रसाद यादव झाविमो के टिकट पर 30117 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे.

मंगलानंद

दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली भाजपा के झारखंड जीतने के सपने शायद पूरे न हो पाएं. हाल ही में आए एक सर्वे के मुताबिक पार्टी को राज्य में पूर्ण बहुमत न मिलने की आशंका है. राज्यभर में किए गए इस सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि 41 प्रतिशत लोग वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं. सर्वे के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 29 से 35 सीटों के बीच मिलने की संभावना है. इसका मतलब यही है कि पार्टी 81 सदस्यीय विधान सभा में पूर्ण बहुमत से दूर रह सकती है.

वैसे इसके कई कारण माने जा रहे हैं लेकिन इनमें से प्रमुख कारण के रूप में भाजपा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू)के गठजोड़ को ही माना जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि इस गठबंधन से भाजपा को फायदे की बजाय नुकसान होने जा रहा है. इस गठबंधन को लेकर कई जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति रोष की भावना है. हजारीबाग, रामगढ़, रांची से लेकर धनबाद तक विद्रोह का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि भाजपा को पहले जो लाभ होने की उम्मीदें दिख रही थीं, वर्तमान समय में नुकसान की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं. इसका एक और कारण टिकटों के बंटवारे में भेदभावपूर्ण रवैये को भी माना जा रहा है. इन जिलों में 17 फीसदी अल्पसंख्यक आबादी में किसी को टिकट नहीं मिलने के अलावा वैश्य समुदाय के नेताओं का कोई खास तवज्जो नहीं दिया जाना भी भाजपा के लिए खासा नुकसानदायक हो सकता है. शायद यही वजह है कि पार्टी से खिन्न होकर बरही विधानसभा क्षेत्र में आजसू की साबी देवी ने जहां झामुमो का दामन थाम लिया, वहीं सदर विधानसभा से प्रदीप प्रसाद निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद चुके हैं. बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में भी नाराजगी कुछ कम नहीं है. आजसू के अर्जुन प्रसाद अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं और जनसंपर्क तेज कर दिया है. जबकि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के भीतर भी अंदरूनी अंतर्कलह हावी है. भाजपा से ही अलग होकर देवीलाल साव ने जहां बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है वहीं राजेंद्र प्रसाद एक क्षेत्रीय दल से टिकट प्राप्त कर लिया है. इतना ही नहीं कई ने तो भाजपा के अमित यादव के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मन बना लिया है.

आखिर ऐसी कौन सी बात है, जो एक साथ पार्टी के अंदर इतना बड़ा भूचाल आ गया और एक साथ कई लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? बीते विधान सभा चुनाव (2009) में बरकट्ठा से भाजपा अमित कुमार यादव ने 39485 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, जबकि अमित कुमार यादव के चाचा जानकी प्रसाद यादव झाविमो के टिकट पर 30117 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे. वहीं तेजी से पार्टी बदलने वाले नेता दिगंबर प्रसाद मेहता 21119 मत लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे तथा कांग्रेस के टिकट पर जयशंकर पाठक 11493 मत लाकर चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर झामुमो के कमलनयन सिंह थे, जिन्होंने 9769 वोट लाया था. छठवें स्थान पर भुनेश्वर प्रसाद मेहता रहे थे, जिन्हें मात्र 7321 वोट पर ही संतोष जताना पड़ा था. आसन्न विधानसभा में इस बार जयशंकर पाठक हजारीबाग सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जबकि भुनेश्वर प्रसाद मेहता एवं कमलनयन सिंह चुनाव से बाहर हैं. लेकिन जानकी यादव पुन: झाविमो से प्रत्याशी हैं और कहीं ऐसा न हो, कि भाजपा की अंतर्कलह में वे बाजी मार लें. चूंकि बीते विधानसभा में वे मात्र 9468 वोट से ही पराजित हुए थे. जबकि 2009 के चुनाव में अमित कुमार यादव को सहानुभूति वोट भी हासिल हुआ था. इसका कारण यह था कि उनके विधायक पिता स्वर्गीय चितरंजन यादव का निधन भी उसी के आस-पास में हुआ था.

भाजपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक के नाराज होने से नुकसान उठाना पड़ सकता है. अभी तक भाजपा ने ऐसे वोट बैंकों को अपने पक्ष में करने की कोई कोशिश नहीं की है, जबकि भाजपा की इस उपेक्षा से नाराज वोट बैंक विकल्पों की तलाश प्रारंभ कर चुका है. ऐसी स्थिति में पहले चरण के चुनाव में ही भाजपा को कुछ स्थानों पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में वैश्य समुदाय है. इसके अलावा मारवाड़ी और पंजाबी भी पिछले कई चुनावों में भाजपा के पक्ष में मतदान करते आये हैं. इस बार इन तीनों ही वर्गों में भाजपा के प्रति नाराजगी नहीं तो उदासीनता जरूर है. पलामू में तो वैश्य मोर्चा ने भाजपा के विरोध का ऐलान भी कर दिया है. वहां से किसी भी वैश्य को टिकट नहीं दिये जाने की वजह से ऐसी घोषणा हुई है. रांची और आस-पास के इलाकों में भी बनिया और इसकी उपजाति के मतदाताओं की अच्छी-खासी तादाद है. रघुवर दास को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाये जाने के बाद यह वर्ग अपने लिए आनुपातिक सीट पाने की उम्मीद में था, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो पाया. दूसरी तरफ रांची समेत कई इलाकों में लगातार भाजपा के लिए हर स्तर पर काम करने वाला मारवाड़ी समुदाय भी इस बार अचानक नाराज नजर आने लगा है. यद्यपि इससे जुड़े लोग इस बारे में औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहते पर ऐसे संकेत मिलते हैं कि रांची सीट के लिए इस बार कुछ लोगों को यह उम्मीद थी कि अजय मारू को भी टिकट मिलेगा, लेकिन चार बार के विधायक सीपी सिंह को ही पार्टी ने टिकट दिया. वहीं रामगढ़ से भी भाजपा की ओर से मारवाड़ी समुदाय के नेता दावेदार थे, लेकिन इस सीट पर गठबंधन में आजसू के खाते में गयी. लगभग यही स्थिति पंजाबी समुदाय की रही. इसके कई बड़े नेता हाल के कुछ घटनाक्रमों की वजह से भाजपा से दूर चले गये हैं. जबकि रांची और जमशेदपुर में यह वर्ग प्रभावी तरीके से मतदान करता है. इसके बाद भी पार्टी के नेताओं ने इस समाज के लोगों को मनाने का काम नहीं किया. जिसकी वजह से ही इन तीनों ही वर्गों में फिलहाल भाजपा के समर्थन की लहर नहीं है. समाज से जुड़े प्रमुख लोग आपसी स्तर पर विकल्प की तलाश पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक भाजपा विरोधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

अब ऐसे समय में जब चुनाव का समय माथे पर आ चुका है भाजपा को पार्टी के भीतर अंतर्कलह का नुकसान उठाना पड़ सकता है. कमोवेश यह तस्वीर सर्वे में भी सामने आई है. हालांकि पार्टी नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी. अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है.■

feedback@chauthiduniya.com

सितापुर : ध्वस्त हो रहा है मेक इन इंडिया का नारा

कल-कारखाने दम तोड़ रहे हैं

हिमांशु कुमार

देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर देशी-विदेशी उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए रास्ता खोल दिया है, लेकिन लखनऊ-दिल्ली राजमार्ग पर स्थित सीतापुर जनपद में उद्योग लगाने के लिए अभी तक किसी उद्योगपति ने पहल नहीं की है. इस जनपद में जो बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान पहले से मौजूद हैं, वे भी शासन-प्रशासन की अनदेखी के चलते दम तोड़ते जा रहे हैं. सीतापुर की कई नामचीन मिलें बंद हो चुकी हैं, जिनमें 126 मूंगफली ऑयल मिलें, बाला जी वेजिटेबिल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सुहागिन- डालडा फैक्ट्री), एशिया प्रसिद्ध प्लाईवुड फैक्ट्री, सहकारी कताई सूत मिल, महमूदाबाद शुगर मिल एवं महोली चीनी मिल कमलापुर समेत कई छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां प्रमुख हैं. अभी कुछ दिनों पहले जनपद की एकमात्र कागज फैक्ट्री का भी कामकाज ठप हो गया. सीतापुर की कई सूत कताई मिलें दम तोड़ चुकी हैं. इस जनपद के भूड़ इलाके में मूंगफली की अच्छी पैदावार होती थी, जिसे देखते हुए हरियाणा एवं राजस्थान से मारवाड़ी समाज के पूंजीपतियों ने यहां आकर मूंगफली ऑयल मिलें लगाई थीं. इधर दो दशकों से किसानों का मूंगफली की खेती से मोहभंग हो गया और वे अन्य फसलों को तरजीह देने लगे. नतीजतन, मूंगफली ऑयल मिलों को पर्याप्त मात्रा में मूंगफली मिलनी कम हो गई और एक-एक करके सभी 126 मूंगफली ऑयल मिलें बंद हो गईं. सीतापुर में धान, गेहूं और गन्ना भी पर्याप्त क्षेत्रफल में बोया जाता है. मौजूदा समय में जनपद में रामगढ़ चीनी मिल, जवाहरपुर चीनी मिल, सेक्सरिया शुगर मिल, बिसवां दि अवध शुगर मिल एवं हरगांव सहकारी किसान चीनी मिल महमूदाबाद चालू हालत में हैं, जबकि महोली चीनी मिल दो दशकों से अधिक समय से बंद है. इस मिल द्वारा निर्मित चीनी अपने बड़े दाने के लिए पूरे देश में विख्यात थी. कमलापुर चीनी मिल भी कई सालों से बंद है. इस मिल पर किसानों के 12 करोड़ रुपये से अधिक पैसा बकाया है. मिल में ताला लगा हुआ है और बेशक़ीमती मशीनें पड़ी-पड़ी जंग खा रही हैं. महमूदाबाद सहकारी सूत कताई मिल सेमरी चौराहा के पास स्थापित की गई थी. कुछ वर्षों तक तो वह चली, लेकिन नेताओं एवं श्रमिक संगठनों के धरना-प्रदर्शनों के चलते मिल घाटे में चली गई और आख़िरकार उसे बंद करना पड़ा. कर्मचारियों को वीआरएस का लाभ देकर नौकरी से छुट्टी कर दी गई. सीतापुर नगर के जीटी रोड पर स्थित सुहागिन-डालडा फैक्ट्री, जिसका वनस्पति घी पूरे देश में सबसे अच्छा माना जाता था, उसे कथित मिलावट की सूचना पर तत्कालीन ज़िलाधिकारी विजय शंकर पांडेय ने प्रबंधन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके बंद करा दिया. तबसे आज तक इस फैक्ट्री में वनस्पति घी का उत्पादन नहीं हो सका और इसमें काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी एवं श्रमिक बेरोज़गार हो गए.

प्लाईवुड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड सीतापुर द्वारा निर्मित प्लाई की वजह से इसका डंका न सिर्फ़ भारत में बजता था, बल्कि एशिया के विभिन्न देशों तक इसकी प्लाई (सीता टैक्स) की मांग थी. इस नामचीन प्लाईवुड फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेज उद्योगपति थॉमसन ने की थी. जब थॉमसन भारत छोड़कर इंग्लैंड वापस जाने लगे, तो उन्होंने इसे व्यवसायी जफरुल्लाह के हाथों बेच दिया. कुछ वर्षों तक यह ठीकठाक ढंग से चली. इसमें हज़ारों कर्मचारी-श्रमिक तीन पालियों में काम करते थे. यहां रेल मार्ग द्वारा असम तक की लकड़ी आती थी, लेकिन छोटी-बड़ी मांगों को लेकर विभिन्न श्रमिक संगठनों के बैनर तले आएदिन हड़ताल, धरना-प्रदर्शन आदि होने लगे और उत्पादन दिनोंदिन गिरता चला गया. अंततः फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद कर दिया, जिससे हज़ारों श्रमिकों की रोजी-रोटी जाती रही. यही नहीं, श्रमिकों-कर्मचारियों का वेतन एवं फंड आदि भी मिल प्रबंधन पर बकाया हो गया. ज़िले में दर्जनों चावल मिलें हैं, लेकिन वे भी शासन-प्रशासन की ढुलमुल नीतियों के चलते बंदी की कगार पर हैं. उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है. ऐसी कई समस्याएं मिल मालिकों के आगे मुंह बाए खड़ी हैं, जिनके निदान के लिए राइस मिलर्स एसोसिएशन आएदिन आंदोलन करता रहता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता. ज़िले में कभी भारी मात्रा में सरसों, लाही, गेहुंआ, अलसी, तिल आदि तिलहनी फसलें हुआ करती थीं, लेकिन रबी की फसल देर से बोने की वजह से पहले की अपेक्षा अब तिलहनी फसलें पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं, जिसके चलते कई तेल मिलें बंद हो चुकी हैं और कई बंदी की कगार पर हैं. अब यहां के कुछ व्यवसायी राजस्थान से टैंकरों द्वारा सरसों का तेल मंगाकर उसे डिब्बों-पीपों में पैक करके थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं. यही नहीं, ज़िले की कई गुड़-चीनी बेलें भी बंद हो चुकी हैं. गांजरी क्षेत्र एवं ब्लॉक एरिया में गुड़ बनाने वाले कोल्हू कढ़ाई कुटीर उद्योग के रूप में कुछ लोगों ने लगा रखे हैं. सीतापुर का नाम दरी उत्पादन के लिए भी लिया जाता है, लेकिन सूत और पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण यह उद्योग भी दम तोड़ रहा है. दरी-दरा बनाने वाले बुनकरों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. हथकरघा चलाकर दरी बनाने से लागत का पैसा भी नहीं वसूल हो पा रहा है. बुनकरों के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन पात्र बुनकरों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है. ■

खोखले सरकारी दावे

बुनकरों के लिए समाजवादी पार्टी सरकार कई तरह की योजनाएं लागू करने का दावा करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उक्त योजनाएं कारगर तरीके से लागू दिखती नहीं हैं. सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दावा किया कि मुलायम सिंह यादव केमुख्यमंत्रित्व काल में भी बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई थीं और अब अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में भी बुनकरों के कल्याणार्थ कई योजनाएं शुरू की गई हैं. चौधरी ने कहा कि सपा सरकार बनने के बाद हथकरघा बुनकरों के लिए आर्थिक पैकेज योजना केतहत 21,620 व्यक्तिगत बुनकरों, 924 प्राथमिक समितियों एवं 12 एपेक्स समितियों को 65.11 करोड़ रुपये जारी किए गए. वित्तीय वर्ष 2013-14 में घोषित आर्थिक पैकेज योजना में लगभग 1,000 प्राथमिक समितियों एवं व्यक्तिगत बुनकरों को लाभांवित किया गया. बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वर्ष 2013-14 में 7,520 बुनकरों को क्रेडिट कार्ड जारी करते हुए 806.61 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया. 2013-14 में माह सितंबर तक 4.328 बुनकरों को क्रेडिट कार्ड जारी करते हुए 603 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया. कच्चे माल की आपूर्ति हेतु धागे की खरीद पर 10 प्रतिशत सब्सिडी पाने के लिए 42,157 बुनकरों को पासबुक जारी की गई. हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार की धनराशि भी बढ़ा दी गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

रामदेव को जेड सुरक्षा चर्चा का विषय बनी

राजकुमार शर्मा

लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार करने का ईनाम सरकार द्वारा योगगुरु बाबा रामदेव को जेड सुरक्षा के रूप में दिया जाना इन दिनों देवभूमि में चर्चा का विषय बना हुआ है. केंद्र सरकार ने बाबा को सुरक्षा देने की वजह अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से उनकी जान को ख़तरा होना बताया है. यह अनोखा मामला है कि रामदेव को सुरक्षा मुहैया कराने से पहले गृह मंत्रालय की ओर से यह आकलन ही नहीं किया गया कि उन्हें सुरक्षा की कितनी ज़रूरत है. गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देने से पहले उस पर ख़तरे की पूरी समीक्षा की जाती है. यह आकलन किया जाता है कि उसकी जान को किससे और किस तरह का ख़तरा है. रामदेव के मामले में ऐसा नहीं किया गया. बाबा को सुरक्षा देने के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य की हरीश सरकार के मानकों को अपने फ़ैसले का आधार बनाया.

रामदेव को उत्तराखंड की सीमा के भीतर पूर्व से ही राज्य की हरीश सरकार के फ़ैसले के अनुरूप जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलती रही है. मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में कांग्रेस और बाबा के बीच छत्तीस के आंकड़े का संबंध बन गया था, जिसकी वजह जगजाहिर है. केंद्र में सत्ता का मुखिया बदलते ही राजनीति के सुजान हरीश रावत ने बाबा को उनके मन-मुताबिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें अपने पक्ष में करने का दांव खेला और बाबा उनके दांव में फंस भी गए. क्षणे रुष्टा-क्षणे तुष्टा स्वभाव के बाबा ने कांग्रेस के प्रति नरम रुख कर लिया और अनेक मुद्दों पर हरीश रावत सरकार की मुक्त कंठ सराहना भी करने लगे. बाबा ने साफ़ कहा कि संत किसी एक दल का नहीं होता. बाबा के बदलते रुख ने केंद्र सरकार के माथे पर पसीना उकेर दिया. भगवा ताकतों के क़रीबी माने जाने वाले बाबा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर मिले थे. बाबा की प्रधानमंत्री से क्या बातें हुईं, यह पूरी तरह से गुप्त ही रखा गया. प्रधानमंत्री सचिवालय ने बाबा के प्रधानमंत्री से मिलने की फोटो जारी की. राजनीति के जानकार तभी मानने लगे थे कि मोदी ने हरीश रावत के नहले पर दहला दे मारा. इसका परिणाम एक पखवाड़े बाद सामने आ गया.

हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ के संस्थापक रामदेव को अर्द्धसैनिक बल के कमांडो प्रदान किए जाएंगे. 40 सुरक्षाकर्मी हर वक्त उनकी सुरक्षा में रहेंगे. रामदेव विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने की मांग कर रहे हैं. बाबा को मिल रही धमकियों के मद्देनज़र हरिद्वार में बाबा रामदेव, उनके आवास संत कुटीर एवं कार्यस्थल के इर्द-गिर्द निजी सुरक्षाकर्मियों का घेरा बढ़ा दिया गया है. बाबा के क़रीबी बालकृष्ण ने बताया कि

> रामदेव को उत्तराखंड की सीमा के भीतर पूर्व से ही राज्य की हरीश सरकार के फ़ैसले के अनुरूप जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलती रही है. मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में कांग्रेस और बाबा के बीच छत्तीस के आंकड़े का संबंध बन गया था, जिसकी वजह जगजाहिर है. केंद्र में सत्ता का मुखिया बदलते ही राजनीति के सुजान हरीश रावत ने बाबा को उनके मन-मुताबिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें अपने पक्ष में करने का दांव खेला और बाबा उनके दांव में फंस भी गए.

देश की खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों ने स्वामी जी की जान पर ख़तरे को देखते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा देने संबंधी सूचना केंद्र सरकार की ओर से दी है. बाबा को सरकार द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा देने को लेकर जितने मुंह, उतनी बातें हो रही हैं. एक बात यह भी उभर कर आ रही है कि हरीश के बाबा से बढ़ते क़रीबी रिश्तों की घबराहट में प्रधानमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्हें अपने पाले में रखने के लिए यह बड़ा दांव खेला है. देवभूमि में राजनीति के जानकार मानते हैं कि बाबा काला धन के मुद्दे पर चुप्पी साधे रहें, इसीलिए यह पूरा व्यूह रचा गया है.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपना रंग बदल दिया. योगगुरु को मोदी सरकार द्वारा जेड सुरक्षा दिए जाने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जो संत है, दुनिया के मोह-माया से परे है, उसे किससे और क्या ख़तरा हो सकता है. यह जनता की गाढ़ी कमाई का खुला अपव्यय है, जिसे देने से पहले सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए था. जबकि सच्चाई यह है कि योगगुरु रामदेव को गोमुख यात्रा पर कड़ी सुरक्षा के मध्य वन क़ानून को धता बताकर सबसे पहले हरीश सरकार ने भेजा था. बाद में बाबा को उनके शिष्यों के साथ केदार नाथ यात्रा सरकारी खर्चे पर हरीश ने ही कराई. बाबा के लिए सुरक्षाकर्मियों की बड़ी फौज भी हरीश ने तैनात की थी. बाबा के पाला बदलते ही हरीश का रंग बदलना देखकर लोग हैरत में हैं. हरीश सरकार की सराहना करने वाले बाबा अब मोदी जी के पाले में पूरी तरह से खड़े दिख रहे हैं और यही बात सूबे के मुख्यमंत्री को पच नहीं रही है. ■

इतने बड़े हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को चल रहे नसबंदी शिविर के रूपरेखा की जांच करनी चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटनाएं न हों. बिलासपुर में हुए नसबंदी कांड की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है. इस आयोग का अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनीता झा को बनाया गया है. उन्होंने बताया की जांच की अवधि प्रशासन ने तीन माह निर्धारित की है. जांच आयोग पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी एक मामले में जांच का काम अनीता झा को दिया गया था. जिसकी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई है.

बिहार की राजनीति में जातिवाद सबसे महत्वपूर्ण है : इब्राहिमी

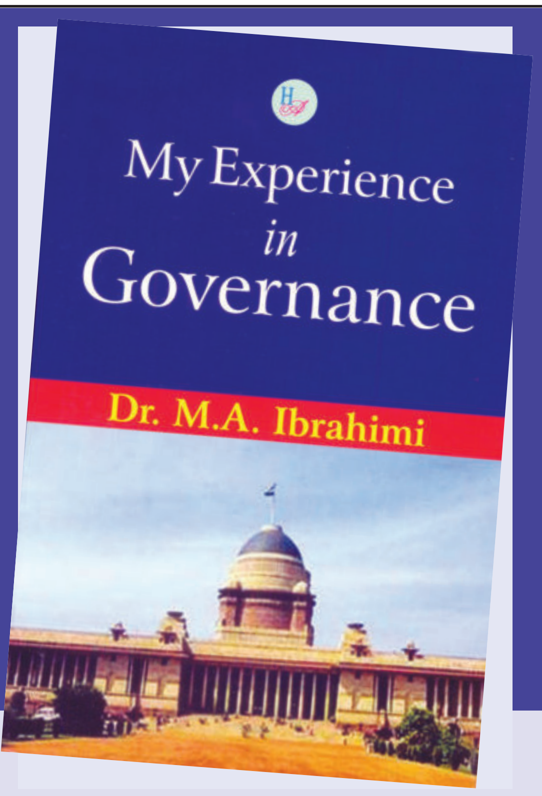

शफीक आलम

वर्ष 2012 में बिहार के मुख्य सचिव रैंक से सेवानिवृत 1978 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ एमए इब्राहिमी ने अपने प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर माई एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस (शासनतंत्र में मेरे अनुभव) के नाम से अंग्रेजी में किताब लिखी है. इस किताब में उन्होंने बिहार की राजनीति और प्रशासन में व्याप्त जातिवाद, भष्टाचार, हिंसा और सांप्रदायिकता जैसे विषयों के छुए और अनछुए पहलुओं पर बड़ी बेबाकी से टिप्पणी की है. वैसे जातिवाद, भष्टाचार, हिंसा, और सांप्रदायिकता का बिहार की राजनीति के साथ चोली-दामन का साथ है. इन विषयों पर पहले भी बहुत कुछ लिखा गया है और आगे भी लिखा जाता रहेगा. लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि बिहार के किसी नौकरशाह ने शासन व्यवस्था के अपने अनुभवों के आधार पर इन विषयों पर कलम उठाने की हिम्मत की हो. ऐसे में इस किताब की अहमियत और बढ़ जाती है. डॉ इब्रहिमी ने अपने 35 साल के करियर में कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया. इसके अलावा केंद्र सरकार में डेपुटेशन के दौरान प्रमुख पदों पर रह चुके इब्राहिमी लिखते हैं कि भारत की राजनीति और नौकरशाही आम तौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सी से शुरू होने वाले तीन शब्दों कास्टिज्म(जातिवाद), कम्युनलिज्म(सम्प्रदायिकता), करप्शन (भष्टाचार) के इर्द-गिर्द घूमती है.

जहां तक बिहार की राजनीति और प्रशासन में जातिवाद का सवाल है तो इससे उनका परिचय समस्तिपुर में एसडीओ के रुप में पहली नियमित नियुक्ति के दौरान ही हो गया था. एसडीओ के रूप में उन्होंने जब कुछ लोगों के खिलाफ एक मामले में कार्रवाई शुरू की तो उन्हें जिला प्रशासन के गुट की ओर से ऐसी प्रतिक्रियाएं मिल रही थीं कि वे एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. वह लिखते हैं कि मुझे उस वक्त यह समझ में आ गया था कि बिहार प्रशासन में काम करने के यहां की जातियों और संप्रदायों के बारे में जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है. एक नौकरशाह के रूप में तीन दशकों के अनुभवों के आधार पर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जातिवाद बिहार की राजनीति का सबसे महतवपूर्ण पहलू है, यहां जातिवाद के प्रभाव से कोई अछूता नहीं है.

अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर डॉ. इब्राहिमी लिखते हैं कि बिहार का हर मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर योग्यता के बजाय अपनी जाति को लोगों को तरजीह देते थे. अधिकांश प्रमुख पदों पर मुख्यमंत्री की जाति के लोगों की नियुक्ति की जाती थी. हालांकि बिहार के ही पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हैं. वे कहते हैं कि इब्राहिमी के विचार आंशिक रूप से सही हो सकते हैं लेकिन अब्दुल ग़फ़ूर और यहां तक कि लालू प्रसाद यादव जैसे मुख्यमंत्रियों ने अपनी जाति के लोगों को प्रदेश का मुख्य सचिव नहीं बनाया. दरअसल, इब्राहिमी ने मुख्य सचिव की बात नहीं की वे महत्वपूर्ण पदों की बात कर रहे हैं और यह संदर्भ किताब के हर हिस्से में मिलता है. वे लिखते हैं कि भगवत झा आज़ाद के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में एक भी मुस्लिम कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट नहीं था. अपने एक हालिया इंटरव्यू में इब्राहिमी ने बताया कि आम तौर पर बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जिसे दूरदर्शी कहा जा सके.

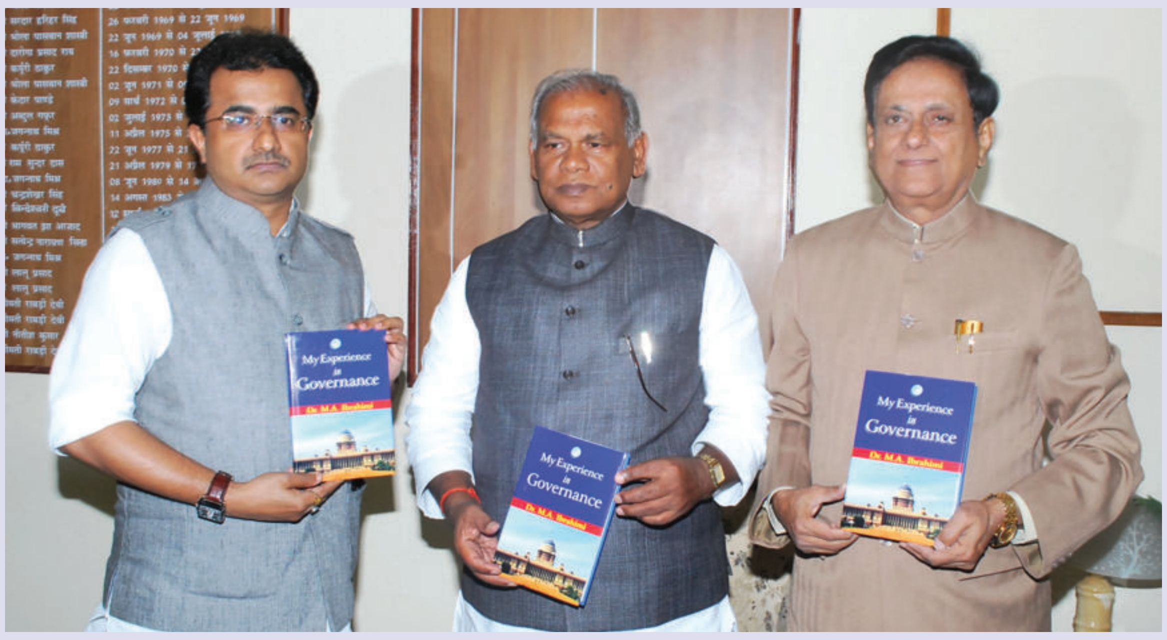

प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की महत्वकांक्षाएं भी ऊंची होती हैं. वे अपनी महत्वतकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ब्लैकमेलिंग से भी परहेज नहीं करते हैं. समस्तीपुर जेल गोली प्रकरण का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें फंसाने की कोशिश की गई. इस तरह के अनुभव से शायद सिविल सेवा के हर अधिकारी को इस तरह के मामलों से रू-ब-रू होना पड़ा. शायद यहभी एक वजह थी कि इस किताब के विमोचन के समय अपने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शिव क्रीर्ति सिंह ने यह सिफारिश की, कि हर नौजवान नौकरशाह को यह किताब पढ़नी चाहिए ताकि वे हर तरह की प्रशासनिक चुनौतियों को समझ सकें और उनसे बेहतर तरीके से निपट सकें.

बहरहाल, प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनका प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ा. उन्हीं घटनाओं में से एक है साल 1989 का भागलपुर दंगा. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद की चरमसीमा पर हुए इस दंगे में तरीबन 2000 लोग मारे गए थे. मरने वालों में ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी. इन दंगों में पुलिस खास तौर पर बिहार सेना पुलिस(बीएमपी) की भूमिका विवादास्पद रही. चूंकि उस वक्त बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी इसलिए मुसलमानों (जो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक समझे जाते थे) ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया. इसके बाद मुसलमान पूरे राज्य में फिर कभी कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हुए. हालांकि हाल ही में सोनिया गांधी ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उस वक्त दंगा रोकने में कांग्रेस सरकार की नाकामी के लिए मुसलमानों से माफ़ी भी मांगी. दरअसल बोफोर्स तोप सौदे की वजह से विवादों में घिरी कांग्रेस ने उस वक़्त एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान पार्टी के खिलाफ हो गये. शाह बानो केस और बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना उनमें शामिल थे.

भागलपुर दंगों के संबंध में वह कहते हैं कि चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई. दंगों की जांच के लिए न्यायिक जांच का गठन किया गया था. इस जांच समिति का प्रमुख ऐसे जज को बनाया गया था, जिनका एक चरमपंथी राजनीतिक दल के प्रति ज्यादा झुकाव था. कई लोगों ने इसी वजह से जांच पैनल में शामिल होते ही त्याग पत्र भी दे दिया. बहरहाल इस न्यायिक जांच की रिपोर्ट ने भागलपुर के डीआईजी की रिपोर्ट को सिरे से ख़ारिज कर दिया था. वह लिखते हैं कि दंगों के ज्यादातर दोषी मुख्यमंत्री लालू यादव की जाति के थे. दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने के लिए उन्होंने हर द दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कहीं से सकारात्मक जवाब नहीं मिला. वे लिखते हैं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से गृह सचिव यूएन पंजियार और उस वक्त राज्य के दो बड़े मंत्रियों शकील अहमद खान और अब्दुल बारी सिद्दीकी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की लेकिन उनमें से किसी ने भी पीडतों को मुआवज़ा दिलवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. हालांकि साल 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह मुद्दा एक फिर से उठा लेकिन वह इस नतीजे पर पहुंचे कि दंगा पीड़ितों को मुवाज़ा देने के मामले में सरकार बहुत कंजूस बन जाती है. फॉरबिसगंज पुलिस फायरिंग में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने के मामले में वे लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने मामले की जांच के लिए जांच आयोग के गठन पर पर खुशी-खुशी 10 करोड़ रुपये खर्च कर दिए लेकिन पीड़ितों को देने के लिए सरकार के पास पांच लाख रुपये भी नहीं थे. यदि किताब के पहले अध्याय को छोड़ दिया जाए तो लेखक ने केवल अपनी प्रशासनिक सफलताओं और असफलताओं के साथ-साथ राज्य की राजनीति पर बेबाक टिप्पणी की है. कहीं-कहीं कई दिलचस्प बातों का भी ज़िक्र उन्होंने किया है. मिसाल के तौर पर भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह जब बिहार दौरे पर बोकारो आए थ. अधिकारियों से परिचय करवाने के दौरान जब हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले एक आईपीएस अफसर की पत्नी से उनका परिचय कराया गया तो उन्होंने पूछ लिया कि उनका संबंध चीन से तो नहीं है. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गुलाम नबी आज़ाद के साथ एक मीटिंग में जब जापान और दुसरे देशों से बिहार आने वाले बौद्ध तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि बिहारी केवल बिहारी पर हमला करता है किसी गैर बिहारी को अपना मेहमान समझता है.

इस किताब पर भी यह आरोप लगाया जा सकता है कि जब नौकरशाह अपनी सेवा के दौरान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं तो वे किताब लिखते हैं और सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं. हालांकि यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि एक नौकरशाह को कितने राजनीतिक दबाव में काम करना होता है. पिछले दिनों कई सेवानिवृत्त नौकरशाह अपनी आत्मकथाओं की वजह से सुर्ख़ियों में थे. लेखक ने किताब में जिन बातों का जिक्र किया है वो बातें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं जिन्हें आसानी से सत्यापित किया जा सकता है. यह किताब न केवल सिविल सेवा से जुड़े अधिकारियों, बिहार की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर शोध करने वाले छात्रों के लिए अहम है बल्कि बिहार की राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए एक अहम दस्तावेज साबित होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

नसबंदी कांड

महिलाओं की मौत का जिम्मेदार कौन

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कैंप लगाकर किए गए नसबंदी कार्यक्रम में कुल 17 महिलाओं की मौत ने छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकारी लापरवाही और डॉक्टरों की कारगुज़ारियों का नज़ारा इस नसबंदी कांड में साफ दिखाई दिया, जिसमें महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और मासूम बच्चों के ऊपर से मां का आंचल छिन गया. इस नसबंदी शिविर में डॉक्टर ने निर्धारित मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी कर दी. इस हिसाब से देखा जाए तो एक आपरेशन को 3 मिनट मे निपटा दिया गया.

इस नसबंदी शिविर में दूरबीन विधि से 83 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद महिलाओं को उनके घर भेज दिया गया. घर पहुंचने के बाद महिलाओं की तबियत बिगड़ने लगी. उन्हें उल्टी, दस्त और चक्कर आने लगे, जिसके बाद परिजनों ने उनको स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया. इस दौरान 17 महिलाओं की मौत हो गई. इन ऑपरेशनों ने सरकार को एक बार फिर कठघरे में खड़ा तो किया साथ ही दवाओं की स्थानीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए. कैंप लगाकर की जा रही नसबंदी ने कई सवाल खड़े किए हैं. इस घटना के बाद कई सारी चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. नसबंदी के बाद महिलाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण डॉक्टरों को नसबंदी के दिए लक्ष्य को माना जा रहा है. डॉक्टरों को अधिक से अधिक नसबंदी ऑपरेशन करने का लक्ष्य दिया गया था. इस वजह से डॉक्टरों ने एक दिन में तीस ऑपरेशन किए जाने वाली मशीन से 83 ऑपरेशन कर डाले. जिनमें से 17 महिलाओं की मौत हो चुकी है. इन मौते के पीछे का प्रमुख कारण दवा को बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पता चला कि ऑपरेशन के बाद जो दवाएं महिलाओं को दी गई, उसमें चुहे मारने वाली दवा जिंक फॉस्फाइड के अंश मिले हैं, यह उनकी मौत का कारण हो सकता है. पोस्टमर्टम रिपोर्ट में जो परिणाम आए हैं और महिलाओं में जो लक्षण दिखे वो जिंक फॉस्फाइड खाने के बाद दिखते हैं. इस रिपोर्ट के आधार पर महावीर फार्मा कंपनी की 43 लाख 34 हजार टैवलेट को जब्त कर लिया गया. टारगेट पूरा करने के लिए जिन महिलाओं का ऑपरेशन किया जा रहा था उनमें कुछ महिलाएं बैगा जाति की भी थीं. यह जाति विलुप्ति की कगार पर हैं और संरक्षण की श्रेणी में रखी जा चुकी हैं. इन लापरवाह डॉक्टरों को केवल अपने टारगेट को पूरा करना और पुरस्कार लेना ही दिखाई दे रहा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं. डॉक्टरों के लिए महिलाओं की जिंदगी से ज्यादा उनका टारगेट था, जो उन्हें येन केन पूरा करना था. मामले को बढ़ता देख प्रशासन की तरफ से चार डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया. निलंबित होने वाले डॉक्टरों में डॉ आर के गुप्ता समेत नसबंदी कार्यक्रम के राज्य समन्वयक केसी उरांव, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के भांगे और प्रखंड चिकित्सा अधिकारी प्रमोद तिवारी थे. इसके बाद फरार चल रहे डॉक्टर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई. गौरतलब है कि डॉ गुप्ता को इसी साल ही 50 हजार नसबंदी ऑपरेशन करने के लिए मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को पुरस्कृत किया था.

जांच के बाद जो जानकारी सामने आई हैं उससे पता चला है कि जिस अस्पताल में नसबंदी कैंप लगाएगा गया था वह चार साल से बंद पड़ा था. सरकारी दस्तावेजों के अनुसार नवंबर माह में बिलासपुर जिले में लगने वाले कैंपों में बंद पड़े निजी अस्पताल का कहीं नाम नहीं था. अब इस घटना से सरकार का गांव-गांव चलाया जा रहा नसबंदी कार्यक्रम सवालों के घेरे में आ गया है. यहीं नहीं आशा ताईयों के खिलाफ भी शिकायतें मिली हैं कि सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा जो नसबंदी कराने वाली महिलाओं को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसमें से भी अपना हिस्सा लेती हैं. शिविर में नसबंदी के लिए लाई गईं ऑपरेशन के लिए अधिकतर महिलाओं के पति से नो तो ऑपरेशन की अनुमति ली गई और ना ही अन्य किसी परिजन से. शिकायत यह भी है कि आशा ताई को एक महिला के ऑपरेशन पर 150 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलते हैं. इसी लालच में वे महिलाओं को बहला-फुसलाकर ऑपरेशन के लिए लाती हैं. यहीं नहीं जिन महिलाओं की डिलेवरी हुई होती है और डिलेवरी होने के तीन महीने बाद ऑपरेशन करान सुरक्षित होता है. लेकिन वे महिलाओं को उससे पहले प्रोत्साहन के चक्कर में डिलेवरी के कुछ दिन बाद ही नसबंदी के लिए अस्पताल ले आती हैं. अब इतने बड़े हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को चल रहे नसबंदी शिविर के रूपरेखा की जांच करनी चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटनाएं न हों. बिलासपुर में हुए नसबंदी कांड की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है. इस आयोग का अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनीता झा को बनाया गया है. उन्होंने बताया की जांच की अवधि प्रशासन ने तीन माह निर्धारित की है. जांच आयोग पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी एक मामले में जांच का काम अनीता झा को दिया गया था. जिसकी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई है. ऐसे में नसबंदी कांड की जांच सरकार ने उनके हांथों में क्यों सौंपी? दूसरा सवाल जिन नकली दवा कंपनियों पर अब छापे मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? क्या रमन सरकार गरीब महिलाओं के मरने का इंतजार कर रही थी? अब यह देखना होगा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आती है या केवल जांच के नाम पर खाना-पूर्ति होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

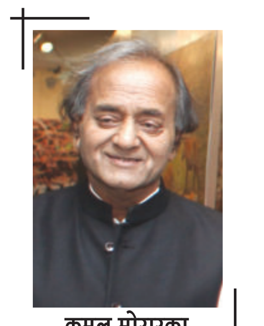

कमल मोरारका

संविधान के बताए रास्ते ही चलना होगा

ग़रीबी के बारे में जो आंकड़े हैं, वे मुझ जैसे शख्स को शर्म से सिर झुकाने को मजबूर कर रहे हैं. ज़रूरी यह है कि हमें ग़रीबों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए. मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, लेकिन ये न तो व्यवस्थित हैं और न इन्हें सही ढंग से संचालित किया जा रहा है. इन योजनाओं के नाम पर बेशुमार पैसा खर्च हुआ और हो रहा है. बेशक, यह योजनाएं सही दिशा में उठाया गया क़दम हैं, लेकिन मनरेगा और खाद्य सुरक्षा में जिस तरह पैसा बहाया जा रहा है, उसके लिए बड़े आर्थिक आधार की ज़रूरत है.

यह मायने नहीं रखता कि सरकार किसकी है. कोई भी सरकार हो, हमें संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों पर चलना ही होगा. सरकार को ग़रीबों, छात्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचना होगा. कॉरपोरेट तरीके से चलकर यह हासिल नहीं हो पाएगा. वास्तव में स्वतंत्रता के मायने क्या हैं? चाहे राजनेता हों, अन्य लोग हों, औद्योगिक घरानों के मुखिया हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी को एक बार फिर से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए. क्या हम उसी राह पर चल रहे हैं, जैसा कि संविधान में उल्लिखित है या 1952 से लेकर आज तक संविधान के सभी भागों को धीरे-धीरे विकृत कर रहे हैं? विकृत इस रूप में कि कागजों पर तो हम संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है.

उदाहरण के लिए, संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार का चुनाव कैसे होता है, उसके कर्तव्य क्या हैं और सरकार की भूमिका क्या हो. यह भी स्पष्ट है कि चुनी हुई सरकार नीतियां बनाए, वह चाहे राजनीतिक हों, आर्थिक हों या सामाजिक, लेकिन उनका क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से होना चाहिए. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं दूसरी सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं, जो एक कठिन प्रक्रिया के बाद चयनित होते हैं. इन सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कुशल लोगों का चयन होता है. इसलिए इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए ये अधिकारी सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं. दुर्भाग्य से जो भी राजनीतिक दल चुनकर आए, उन्होंने छोटे-छोटे मुद्दों पर ही अपनी रुचि दिखाई, न कि बड़े एवं ज़रूरी विषयों पर. कोई भी राजनीतिक दल उन आधारभूत विसंगतियों को बदलना नहीं चाहता, जो समूचे देश में व्याप्त हैं.

उदाहरण के तौर पर, जब देश का विभाजन हुआ, तो दुर्भाग्य से जिन्ना ने विभाजन धर्म के आधार पर किया और पाकिस्तान का निर्माण भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए हुआ. लेकिन, विभाजन के दिन से ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत में उससे ज़्यादा मुसलमान रह गए, जितने विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए. यह क्या दर्शाता है? और, जो मुसलमान भारत में ही रह गए, उन्होंने यहीं रहने को क्यों तरजीह दी? इसलिए, क्योंकि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल एवं मौलाना आज़ाद ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा और सरकार देश के नागरिकों के लिए धर्म को कभी आधार नहीं बनाएगी. धर्म एक व्यक्तिगत मसला है. इसका केवल इतना-सा मतलब है कि आप ईश्वर को सिर्फ़ किसी और नाम से याद कर रहे हैं. आप कहीं उसे भगवान कह सकते हैं, कहीं अल्लाह, कहीं जीजस क्राइस्ट, तो कहीं वाहे गुरु. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप उसे किस नाम से बुला रहे हैं. लेकिन, क्या हम उस भावना के साथ चल रहे हैं?

> अगर मैं मुसलमान होता (जो कि मैं नहीं हूं) और भारत में रह रहा होता, तो निराश होता, क्योंकि देश के महान नेताओं ने जो वादा किया था, उसे बाद की सरकारों ने निभाया नहीं. हां, यह सही है कि सबने हमें केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया. इस देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का है, लेकिन उनकी सहभागिता क्या है, यह बड़ा सवाल है. भारतीय प्रशासनिक सेव-ाओं में दो प्रतिशत, भारतीय पुलिस सेवा में दो प्रतिशत और कॉरपोरेट जगत में तो बमुश्किल एक या दो प्रतिशत. फिर उन्हें क्या हासिल हुआ?

अगर मैं मुसलमान होता (जो कि मैं नहीं हूं) और भारत में रह रहा होता, तो निराश होता, क्योंकि देश के महान नेताओं ने जो वादा किया था, उसे बाद की सरकारों ने निभाया नहीं. हां, यह सही है कि सबने हमें केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया. इस देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का है, लेकिन उनकी सहभागिता क्या है, यह बड़ा सवाल है. भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में दो प्रतिशत, भारतीय पुलिस सेवा में दो प्रतिशत और कॉरपोरेट जगत में तो बमुश्किल एक या दो प्रतिशत. फिर उन्हें क्या हासिल हुआ? साफ़ है कि मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ. उन्हें समान अवसर नहीं मिले. उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई. ज़्यादातर मुसलमान आज भी अशिक्षित हैं. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक समाजवादी एवं लोकतांत्रिक देश है. अब यह बेहद ज़रूरी है कि मौजूदा सरकार संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे, जिसकी इस समय पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है.

ग़रीबी के बारे में जो आंकड़े हैं, वे मुझ जैसे शख्स को शर्म से सिर झुकाने को मजबूर कर रहे हैं. ज़रूरी यह है कि हमें ग़रीबों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए. मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, लेकिन ये न तो व्यवस्थित हैं और न इन्हें सही ढंग से संचालित किया जा रहा है. इन योजनाओं के नाम पर बेशुमार पैसा खर्च हुआ और हो रहा है. बेशक, यह योजनाएं सही दिशा में उठाया गया क़दम हैं, लेकिन मनरेगा और खाद्य सुरक्षा में जिस तरह पैसा बहाया जा रहा है, उसके लिए बड़े आर्थिक आधार की ज़रूरत है. यह भी सोचना होगा कि हम किस तरह से सबसे निचले या ग़रीब तबके को मध्यम वर्ग की श्रेणी में ले आएं. अमीर और अमीर हो रहे हैं, यह कोई समस्या नहीं है. लेकिन, ग़रीब अभी भी वहीं है, जहां पहले था, जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी हो रही है.

देश का मध्यम वर्ग बेहतरी के रास्ते पर है और आपके इर्द-गिर्द मॉल, मोटर गाड़ी, अच्छी सड़कों एवं विदेशी ब्रांड की चमक-दमक है, लेकिन ये सब उस आदमी की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते, जिसके पास ज़मीन नहीं है. भूमिहीन श्रमिक अभी भी भूमिहीन श्रमिक ही है और गांव का ग़रीब आदमी अभी भी ग़रीब है. वह केवल टीवी पर उभरती हुई तस्वीरों के माध्यम से इस चमक को देख सकता है और यह सब उसके भीतर एक टीस पैदा करता है. इस दौर में संविधान के अनुपालन की बेहद ज़रूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विश्वसनीयता का संकट

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

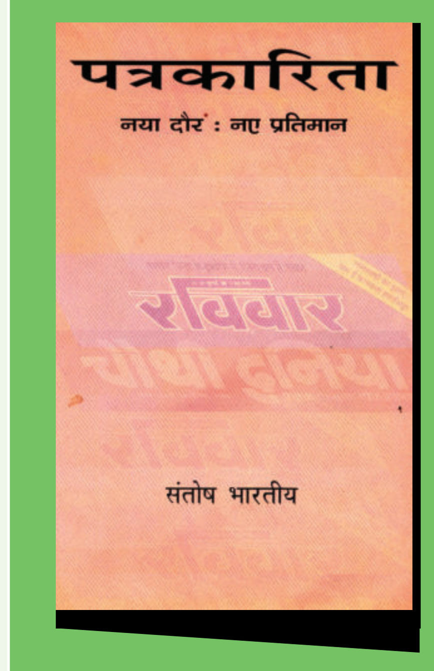

वैसे तो हर रिपोर्ट खोजी रिपोर्ट का लघु संस्करण होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रमाण कुछ भी लिखा गया साख खराब करता है. पाठक बहुत जल्दी समझ जाता है कि संवाददाता का उद्देश्य आख़िर है क्या? आज साख या क्रेडिबिलिटी ही सबसे बड़ी चुनौती है. विश्वसनीयता के इस संकट ने छोटे शहरों में पत्रकारों की स्थिति पुलिस जैसी बना दी है. लोग पत्रकार से डरते हैं और यदि सुबह-सुबह वे अपने यहां पत्रकारों को देखते हैं, तो घबरा जाते हैं. पत्रकार या संवाददाता कैसे पुलिस का पर्यायवाची न बनें, कैसे अपनी पत्रकारिता की सत्ता में पहुंच के ज़रिये अपना या दूसरों का काम न करवाएं, किस तरह पत्रकारिता स्वयं को प्रतिष्ठित करने का साधन न बने, यह सोचना होगा. इतना ही नहीं संपादकों का अख़बार के ज़रिये पुरस्कार लेना, विदेश यात्राएं करना, नौकरियां दिलाना, अपने लिए मकान बनाना, आउट ऑफ टर्न वस्तुओं को एलॉट कराना आदि काम नहीं करने चाहिए. पहले आउट ऑफ टर्न कई चीजें कराई जाती थीं, आज इसका रूप बदल गया है. आज बड़ी कंपनियों और मल्टी-नेशनल कंपनियों के लांचिंग पैड की भूमिका पत्रकारिता के कुछ बड़े निभाते हैं. सुरेंद्र प्रताप सिंह का तो मानना था, हमारी विश्वसनीयता तो सचमुच शून्य के क़रीब पहुंच चुकी है. इस इमेज को तोड़ने के लिए हम सभी को मिलकर दूसरों के साथ काम करना पड़ेगा.

पत्रकार या संवाददाता की साख या विश्वसनीयता पर मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह को उद्धृत करना चाहूंगा. उनसे ज़्यादा हिंदी पत्रकारिता में टिप्पणी के लिए उपयुक्त व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देता. उनका मानना था, आज पत्रकारिता के ज़रिये कुछ लोग अन्य सुविधाएं और उद्देश्य हासिल करने में लगे हुए हैं, लिहाजा पत्रकारों में इस तरह की चारित्रिक गिरावट तो निश्चित रूप से आई है, पर यह गिरावट समाज के हर अंग में आई है. अख़बार पलट कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क़ानून की रक्षा करने वाली पुलिस स्वयं हर प्रकार के संगीन जुर्म में शामिल है. लेकिन, एसपी का इसे देखने का एक और तरीका था. उन्होंने यह भी कहा है कि दरअसल, पत्रकार कोई देवदूत नहीं होता. उनमें भी बहुत सारे दलाल घुसे हुए हैं. समाज के बाहर रहकर पत्रकारिता नहीं हो सकती. यह कैसे हो सकता है कि समाज तो भारत का हो और पत्रकारिता फ्रांस की हो! समाज में आई चौतरफ़ा गिरावट पत्रकारिता में भी परिलक्षित हो रही है. पत्रकारों की विश्वसनीयता अवश्य कम हुई है, पर मेरे लिए यह कोई ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है. मेरे लिए चिंताजनक बात यह है कि लोगों का विश्वास राज्य की सत्ता से ही उठता जा रहा है. न्याय व्यवस्था, प्रशासन और सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है. मैं इसे पत्रकारिता की विशेष समस्या नहीं मानता.

एसपी के इस कथन में उनकी एक अलग तरह की चिंता झलकती है, मौजूदा समस्याओं मसलन सांप्रदायिकता, जातीयता आदि को बढ़ाने में प्रेस की बहुत बुरी भूमिका रही है. मैं समझता हूं कि एक दौर, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपने को जलाकर मार डाला, के पीछे सबसे बड़ी भूमिका अख़बारों की रही है. कुछ अख़बारों ने बाकायदा इस पर कैंपेन भी चलाया, मंडल का विरोध उन्हें तब तक संतुष्ट नहीं कर सका, जब तक नौजवान जलकर मरने नहीं लगे... और जल कर मरने वालों का समाचार जब न्यूज रूम में पहुंचता था, तो वहां जैसे उल्लास का एक वातावरण बन जाता था. उसी तरह राम मंदिर के मामले में भी देखने को मिला कि पत्रकार कारसेवक बन बैठे. मैं यह नहीं कहता कि पत्रकार धार्मिक भावना से अछूता रहे, पर इतना ज़रूर सोचता हूं कि पत्रकार को चाहिए कि वह इस भावना को दबाकर, समेट कर रखे, बस इसका प्रचार अख़बार के माध्यम से न करे. संवाददाता की विश्वसनीयता के लिए कुछ ज़रूरी संकेत ये हैं. संवाददाता को उन विषयों को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए, जहां आम आदमी का संघर्ष चल रहा हो. यह संघर्ष ज़मीन को लेकर हो सकता है, जंगल को लेकर हो सकता है, पानी को लेकर हो सकता है तथा अपने जीने के बुनियादी अधिकारों को लेकर हो सकता है. आजकल ऐसी रिपोर्ट न के बराबर लिखी जा रही है. टेलीविजन ने तो फील्ड में जाना बंद जैसा कर दिया है, जबकि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली ख़बरें फील्ड में यानी शहरों से बाहर गांवों की ओर क़दम-क़दम पर बिखरी पड़ी हैं.

इलेक्ट्रॉनिक संवाददाता यानी टीवी के लिए काम कर रहे पत्रकार और प्रिंट के लिए काम कर रहे पत्रकार के बुनियादी नियम एक ही हैं. उल्टा हो रहा है. जहां टेलीविजन को दिखाने की क्षमता के कारण पूरी रिपोर्ट दिखानी चाहिए, वह अज्ञानतावश बाइट को आधार बनाकर अधूरी तस्वीर दिखा रहा है. टेलीविजन पत्रकारिता को विकसित करने का काम कहीं पीछे इसलिए छूट गया है, क्योंकि संपादकों ने एसपी सिंह द्वारा विकसित आजतक की शैली से आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की. अगर एसपी होते, तो आजतक की तस्वीर शायद कुछ और होती और तब गुणात्मक प्रतियोगिता ज़्यादा होती. आज सबसे बड़ी कमी टीवी पत्रकारिता के विषय में ट्रीटमेंट की है. अफ़सोस इस बात का है कि एसपी में श्रद्धा रखने वाले टीवी पत्रकार उनकी तकलीफ़ को न समझ कर उनकी शैली की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं.

> विश्वसनीयता के संकट ने छोटे शहरों में पत्रकारों की स्थिति पुलिस जैसी बना दी है. लोग पत्रकार से डरते हैं और यदि सुबह-सुबह वे अपने यहां पत्रकारों को देखते हैं, तो घबरा जाते हैं. पत्रकार या संवाददाता कैसे पुलिस का पर्यायवाची न बनें, कैसे अपनी पत्रकारिता की सत्ता में पहुंच के ज़रिये अपना या दूसरों का काम न करवाएं, किस तरह पत्रकारिता स्वयं को प्रतिष्ठित करने का साधन न बने, यह सोचना होगा. इतना ही नहीं संपादकों का अख़बार के ज़रिये पुरस्कार लेना, विदेश यात्राएं करना, नौकरियां दिलाना, अपने लिए मकान बनाना, आउट ऑफ टर्न वस्तुओं को एलॉट कराना आदि काम नहीं करने चाहिए.

संवाददाता से लेकर संपादक तक एक पूरी कड़ी बनती है. यदि इस कड़ी में कहीं भी कमजोरी आती है, तो वह रिपोर्ट के प्रभाव और उसकी धार पर असर डालती है. इसलिए हमेशा सावधान रहना जहां संपादक के लिए आवश्यक है, वहीं डेस्क और संवाददाता के लिए भी आवश्यक है. एक संपादक और संवाददाता को इतिहास रचने का सपना अवश्य देखना चाहिए. अगर वह यह सपना नहीं देखता, तो वह पत्रकारिता में कुछ नया नहीं कर सकता, केवल भीड़ में खड़ा अपना समय काट सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जम्मू-कश्मीर में जब बाढ़ आई और बाढ़ के बाद आंकड़ों के ऊपर बातचीत शुरू हुई कि कितनी मौतें हुई हैं, तो यह संख्या सिर्फ़ दो से सवा दो सौ के बीच पहुंची. कुछ लोग ढाई सौ कह रहे हैं, तो कुछ लोग तीन सौ. दरअसल, इसमें वह संख्या शामिल नहीं है, जो गांव की है. गांव के गांव साफ़ हो गए और अभी तक तो सरकार के सर्वे करने वाले भी यह अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि आख़िर सचमुच मौतें हुईं, तो कितनी हुईं? इन मौतों में बिहार से वहां जाकर काम करने वाले लोगों की संख्या शामिल नहीं है. बिहार के बहुत सारे लोग जम्मू-कश्मीर में विभिन्न जगहों पर काम करते हैं. वे अलग-अलग जगहों पर रहते हैं और उनकी परेशानी यह है कि उनमें आपस में कोई संपर्क-संबंध नहीं बन पाया और न उनका कोई संगठन वहां बन पाया. इसलिए वह कोई भी संख्या शामिल नहीं है. और, बिहार में जो लोग जम्मू-कश्मीर से वापस नहीं लौटे, उनकी आवाज़ भी सुनी नहीं जा रही है.

आपदा प्रबंधन देश की सबसे बड़ी ज़रूरत

नुक़सान अरबों में हुआ है या खरबों में, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि गोदामों में जो सामान भरा था, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया. ज़मीन के ऊपर, डेढ़ मंजिल तक सारा सामान नष्ट हो गया और उससे कहीं बढ़कर गोदामों में भरा सामान नष्ट हो गया, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में छह महीने के लिए यानी नवंबर से लेकर अगले मार्च-अप्रैल तक का सामान स्टॉक होता है. करेंसी कितनी नष्ट हुई, इसका कोई आंकड़ा बैंकों ने अब तक नहीं दिया है. विडंबना यह कि जो सहायता बाहर से जा रही है, वह जम्मू-कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहां पर स्वयंसेवी संस्थाओं या एनजीओ के नाम पर एक नया गोरखधंधा शुरू हो गया है. जो लोग सारी दुनिया से पैसा मांग रहे हैं, उनका जम्मू-कश्मीर में कोई अस्तित्व है या नहीं, किसी को नहीं मालूम. पैसा देने वाले अपने स्वभाव-वश पैसा दे रहे हैं, पर वह पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, सामान कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं है. कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है. यह हमारे देश की विडंबना है कि अचानक एक तबका खड़ा हो जाता है, जो दु:ख और दर्द के नाम पर भी लोगों को लूटता है, उनका शोषण करता है.

पर आज मैं इस भ्रष्टाचार की बात नहीं बताना चाहता हूं. मैं यह बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में और खासकर घाटी में संयुक्त परिवार प्रथा अभी भी चल रही है. एक ही घर में पूरे परिवार के लोग रहते हैं. जब बाढ़ आई, तो पहले लोग ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल पर चले गए और पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल पर चले गए. वहां के घरों में दूसरी मंजिल और छत के बीच एक और छोटी-सी मंजिल होती है, जहां लोग घुस गए. और, जब पानी वहां भी पहुंच गया, तो लोग छतों के ऊपर पहुंच गए. ये छतें टीन की होती हैं. सबने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और मिलजुल कर किसी को भी डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया. इसीलिए, कश्मीर घाटी में बाढ़ से मौतें कम हुईं. सामान की बर्बादी रोकी नहीं जा सकती थी, सामान लेकर भागा नहीं जा सकता था, क्योंकि पांच मिनट के भीतर पानी पहली मंजिल को छूने लगा था. कई ऐसी घटनाएं देखी गईं कि बाप बाहर गाड़ी में था, बेटा ऊपर की मंजिल में सामान, जिनमें रुपये-गहने हो सकते हैं, लेने के लिए गया था और इतनी ही देर में पानी इतनी तेजी से आया कि बेटे ने कहा, पिता जी, आप चले जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे. मैं तो ऊपर की मंजिल पर फंस गया हूं. बाप गाड़ी लेकर झेलम के बांध के ऊपर पहुंच गया. बेटा घर में बंद और बाप झेलम के बांध पर गाड़ी लेकर बेटे की सलामती की दुआ मांग रहा था. ऐसे बहुत सारे किस्से श्रीनगर घाटी में पता चले. इस संयुक्त परिवार प्रथा ने लोगों को ज़िंदा बचा लिया. एक रोटी में दस टुकड़े करके लोगों ने खाए. हमारा संवाददाता भी इस बाढ़ से बच गया.

लेकिन इस संवाददाता ने जो बताया, वह मेहमाननवाजी की मिसाल है. उसने बताया कि उसके घर में 18 लोग आ गए, जो बाढ़ के शिकार थे और जिनके घर का सब कुछ तबाह हो गया था. तीन-चार दिनों तक तो उसके घर में खाना-पीना चला. उसके बाद आए हुए मेहमानों ने उससे कहा कि हम अपना खाना अलग बनाएंगे, चूल्हा अलग करेंगे. इसके पीछे कारण यह था कि उस घर का सारा खाने का सामान ख़त्म हो रहा था. उन लोगों ने कहा कि अगर हम भी इसमें से खाएंगे, तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे. उनमें से किसी ने दाल खाकर, तो किसी ने चावल खाकर सात-आठ दिन निकाले. आख़िर के दो-तीन दिन बिल्कुल भूख में गुजरे, क्योंकि कुछ भी उपलब्ध नहीं था. बच्चों को दूध छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसी चीज उपलब्ध नहीं थी, जो ज़िंदा रहने का सहारा बने और यहीं पर संयुक्त परिवार प्रथा का सबसे सकारात्मक पहलू सामने आया कि एक रोटी के 6 और 8 टुकड़े करके लोगों ने आपस में बांटकर किसी तरीके से वे सात-आठ दिन निकाले.

जितनी चीजें हमने देखीं, उनमें जीने के लिए जितनी आवश्यक चीजें होती हैं, चाहे वह खाने का सामान हो, चाहे दवाइयां हों, चाहे पहनने-ओढ़ने के कपड़े हों यानी सब कुछ तबाह हो गया. जो लोग बाहर से श्रीनगर घूमने गए थे और जो होटलों में फंस गए थे, उनमें बहुत सारे ऐसे थे, जिनकी उम्र सत्तर साल से ऊपर थी, जो एक्यूड डायबिटीज के शिकार थे और इंसुलिन लेते थे, उनके पास दवाइयां ख़त्म हो गईं. कोई तरीका उनके पास दवाइयां पहुंचाने का नहीं था. मुझे दिल्ली में भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पत्नी ने बताया कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन करके कहा कि वहां पर उनके एक परिचित के पिता जी, जिनकी उम्र 80 साल है और जो इंसुलिन लेते हैं, वह फंस गए हैं. किसी तरह उनके पास इंसुलिन पहुंचा दीजिए. मेरा ख्याल है, मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर में तो पानी नहीं आया था, लेकिन वह ऐसी जगह पर थे, जहां पर किसी का किसी से संपर्क रहा ही नहीं था.

जम्मू-कश्मीर में पूरी संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी. जम्मू-कश्मीर की संचार व्यवस्था, जिसमें टेलीफोन प्रमुख है, सैटेलाइट से जुड़ी नहीं है, बल्कि ज़मीन के ऊपर की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और इस वजह से वहां अफ़वाहों का बाज़ार गर्म हो गया. रोज अफ़वाहें फैलती थीं कि आज वहां इतने मर गए, आज वहां इतने मर गए. किसी के पास उन्हें सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं बचा था. श्रीनगर रेडियो के लोगों ने अपना सामान उठाकर एक पहाड़ी पर लगा दिया और वहां से उन्होंने किसी भी तरीके से प्रसारण शुरू किया, लेकिन दूरदर्शन का प्रसारण तो आज तक शुरू नहीं हो पाया है. सिर्फ़ वे दो घंटे का प्रोग्राम किसी तरह बनाते हैं और वहां दिखाते हैं. संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह रेडियो का हो या दूरदर्शन का, तबाह हो गया. इन सारी स्थितियों में आपदा प्रबंधन सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारों की प्राथमिकताओं में सबसे कम प्राथमिकता वाला स्थान आपदा प्रबंधन को मिला हुआ है. वह चाहे उत्तराखंड की बाढ़ रही हो, चाहे कश्मीर की बाढ़ रही हो, कहीं भी आपदा प्रबंधन नामक चीज नहीं है. हमने अभी थोड़ी सफलता सिर्फ़ पाई है, तो तूफ़ान का सामना करने में, वह भी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि उसका तीन दिन पहले से पता चल गया था. इसलिए लोगों ने किसी तरीके से अपना गांव-घर छोड़कर शिविरों में रहकर अपनी जान बचाई. लेकिन, माल का नुक़सान वहां भी ज़्यादा हुआ, जान का कम हुआ.

पर आपदा उसे नहीं कहते हैं, जो सूचना देकर आती है. आपदा उसे कहते हैं, जो अचानक आती है, जैसे श्रीनगर में आई. सरकार चाहती, तो नुक़सान कम करा सकती थी, क्योंकि अनंतनाग से श्रीनगर तक आने में पानी को तीन दिनों का समय लगा, लेकिन सरकार ने इसे नज़रअंदाज किया. इसी तरह उत्तराखंड झील ऊपर बनी हुई थी, लेकिन वह फट सकती है, इसके ऊपर तत्कालीन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि पूरा का पूरा केदारनाथ बह गया. इसलिए हम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि आपदा प्रबंधन के काम को आप सबसे ज़्यादा तरजीह दें और उसमें ऐसे लोगों को लगाएं, जो सेवाभावी हों, जो किसी भी तरह से पीछे न हटें और जिनके पास पूरा नक्शा हो. श्रीनगर में आपदा प्रबंधन के नाम पर बाहर के लोग गए, जिन्हें श्रीनगर के रास्तों का ही पता नहीं था. और, राज्य सरकार ने उस आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों का सहयोग ही नहीं लिया, उन्हें शामिल नहीं किया. लिहाजा जिस कारगर तरीके से लोगों की मदद होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई, क्योंकि बाहर के लोगों को भूगोल या टोपोग्राफी का पता ही नहीं था.

श्रीनगर में पानी निकालने वाले पंप नहीं थे. ये सारी बातें हो गईं और हमने भुला दिया. हमें बड़े डिजास्टर के लिए तैयार रहना चाहिए, बड़ी आपदा के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए. अगर हम हर राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करें, तो देश की सबसे बड़ी संपत्ति यानी इंसान की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं. क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों या देश के प्रधानमंत्री के कानों तक हमारी यह साधारण-सी आवाज़ पहुंच कर उन्हें इस दिशा में कुछ करने के लिए प्रेरित कर पाएगी, हमें नहीं पता, लेकिन हम कामना अवश्य करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों के मुखियाओं के कानों तक यह आवाज़ पहुंचे और उन्हें आपदा प्रबंधन की महत्ता समझने की शक्ति मिले. ■

editor@chauthiduniya.com

मोदी सरकार को असाधारण बजट पेश करना होगा

मेघनाद देसाई

आदर्श रूप से मंत्रालयों को संतुलित या तर्कसंगत होना चाहिए. मंत्रिमंडल का आकार छोटा होना चाहिए. कुछ बड़े (सुपर) मंत्रालयों को छोड़कर शेष राज्य मंत्रालय होने चाहिए. कई विभाग बिल्कुल ग़ैर ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म करने का मतलब होगा कि बहुत सारे सांसदों को नाराज़ करना. इसलिए राजनीतिक मजबूरियों के कारण अयोग्यता को अभी भी झेलना पड़ेगा.

आजकल भारत और पाकिस्तान की राजनीति में एक अजीबोग़रीब समानता नज़र आ रही है. अगस्त महीने में इमरान खान ने अपने हज़ारों समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को अपदस्थ करने की कोशिश की. नवाज़ शरीफ संवैधानिक रूप से चुनकर नेशनल असेंबली में पहुंचे हैं. दरअसल, चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही इमरान खान नवाज़ शरीफ पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाते आ रहे हैं. इसके लिए उन्होंने कई बार समय सीमा भी निर्धारित की, लेकिन नवाज़ शरीफ उसे लगातार नज़रअंदाज़ करते रहे हैं. इमरान इतने स्वाभिमानी हैं कि वह अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकते और शरीफ इतने चतुर हैं कि वह यह स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने ग़लत तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की. अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस रस्साकशी का अंजाम क्या होता है. महाराष्ट्र की राजनीति में भी यही खेल दोहराया जा रहा है. उद्धव ठाकरे हठ कर रहे हैं कि भाजपा शिवसेना से बातचीत करे और उसकी मांगें मान ले. नरेंद्र मोदी शिष्ट तरीके से यह कह सकते थे कि शिवसेना को जानना चाहिए कि भिखारी अपनी शर्तों पर अपनी मांग पूरी नहीं करा सकता. लेकिन, यह कहने की बजाय उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श करने को तरजीह दी. महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया. विपक्षी विधायकों ने सदन के वेल में पहुंच कर हंगामा किया और राज्यपाल का घेराव कर राज्य में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया. यह राजनीति में सामान्य बात है.

मोदी के काम करने का अलग अंदाज़ अब उभर कर सामने आने लगा है. पहले उन्होंने एक अंतरिम कैबिनेट गठित कर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों तक इंतज़ार किया. इन चुनावों में पार्टी की जीत के बाद एक चुनाव जिताऊ नेता के रूप में अपनी छवि को मज़बूत करके उन्होंने भाजपा पर अपनी पकड़ और मज़बूत कर ली है. अब पार्टी में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है और न कोई ऐसा विपक्षी गुट है, जो उन्हें गंभीर चुनौती दे सके. अब उन्हें अपना ध्यान देश के विकास की स्व-निर्धारित नीति पर केंद्रित करना चाहिए. मोदी एक सतर्क राजनेता हैं. वह साहसी ज़रूर हैं, लेकिन जल्दबाज़ नहीं.

> यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि भारत में सरकारी विभागों का आकार ज़रूरत के मुताबिक क्यों नहीं तय किया जाता. कैबिनेट के बड़े आकार का मकसद देश में शासन व्यवस्था स्थापित करना नहीं होता, बल्कि मंत्रियों के लिए लालबत्ती की व्यवस्था करना या उनकी जेबें भरना होता है (ज़ाहिर है, इसमें सभी राजनीतिक दल शामिल हैं).

वह चाहते हैं कि उनका कार्यकाल यूपीए से अलग हो, लेकिन वह अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुंचा कर ऐसा कतई नहीं करना चाहते. वह केवल बदलाव के लिए बदलाव नहीं करेंगे. उनके कार्यकाल में सुधार की रफ्तार एक तय सीमा के अंदर रहेगी. इसका सीधा-सा मतलब यह है कि इसके लिए अचानक से किसी तरह का बड़ा आर्थिक सुधार नहीं किया जाएगा. ये सुधार यूपीए-1 के कार्यकाल के दौरान हासिल की गई 8.5 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखने तक सीमित रहेंगे. यानी नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी. वे लोग, जो भारत में एक मार्गरेट थैचर (ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश में क्रांतिकारी आर्थिक सुधार किए थे) को सत्ता में देखना चाहते थे, उन्हें फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा.

दरअसल, हमें यह याद रखना चाहिए कि थैचर ने साहसिक आर्थिक सुधार अपने दूसरे एवं तीसरे कार्यकाल में किए थे. अगर मोदी को अपनी नीतियां लागू करनी हैं, तो उन्हें दोबारा चुनकर आना होगा. यानी पहले राजनीति होगी, सुधार बाद में होगा. इसके अतिरिक्त, जो चुनौतियां सामने हैं, पहले उन्हें हल करना होगा. मोदी का मंत्रिमंडल पिछले सभी मंत्रिमंडलों जैसा ही बड़ा है. यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि भारत में सरकारी विभागों का आकार ज़रूरत के मुताबिक क्यों नहीं तय किया जाता. कैबिनेट के बड़े आकार का मकसद देश में शासन व्यवस्था स्थापित करना नहीं होता, बल्कि मंत्रियों के लिए लालबत्ती की व्यवस्था करना या उनकी जेबें भरना होता है (ज़ाहिर है, इसमें सभी राजनीतिक दल शामिल हैं). अगर अभी तक देखा जाए, तो मोदी सरकार का कामकाज पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही चल रहा है. मनोहर पार्रिकर को रक्षा मंत्री और शिवसेना से निष्कासित किए गए सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बनाना स्वागत योग्य है. इससे अरुण जेटली का बोझ कम होगा, जो अब तक दो बड़े मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे थे. हालांकि, उन्हें इस बार भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. हर्षवर्धन की स्वास्थ्य मंत्रालय से छुट्टी यह ज़ाहिर करती है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी. इस तरह बहुत दिनों बाद मिले एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री की सेवाओं से भारत वंचित रह गया.

आदर्श रूप से मंत्रालयों को संतुलित या तर्कसंगत होना चाहिए. मंत्रिमंडल का आकार छोटा होना चाहिए. कुछ बड़े (सुपर) मंत्रालयों को छोड़कर शेष राज्य मंत्रालय होने चाहिए. कई विभाग बिल्कुल ग़ैर ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म करने का मतलब होगा कि बहुत सारे सांसदों को नाराज़ करना. इसलिए राजनीतिक मजबूरियों के कारण अयोग्यता को अभी भी झेलना पड़ेगा. फिलहाल सरकार की सबसे बड़ी चिंता अर्थव्यवस्था की है. इसकी संभावना बहुत कम है कि जुलाई के बजट में घाटे को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे प्राप्त कर लिया जाएगा. यह चुनौती उसी समय से बनी हुई है, जब नई सरकार ने अंतरिम बजट को काम का आधार बनाया था. वह बजट नौकरशाहों द्वारा बनाया गया था, जिसमें पहले से ही बहुत सारी त्रुटियां थीं. अगर सरकार को अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखना है, तो उसे फरवरी में एक असाधारण बजट पेश करना होगा. इसके लिए सरकार के पास बहुत कम समय बचा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने एचआईवी पॉजटिव और एड्स रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिलों में एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है जहां रोगियों 1000 से अधिक एड्स रोगियों की पहचान की जा चुकी है. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण(एनएसीपी-2) के तहत नि:शुल्क एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी (एआरटी) की शुरूआत सबसे पहले उन छह राज्यों में की गई जहां एड्स के सबसे ज्यादा मामले देखने में आए थे. राजधानी दिल्ली सहित अन्य छह राज्यों में इसकी शुरूआत 1 अप्रैल, 2004 को की गई.

नर्स से जासूसी का सफर - एडिथ कावेल

चौथी दुनिया ब्यूरो

नवंबर 1914 में जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर अधिकार किए जाने के बाद कावेल ने ब्रिटिश सैनिकों को आश्रय देना शुरू कर दिया. वे इन सैनिकों को दबे छिपे अपने पास रखा करती थीं और कोशिश किया करती थीं कि जर्मन सैनिकों को इस बात की भनक भी न लगे. वे इन सैनिकों को नीदरलैंड पहुंचने में मदद कर रही थीं. न सिर्फ ब्रिटिश बल्कि कई देशों के सैनिकों को वे देश से बाहर निकलने में मदद कर रही थीं. सेनाओं से नजरें बचाकर वे इन सैनिकों को गाइड के जरिए बाहर भेजती रहीं. उनकी इन गतिविधियों को लेकर जर्मन सेना को उन पर शक हो गया था.

साहस की अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं. लेकिन जब हिटलर जैसा तानाशाह हो तो साहसी से साहसी व्यक्ति भी एक बार घबरा जरूर जाता है. महिला जासूसों के बारे में अपनी श्रृंखला के दौरान हमने आपको पहले भी ऐसी ही कुछ जासूसों के बारे में बताया है जो न सिर्फ युद्ध के मैदान में मजबूती से खड़ी हुईं बल्कि अपनी अक्लमंदी और सूझ-बूझ का लोहा भी मनवाया. इन्हीं साहसी महिलाओं में एक थीं एडिथ कावेल. जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान नर्स का काम करते हुए बहुत से सैनिकों की मदद की थी.

एडिथ कावेल एक ब्रिटिश नर्स थीं. उनका जन्म 4 दिसंबर 1865 को हुआ था. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने प्रयासों से लगभग दो सौ सैनिकों की जान बचाई थी. उन्होंने जर्मनी के अधिकार क्षेत्र वाले बेल्जियम से मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की भागने में मदद की थी. इस वजह से उन्हें बाद में गिरफतार कर लिया गया और उनपर मुक़दमा भी चलाया गया. उन पर केस चलाया गया जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई थी. इसके बावजूद उन पर मुकदमा चलाया गया मौत की सजा दी गई. इसके लिए जर्मनी की वैश्विक स्तर पर भर्त्सना की गई. एडिथ को उनके मशहूर वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था कि, सिर्फ देश भक्ति ही पर्याप्त नहीं है, के लिए भी याद किया जाता है. उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की रक्षा के लिए काम करना चाहिए. यही कारण था कि उन्होंने जर्मन और मित्र राष्ट्र दोनों के सैनिकों की मदद की. उनकी इसी ईसाई भावना के लिए हर साल चर्च में 12 अक्टूबर को उन्हें याद किया जाता है. एडिथ को बेल्जियम में उनकी नर्सिंग की बेहतरीन सेवाओं के लिए भी याद किया जाता है.

एडिथ का जन्म ब्रिटेन के शहर नॉरविच में हुआ था. उनके पिता 45 साल तक विकार(पादरी) के पद पर कार्यरत थे. वे चार भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं. उन्होंने लंदन अस्पताल से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी. इसके बाद उन्होंने देश के कई अस्पतालों में काम किया. 1907 में उन्हें डॉक्टर एंटोनी ने ब्रसेल्स के अस्पताल की सीनियर नर्स बनाया. इस पद को मैट्रन कहते हैं. उन्होंने बेल्जियम में नर्सिंग के पेशे को नई ऊंचाईयां प्रदान कीं. कुछ ही सालों के भीतर वे तीन अस्पतालों व 24 स्कूलों में नर्सिंग की शिक्षा दे रही थीं.

पहले विश्वयुद्ध की शुरूआत होने के बाद उनके अस्पताल को रेडक्रास संस्था ने ले लिया था. नवंबर 1914 में जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर अधिकार किए जाने के बाद कावेल ने ब्रिटिश सैनिकों को आश्रय देना शुरू कर दिया. वे इन सैनिकों को दबे छिपे अपने पास रखा करती थीं और कोशिश किया करती थीं कि जर्मन सैनिकों को इस बात की भनक भी न लगे. वे इन सैनिकों को नीदरलैंड पहुंचने में मदद कर रही थीं. न सिर्फ ब्रिटिश बल्कि कई देशों के सैनिकों को वे देश से बाहर निकलने में मदद कर रही थीं. सेनाओं से नजरें बचाकर वे इन सैनिकों को गाइड के जरिए बाहर भेजती रहीं. उनकी इन गतिविधियों को लेकर जर्मन सेना को उन पर शक हो गया था. सेना के उनपर शक का एक कारण यह भी था कि एडिथ बोलती ज्यादा थीं. उन्हें 3 अगस्त 1915 को मित्र राष्ट्र के सैनिकों की मदद के आरोप में गिरफतार कर लिया गया. उन्हें सैंट गाइल्सा जेल में रखा गया. उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा गया. इस दौरान उनकी जांच होती रही. जर्मन मिलिट्री किसी भी तौर पर यह नहीं चाहती थी कि एडिथ को जिंदा छोड़ा जाए. जांच के दौरान यह बात बताई गई कि एडिथ उन सैनिकों की न सिर्फ मदद की बल्कि उन्हें अपने घर में रखती थीं. उनके ऊपर मौत का खतरा मंडराने लगा था.

जब मुकदमे की शुरुआत हुई तो एडिथ ने इस बात को कोर्ट में कुबूल कर लिया कि उन्होंने सैनिकों की मदद की थी. उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की. उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि इन सारे सैनिकों ने ब्रिटेन में सुरक्षित रूप से पहुंचने पर उन्हें पत्र भी लिखे.

अब हालांकि जर्मनी के कानून के अनुसार तो उन्हें मौत की सजा ही दी जानी थी. लेकिन पहले जेनेवा कंवेंशन के हिसाब से साधारणत: किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी. ब्रिटेन ने उस समय अपने को असहाय बताते हुए मामले से अगल कर लिया था. विदेश कार्यालय के सर होरेस रॉलैंड ने कहा था कि मिस कावेल के साथ जो कुछ हो रहा है, वह काफी दु:खद है, लेकिन हम इस मामले कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हैं, हम असहाय हैं.

कई देशों ने एडिथ को बचाने के लिए माहौल बनाया लेकिन उनकी मौत करीब आ चुकी थी. एक नर्स होने के नाते मानवीय भावनाओं से ओत प्रोत होकर उन्होंने बहुत सारे सैनिकों की जानें बचाईं. उन्होंने अपने पेशे के साथ खिलवाड़ नहीं किया जब वे ब्रिटिश सैनिकों की मदद कर रही थीं ठीक उसी समय पर अगर कोई घायल जर्मन सैनिकों का इलाज भी कर रही थीं. वे उनका इलाज भी पूरी तनमयता के साथ करती थीं. उनका मानना था कि देश बाद में है, मानवता पहले है. शायद इसी वजह से उन्हें आज भी याद भी किया जा सकता है. आखिरकार जर्मनी ने सारे अंतरराष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए मौत के घाट उतार दिया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पर विशेष

एचआईवी के बाद भी जीवन संभव

मोनिशा भटनागर

एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो ह्युमन इम्युनो डिफिसिएंसी वायरस (एचआईवी) की वजह से होती है. एचआईवी के संक्रमण से मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है. यह वायरस मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इस हद तक कम कर देता है कि इसके बाद शरीर अन्य संक्रमणों से लड़ पाने में अक्षम हो जाता है. इसका मतलब यह की शरीर दूसरी बीमारियों के रोगाणुओं से नहीं लड़ पाता है. एक बार किसी बीमारी के होने के बाद उसे ठीक होने में लंबा वक्त लगता है. एचआईवी संक्रमण का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को एड्स हो गया है. एड्स के लक्षण दिखने में लंबा वक्त लगता है. यह व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है. कई बार एड्स के लक्षण दिखने में 8 से 10 साल भी लग जाते हैं. एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में एड्स की पुष्टि संभावित लक्षणों के दिखने पर चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद ही की जा सकती है. एचआईवी संक्रमित व्यक्ति टी-सेल्स की जांच की जाती है. इस टेस्ट को सीडी-4 काउंट टेस्ट कहते हैं. यदि रक्त में यह संख्या 350 से कम हो जाती है तो व्यक्ति के एचआईवी से संक्रमित होने की पुष्टि की जाती है.

अभी भी गांवो में रहने वाले 90 फीसदी लोग एचआईवी और एड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते. जरूरत इस बात की है कि सभी को यह बताया जाए कि एचआईवी/एड्स से बचने का एक मात्र रास्ता बचाव ही उपाय है. एचआईवी मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त को दूसरे रोगी को चढ़ाने, संक्रमित सुई का प्रयोग करने तथा ग्रसित मां से गर्भस्थ शिशु में प्रवेश करने से होता है. अभी तक एड्स की किसी दवा की खोज नहीं हुई है, पूरी दुनिया में इसके लिए प्रयास चल रहे हैं. साल 2013 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 21 लाख लोग एचआईवी से संक्रमित थे. एड्स की वजह से मरने वालों की संख्या 1.3 लाख थी. एड्स से बचने वालों की रोगियों की बढ़ती तादाद के कारण भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है.

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने एचआईवी पॉजटिव और एड्स रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिलों में एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है जहां रोगियों 1000 से अधिक एड्स रोगियों की पहचान की जा चुकी है. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण(एनएसीपी-2) के तहत नि:शुल्क एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी (एआरटी) की शुरूआत सबसे पहले उन छह राज्यों में की गई जहां एड्स के सबसे ज्यादा मामले देखने में आए थे. राजधानी दिल्ली सहित अन्य छह राज्यों में इसकी शुरूआत 1 अप्रैल, 2004 को की गई.

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी में बचाव की दवाईयां एचआईवी पॉजिटिव लोगों को दी जाती है. जो उनकी हालत में सुधार करने में मदद करता है और एचआईवी को एड्स में परिवर्तित होने से रोकता है. भारत में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जल्दी इलाज की शुरूआत होने से ये दवाएं न केवल एचआईवी को एड्स बनने से रोकती है बल्कि वायरस को और ज्यादा फैलने से भी रोकती हैं.

एड्स गर्भवती मां से गर्भ में पल रहे बच्चे को हो जाता है. लेकिन अफसोस की बात है. लोगों तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि एआरटी की मदद से मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को एड्स होने से बचाया जा सकता है. सरकार द्वारा एआरटी की शुरूआत करने के बाद भी लोगों को न तो इसके बार में पर्याप्त जानकारी है और न ही लोगों को उपचार मुहैया नहीं हो पा रहा है. दुनिया में एड्स रोगियों की संख्या के मामले में तीसरे पायदान पर होने के बावजूद भारत उन देशों में से एक बना हुआ है जहां कुल ज्ञात रोगियों में से केवल दस प्रतिशत को एआरटी उपलब्ध हो पा रही है. यहां दवा की कमी के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं. एआरटी का सही से पालन एवं क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है. इसके क्रियान्वयन में थोड़ी-सी भी चूक इसके प्रभाव को कम या खत्म कर सकती है. यह बाद में और ज्यादा घातक साबित हो सकती है.

एआरटी अगर समय से शुरू कर दी जाए तो एचआईवी के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है. परिणामस्वरूप शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे बढ़ने लगती है. बीमारी का बढ़ना बंद हो जाता है एवं अन्य संक्रमणों के शरीर में फैलने की आशंका भी घट जाती है. लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी एचआईवी/एड्स प्रभावित लोगों को एआरटी मुफ्त उपलब्ध की जाए. इसके अंतर्गत संक्रमित महिलाओं एवं बच्चों के उपचार के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं.

एआरटी केंद्र चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य सेवा, सहयोग व उपचार सेवाएं देने वाले संस्थानों में स्थित हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें. एचआईवी/एड्स से प्रभावित व्यक्ति इन केंद्रों पर जाकर उपचार एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं. यह केंद्र लोगों को सामुदायिक सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपचार से संबंधित सूचनाएं, जानकारियां एवं परामर्श सेवाएं भी देते हैं. एआरटी के प्रयोग में आने के बाद एड्स से मरने वालों की संख्या में कमी आई है. 2007 से 2011 के बीच एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में वार्षिक आधार पर 29 प्रतिशत की कमी आई है. ऐसा अनुमान है कि 2011 तक लगभग 1.5 लाख लोगों को एआरटी की मदद से बचाया जा चुका है. साल 2012 में भारत में नए एचआईवी संक्रमण के मामलों में कुल 57 प्रतिशत की कमी देखी गई है.

प्रीवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड सेंटर (पीपीटीसी)

एचआईवी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे पर होने वाले एड्स के खतरे को कम करने के लिए नाको ने ट्रिपल-एआरटी लागू की. इसके तहत देशभर में प्रीवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड सेंटर (पीपीटीसी) स्थापित किए गए. एचआईवी का मां से बच्चे का एचआईवी से ग्रसित होना संक्रमण के प्रमुख कारणों में से एक है. समय पर प्रसव पूर्व एचआईवी का पता न लग पाने के कारण 20.45 प्रतिशत नवजात बच्चों में एचआईवीसे पीड़ित हो जाते हैं. पीपीटीसीटीसी कार्यक्रम में गर्भवती मां से शिशु में एचआईवी के प्रवेश पर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य होता है. सरकार ने जच्चा-बच्चा की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं की एड्स की जांच अनिवार्य रूप से करने का प्रावधान किया गया है. गर्भावस्था के पहले महीने में ही यदि एचआईवी का पता चल जाए तो नौ महीने तक एआरटी देकर गर्भस्थ शिशु को संक्रमण से बचाया जा सकता है. यदि एचआईवी की पुष्टि दो महीने बाद हुई तब भी महिलाओं को इसे पूरे नौ महीने लेना होता है . वहीं प्रसव के बाद शिशु को भी एंटी रेट्रोवॉयल सीरप का डोज कुछ महीने के लिए दिया जाता है. एचआईवी से ग्रस्त सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए रेट्रोवायरल थेरेपी से मां से बच्चे में एचआईवी का संचरण रोकने में सहायता मिलती है. विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों को मां से मिलने वाले संक्रमण की गुंजाइश 10 फीसदी रहती है, लेकिन एआरटी से संक्रमण की गुंजाइश पांच फीसदी तक कम हो जाती है. साल 2013-14 में, 97 लाख गर्भवती महिलाओं में से 12000 गर्भवती महिलाओं को एचआईवी से संक्रमित पाया गया, जिनमें से 84 प्रतिशत महिलाओं को एचआईवी का मां से बच्चे को फैलने से रोकने के लिए एंटी रेट्रोवाइरल दवायें दी गईं.

एचआईवी/एड्स संबंधी मामलों में जागरूक बनें

लोगों को जागरूक करना एचआईवी के संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका है. लोगों को इसकी उत्पत्ति एवं प्रसार के बारे में बताने की जरूरत है ताकि लोग इस महामारी के दुष्प्रभाव से बचा जा सके. इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी. यद्यपि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसके बावजूद प्रभावित व्यक्ति भी सामान्य जीवन जी सकता है. एचआईवी संक्रमित होना जीवन का अंत नहीं हैं क्योंकि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति भी सही चिकित्सीय मदद एवं सही जीवन शैली अपना कर लंबे समय तक जीवन जी सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

जी-20 सम्मेलन के दौरान चीन और अमेरिका के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के संबंध में समझौता हुआ है. दोनों ही दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले देश हैं. समझौते के तहत अमेरिका 2025 तक वर्ष 2005 की तुलना में 26-28 प्रतिशत कार्बन कटौती करेगा, जबकि चीन 2030 तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने वाले ईंधन में जैविक ईंधन की 20 प्रतिशत की कटौती करेगा.

जी-20 सम्मेलन

भारतीय किसानों के लिए अच्छी ख़बर

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान और जी-20 देशों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत लौट आए हैं. वह अपने साथ देश के किसानों एवं ग़रीबों के लिए एक अच्छी ख़बर भी लाए हैं. भारत और अमेरिका ने भारतीय किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर गतिरोध दूर कर लिया है. अमेरिका ने खाद्यान्न के भंडारण के मुद्दे पर भारत के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है. अब इसे डब्ल्यूटीओ की आम परिषद में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जिससे व्यापार सुगमता करार पर हस्ताक्षर हो सकें. यह करार कई महीनों से अटका हुआ है. कई देशों को डब्ल्यूटीओ में भारत का दृष्टिकोण उचित लगा है. लंबे समय से डब्ल्यूटीओ के मसले पर कई मुद्दों को लेकर गतिरोध बना हुआ था. इस वजह से कई देश नाराज़ भी हुए, लेकिन भारत सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए. इस समझौते की राह में भारत का खाद्य सुरक्षा क़ानून और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का विवाद एक बड़ी बाधा था. इस मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ के 160 सदस्य देशों में से केवल क्यूबा, वेनेजुएला एवं बोलिविया भारत के पक्ष में थे. लेकिन, बाकी देशों के विरोध के बावजूद भारत अपनी मांग पर अड़ा रहा.

इससे पहले पर्यावरण के मुद्दे पर विकसित एवं विकासशील देशों के बीच इस तरह के मतभेद सामने आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारत ने डब्ल्यूटीओ की बैठक में अपने देश के ग़रीबों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए विकसित देशों के दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया और यह कहा कि भारत अपने देश के गरीबों एवं किसानों के हितों के ख़िलाफ़ किसी भी समझौते पर अपनी सहमति नहीं देगा. पहली बार भारत ने ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया था, जिससे 160 देशों के बीच के अंतरराष्ट्रीय संबंध और व्यापार प्रभावित होने वाले थे. ऐसा करके भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया था कि उसके लिए अपने किसानों-ग़रीबों का हित सर्वोपरि है, और वह उन्हें दरकिनार करके कोई समझौता नहीं करेगा. उनके हितों को सुनिश्चित करने के बाद ही व्यापार को बढ़ावा देने वाले किसी भी समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा.

इसके अलावा, भारत ने अपने रुख पर गंभीरता दिखाते हुए यह भी कहा था कि यदि उसकी ज़रूरतों को अनदेखा किया गया, तो वह डब्ल्यूटीओ की सदस्यता छोड़ सकता है. इसी मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तल्खी आ गई थी, जिसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भारत आए थे. भारत ने यह भी साफ़ कर दिया था कि वह व्यापार सुविधा समझौते (एफटीए) की तब तक पुष्टि नहीं करेगा, जब तक खाद्य सुरक्षा के मसले का कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता. बीते सितंबर महीने में मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इस मसले पर बात हुई थी. इसके बाद ब्रिस्बेन में जी-20 सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच फूड सब्सिडी को लेकर समझौता हो गया. इस पर खुशी जताते हुए डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर-जनरल रौबर्टो अजेवीडो ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते से अहम गतिरोध ख़त्म हो चुका है और अब जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बाली समझौता लागू किया जा सकता है.

पहली नज़र में तो यह विवाद ही अजीब लग सकता है कि आख़िर खाद्य सुरक्षा क़ानून की बात डब्ल्यूटीओ तक कैसे पहुंची? क्या खाद्य सुरक्षा का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बहुत अलग नहीं है? यह सवाल वाजिब है, पर समस्या यही है कि जब गैट के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमन के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, तो इसके नियमों का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया. विकासशील देशों की ऐसी नीतियां, खासकर सब्सिडी, जिसे अब तक घरेलू या राष्ट्रीय नीति की बात माना जाता था, वह भी अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों के अंतर्गत आने लगी. उस समय भी इस बदलाव का कई नागरिक संगठनों ने बहुत विरोध किया था, पर इस विषय को तब समुचित महत्त्व नहीं दिया गया. अब सरकार के सामने भी स्पष्ट हो रहा है कि इस वजह से कितनी नई समस्याएं पैदा हुई हैं. डब्ल्यूटीओ के नियम बताते हैं कि किस तरह की और कितनी सब्सिडी स्वीकार की जा सकती है और किस पर आपत्ति लग सकती है. यह अलग बात है कि ये नियम अब तर्कसंगत नहीं रह गए हैं, क्योंकि ये बहुत पहले की क़ीमतों पर आधारित हैं, जब विश्व बाज़ार में खाद्य क़ीमतें आज से बहुत कम थीं. जब भारत ने खाद्य सुरक्षा क़ानून बनाया, तो सस्ता अनाज प्राप्त करने वालों की संख्या काफी हद तक बढ़ाई गई. जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बिकने वाले अनाज की क़ीमत और कम की गई. इस तरह भारत की खाद्य सब्सिडी बढ़ गई और हमसे पहले कुछ विकसित देशों ने हिसाब लगाकर यह बता भी दिया. यह बात अलग है कि हिसाब ठीक से नहीं लगाया गया कि हम डब्ल्यूटीओ द्वारा तय सीमा पार कर रहे हैं.

> भारत अब तक बाली समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना इसलिए करता रहा, क्योंकि दिसंबर 2013 में इस बात का आश्वासन मिला था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सब्सिडी 2017 तक जारी रखी जाएगी, जिसके फलस्वरूप ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट करना था. अमेरिका और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) के प्रमुख समेत तमाम विकसित देश लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि कृषि एवं खाद्य सब्सिडी के मुद्दे पर भारत का अड़ियल रुख डब्ल्यूटीओ समझौते को पटरी से उतार रहा है.

डब्ल्यूटीओ में भारत की मांगें

- भारत मांग कर रहा था कि नए समझौते को अंतिम रूप डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा फूड सब्सिडी के नियमों में बदलाव को सहमति देने के बाद ही किया जाना चाहिए.
- सरकारों को फूड सब्सिडी की सीमा उत्पादन की लागत का 10 प्रतिशत ही रखनी है. यह लागत 1986-88 की क़ीमतों पर आधारित है. इसका आकलन वर्तमान क़ीमतों के आधार पर होना चाहिए.

भारत अब तक बाली समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना इसलिए करता रहा, क्योंकि दिसंबर 2013 में इस बात का आश्वासन मिला था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सब्सिडी 2017 तक जारी रखी जाएगी, जिसके फलस्वरूप ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट करना था. अमेरिका और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) के प्रमुख समेत तमाम विकसित देश लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि कृषि एवं खाद्य सब्सिडी के मुद्दे पर भारत का अड़ियल रुख डब्ल्यूटीओ समझौते को पटरी से उतार रहा है. भारत की जिद के चलते ही डब्ल्यूटीओ के प्रोटोकॉल के तहत ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट (टीएफए) 14 जुलाई की तय तिथि को लागू नहीं हो सका. अब इस बात को लेकर सहमति हुई है कि सब्सिडी की समय सीमा 2017 नहीं रहेगी. अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) की तरफ़ से जारी बयान में इसे ज़्यादा साफ़ किया गया है. कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी मुद्दे का स्थायी हल होने तक भारत को इस तरह की सब्सिडी से नहीं रोका जाएगा और न कोई इसके ख़िलाफ़ विवाद निस्तारण पैनल में जाएगा. हालांकि, पहले भारत इस मुद्दे पर 2017 तक मामला न उठाने की छूट देने वाले पीस क्लॉज पर सहमत हो गया था, लेकिन बाद में इसकी पेचीदगी ने सरकार को संकट में डाला और उसके बाद सख्त रुख अपनाया गया कि इस मुद्दे के स्थायी हल तक भारत टीएफए के लिए तैयार नहीं होगा. यहीं पर पेंच फंसा है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में कोई भी समझौता लागू करने के लिए हर सदस्य का सहमत होना ज़रूरी है. हालांकि, कई मामलों में हमने जिस तरह की नीतियां अपनानी शुरू की हैं, उनसे लगता है कि सरकारी खरीद और खाद्य सब्सिडी के मुद्दे पर हम बीच का रास्ता अपनाने जा रहे हैं. फिलहाल भारत सरकार इस शर्त पर सहमत हुई है कि जब तक इस मसले का कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक पीस क्लॉज अनिश्चित समय तक बढ़ा देना चाहिए. पीस क्लॉज के अंतर्गत विभिन्न देशों के खाद्य सुरक्षा क़ानूनों को जगह दी गई है. भारत अब पहले की तरह खाद्यान्न का संग्रहण एवं वितरण खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत करता रहेगा. भारत सरकार चाहती थी कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट बिना शर्त क्रियान्वित किया जाए.

जी-20 सम्मेलन के दौरान चीन और अमेरिका के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के संबंध में समझौता हुआ है. दोनों ही दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले देश हैं. समझौते के तहत अमेरिका 2025 तक वर्ष 2005 की तुलना में 26-28 प्रतिशत कार्बन कटौती करेगा, जबकि चीन 2030 तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने वाले ईंधन में जैविक ईंधन की 20 प्रतिशत की कटौती करेगा. इससे पहले यूरोपियन यूनियन 1990 के कार्बन उत्सर्जन स्तर पर 40 प्रतिशत की कटौती करने का ऐलान कर चुका है. मोदी दुनिया को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं. इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा. चीन अब कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के आधार पर भारत को निशाना बनाने की कोशिश करेगा. डब्ल्यूटीओ की तरह दूसरे विकसित देश पर्यावरण के मसले पर भी भारत के ऊपर दिसंबर में पेरू की राजधानी लीमा में होने वाली क्लाइमेट चेंज कांफ्रेंस से पहले दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

हालांकि, प्रधानमंत्री ने डब्ल्यूटीओ के जिस मसौदे के लिए सहमति जताई है, उसे उन्हें देश के सामने रखना चाहिए. इस मसले पर अंतिम फ़ैसला देश की संसद में हर पक्ष की बातें सुनकर होना चाहिए. हालांकि, सरकार किसानों और ग़रीबों के हितों की बात कर रही है, लेकिन दूसरे पक्षों की बातें सुनकर और देश को विश्वास में लेकर ही इस दिशा में कोई ठोस क़दम उठाना चाहिए. ऐसा करना ही देश के किसानों और गरीबों के हक़ में होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

आपका ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे. आपके श्री चरणों में हमारा बार-बार प्रणाम है. हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहियेगा, क्योंकि हमारे मन में सोते-जागते हर समय न जाने क्या-क्या संकल्प-विकल्प उठा करते हैं. आपके भजन में ही हमारा मन मग्न हो जाए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए. बाबा के भक्त सपटणेकर के पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया.

साईं बाबा कल्याण करते हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा सबके सदगुरू हैं, इसलिए हमें हमेशा उनके द्वारा कहे गए वचनों का अनुशरण करना चाहिए. गुरुकृपा की एक किरण ही भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दु:ख को सुख में परिवर्तित कर देती है. यदि सदगुरु के मोहविनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भवसागर के दु:खों का अन्त होकर जन्म-मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा. इसीलिये जो अपने कल्याणार्थ चिन्तित हों, उन्हें साई समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए. ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी.

साई बाबा सर्वमान्य हैं. वह भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं. सद्गुरु अपने भक्तों के सभी अवगुण दूर कर देते हैं. साई बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, बाबा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं. साई बाबा कहते हैं कि अपने अंदर हमेशा सकारात्मक विचारों को ही जगह देनी चाहिए. हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए. जो भी व्यक्ति साई बाबा की शरण में आता है, वह उनका भक्त बन जाता. अगर मनुष्य स्वच्छ मन से अपने गुरू में आस्था प्रकट करे, तो उसकी सब चिंताएं दूर हो जाती हैं. साई बाबा किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आइए जानते हैं

इस कथा के माध्यम से. साई बाबा के सपटणेकर नाम के एक भक्त थे, जो उनका दर्शन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वह बाबा का दर्शन नहीं कर पा रहे थे. वह इस बार साई के दर्शन के लिए बहुत धैर्य के साथ आए थे. उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण साई बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं. उन्होंने चरित्र सुधारने के लिए साई बाबा से एकांत में भेंट कर पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया. उन्होंने वैसा ही किया. उन्होंने अपना मस्तक साई के चरणों पर रख दिया और साई बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया. सपटणेकर बैठकर बाबा के पैर दबा ही रहे थे कि इतने में एक गड़ेरियन आई और बाबा की कमर दबाने लगी. वे हमेशा की तरह एक बनिए की कहानी सुनाने लगे. जब उन्होंने उसके जीवन के अनेक परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपटणेकर को बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा जो कहानी सुना रहे थे, वह उनके ही बारे में थी. उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उन्हें मेरे जीवन की हर बात कैसे पता है. अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा-पूरा रहस्य जानते है. यह विचार उनके मन में आया ही था कि गड़ेरिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपटणेकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है. क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण-हरण करता हूं. ये महानुभाव मस्जिद में आकर अब क्यों चीख-पुकार मचाते हैं. अब मैं एक काम करुंगा. अब मैं उसी बालक को फिर से उनकी पत्नी के गर्भ में डाल दूंगा. ऐसा कहकर बाबा ने अपना हाथ सपटणेकर के सिर पर रखा और उसे सान्त्वना देते हुए कहा कि यह चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है. जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे, तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी. सपटणेकर का हृदय गदगद हो उठा. तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवासस्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेघ आदि लेकर वे मस्जिद में आए. वे इसी प्रकार नित्य नैवेघ चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे. मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार-बार प्रणाम करते थे. एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक ही प्रणाम मेरे लिए पर्याप्त है. उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिया. जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को एक रुपया दूंगा. यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय एक रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा. फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्यराशि पर्याप्त होगी. जब उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा को एक रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर एक रुपया उनसे और मांगा. जब सपटणेकर ने उसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रख देना. उन्होंने वैसा ही किया और एक वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ. आठ माह का शिशु लेकर वह अपनी पत्नी के साथ फिर शिरडी आए और बाबा के चरणों में बालक को रखकर प्रर्थना करने लगे कि हे साई बाबा. आपका ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे. आपके श्री चरणों में हमारा बार-बार प्रणाम है. हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहियेगा, क्योंकि हमारे मन में सोते-जागते हर समय न जाने क्या-क्या संकल्प-विकल्प उठा करते हैं. आपके भजन में ही हमारा मन मग्न हो जाए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए. बाबा के भक्त सपटणेकर के पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया. बाद में उनको दो पुत्र और प्राप्त हुए. इस दंपति को अनुभव हुआ कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं निकले. साई बाबा के वचन सत्य हैं. वे अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए हैं? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

ज्ञान से भरा चौथी दुनिया

चौथी दुनिया दिनांक 03 नवंबर से 09 नवंबर 2014 अंक का मुख्य पृष्ठ बहुत आकर्षित किया. इस अंक के सभी पृष्ठ पर प्रकाशित खबरें रोचक हैं. खासकर नूर इनायत खान, फेफड़े का कैंसर, आफिया सिद्दकी पर लेख, भगवान भास्कर से लौकिक रिश्तों का पर्व हैं छठ, सफलता के लिए साधन की पहचान ज़रूरी एवं क्या टीम इंडिया(क्रिकेट) खिताब बचा पाएगी बहुत अच्छा लगा. चौथी दुनिया समाचार पत्र हमें केवल पांच रूपये में कई सारी जानकारियां एंव ताजा तरीन खबरें उपलब्ध कराता है, जो पांच रुपये से कई गुना अधिक की होती हैं. बहुत सारी जानकारियां देने वाले चौथी दुनिया समाचार पत्र के संपादक और प्रकाशक को कितना भी धन्यबाद दिया जाए वह कम होगा, फिर भी आप सभी(चौथी दुनिया परिवार) को कोटि-कोटि धन्यबाद.

-विनोद कुमार तिवारी, फारबिसगंज, बिहार.

सराहनीय आलेख

चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशति आलेख आईएसआईएस का भारत पर खतरा काफी तथ्यपकरक है. सभी समचार पत्रों में आईएसआईएस पर खबरें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन किसी भी समाचार पत्र ने इतनी अच्छी, तथ्यपूर्ण एवं विस्तार से जानकारी नहीं दी. चौथी दुनिया समाचार पत्र में सभी खबरें तथ्यों पर आधारित होती है और विस्तार से होती है. चौथी दुनिया समाचर पत्र में प्रकाशित यह खबर पढ़कर हम सभी को खुशी हुई.

-शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, सोनपुर, बिहार.

एकजुट होता जनता परिवार

कवर स्टोरी-मोदी के लिए नई चुनौती जनता परिवार(17 नवंबर-23 नवंबर 2014) पढ़ा तथ्यपरक है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि मोदी के लिए जनता परिवार नई चुनौती है. अगर यह परिवार फिर से एक हो जाए, तो संसद में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सकता है और भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को कड़ी चुनौती दे सकता है. कभी जनता परिवार में एक साथ रहे सभी नेता फिर एक बार मुलायम सिंह यादव के घर पर नजर आए, लेकिन सवाल यह है कि इस एकता के बीच में क्या एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई बाधा बनेगी या वर्चस्व को किनारे कर जनता परिवार मोदी को चुनौती दे सकेगा? भारतीय राजनीति में भाजपा का उभार और कांग्रेस की उदीसनता के लिए जरूरी है कि जनता परिवार एक साथ आए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, क्योंकि एक सशक्त सरकार के साथ एक सशक्त विपक्ष की भी जरूरत है और कांग्रेस अब इस हालत में नहीं है कि वो एक सशक्त विपक्ष विपक्ष की भूमिका निभा सके.

-रघुनाथ सिंह, बक्सर, बिहार.

निष्पक्ष समाचार पत्र

चौथी दुनिया सामाचार पत्र का मैं तीन वर्ष से पाठक हूं. चौथी दुनिया की कवर स्टोरी से लेकर सभी आलेख नई-नई घटनाओं पर आधारित होते हैं, जो इसे सबसे अलग बनाता है. चौथी दुनिया समाचार पत्र में साई की महिमा बहुत अच्छा लगता है. चौथी दुनिया की कवर स्टोरी मोदी के लिए नई चुनौती जनता परिवार, मनीष कुमार आलेख मोदी का आदर्श ग्राम, कमल मोरारका का आलेख एवं चौथी दुनिया के अंक(17 नवंबर-23 नवंबर 2014) में प्रकाशित सभी आलेख नई जानकारियों पर आधारित है. चौथी दुनिया एक निष्पक्ष समाचार पत्र है.

-अभिन्यु कुमार, शाहदरा, दिल्ली.

आदर्श ग्राम

आलेख-मोदी का आदर्श ग्राम (17 नवंबर-23 नवंबर 2014) पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है. मनीष कुमार का आदर्श ग्राम पर लिखा गया आलेख गांव के दर्द को बयां कर रहा है और बिल्कुल सही है कि गांवों में लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है. मोदी ने आदर्श ग्राम को लेकर जो बाते कहीं है उससे लोगों के मन एक आश जगी है, लेकिन कुछ शंकाए भी हैं. पहली शंका है कि मोदी ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के लिए सरकारी पैसा नहीं आएगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा विकास तो कैसे होगा. इसलिए मोदी को जनता को इस कंफ्यूजन से बाहर निकालना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके गांव का विकास किस प्रकार होगा. अगर मोदी आदर्श ग्रामों को आदर्श ग्राम पंचायती व्यवस्था के सहारे बनाना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि पंचायती व्यवस्था में आने वाले पैसे को उसके अधिकारी मिल-जुल कर हजम कर जाते हैं. इसलिए मोदी को आदर्श ग्राम का विकास किस प्रकार होगा उसका पूरा रोड मैप जनता के सामने रखना चाहिए.

-रविकांत चौरसिया, सीतापुर, उत्तर प्रदेश.

साजिश तो नहीं

जब तोप मुकाबिल हो-प्रधानमंत्री जी, अफ़वाहों पर तुरंत रोक लगाइए(17 नवंबर-23 नवंबर 2014) पढ़ा काफी तथ्यपरक है. संतोष भारतीय का हर आलेख और जब तोप मुकाबिल हो बेबाकी से लिखते हैं, उनका हर आलेख और संपादकीय हर नए विषय पर होता है. उन्होंने अपने संपादकीय में जिन अफवाहों की बात की है, वह बिल्कुल खतरनाक है और इस प्रकार लोगों के मन में एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा होगी, जो भविष्य में खतरनाक रूप धारण कर सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस पर रिपोर्ट मांगनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कौन लोग हैं जो ऐसी अफवाहें देश में फैला रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वो फेसबुक और वाट्सऐप के द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों पर रोक लगाए और उस पर नजर रखें कि कौन लोग हैं जो इस प्रकार काम कर रहे हैं. यह भी हो सकता है कि देश में अशांति फैलाने की एक साजिश हो, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस तरह की फैलाई जा रही गलत अफवाहों पर रोक लगाए.

-आलोक तिवारी, पटना, बिहार.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें : चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

एक महर्षि

एक महर्षि थे. उनका नाम था कणाद. किसान जब अपना खेत काट लेते थे तो उसके बाद जो अन्न-कण पड़े रह जाते थे, उन्हें बिन करके वो अपना जीवन चलाते थे. इसी से उनका यह नाम पड़ गया था. उन जैसा दरिद्र कौन होगा इसलिए जब देश के राजा को उनके कष्ट का पता चला तो उसने बहुत-सा पैसा लेकर अपने मंत्री को उनके पास भेजा. मंत्री पहुंचा तो महर्षि ने कहा, मैं ठीक हूं. इस धन-दौलत को तुम उन लोगों में बांट दो, जिन्हें इसकी जरूरत है.

इस तरह राजा ने तीन बार अपने मंत्री को भेजा और तीनों बार महर्षि ने कुछ भी लेने से मना कर दिया. आखिर में राजा खुद उनके पास गया.

वह अपने साथ बहुत-सा पैसा ले गया. उसने महर्षि से इसे स्वीकार करने की प्रार्थना की, किन्तु वह बोले, उन्हें दे दो, जिनके पास कुछ नहीं है. मेरे पास तो सब कुछ है. राजा को आश्चर्य हुआ. जिसके तन पर एक लंगोटी मात्र है, वह कह रहा है कि उसके पास सब कुछ है. उसने लौटकर पूरी कहानी अपनी रानी से कही. वह बोली, आपने भूल की. ऐसे साधु के पास कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए जाना चाहिए.

राजा उसी रात महर्षि के पास गए और माफी मांगी. कणाद ने कहा, गरीब कौन है? मुझे देखो और अपने को देखो. बाहर नहीं, भीतर. मैं कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहता. इसलिए अचानक ही सम्राट हो गया हूं. एक धन-दौलत बाहर है और एक भीतर है. जो बाहर है वह आज या कल छिन ही जाती है. इसलिए जो जानते हैं, वो उसे सम्पदा नहीं, विपदा मानते हैं. जो भीतर है, वह मिलती है तो खोती नहीं. उसे पाने पर फिर कुछ भी पाने को नहीं रह जाता. ■

शिक्षा-जो भी पास हो उसी में खुश रहना चाहिए.

नागपुर इस गांव से बीस मील की दूरी पर था. चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई. यह उसकी भतीजी का नाम था. उसके आने से झोंपड़े में जान–सी पड़ गई. मगन दास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी, उसका रंभा से कोई मेल न था. वह सौंदर्य नामक चीज का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत, जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा था.

बेबाक ज़िंदगी, बिंदास अदा

अनंत विजय

हाल में वहीदा रहमान की जीवनी–कनवर्सेशन विद वहीदा और दिलीप कुमार की आत्मकथा–दिलीप कुमार : दे सब्सटेंश एंड द शैडो प्रकाशित होकर आई हैं. वहीदा की किताब में भी कुछ खास नहीं है और दिलीप कुमार की आत्मकथा तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट है. दिलीप कुमार की आत्मकथा में उनके दौर की नायिकाओं के साथ उनके संबंधों के बारे में विवादित एवं अप्रिय प्रसंगों की तो चर्चा नहीं ही है, प्रिय एवं प्रेम प्रसंगों पर भी खामोशी है. सितारों की जीवनियों और आत्मकथाओं की इसी कड़ी में हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सितारों में से एक नसीरुद्दीन शाह ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है– एंड देन वन डे, अ मेमॉयर. लगभग तीन सौ पृष्ठों की इस किताब के लिखे जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है. फिल्म की शूटिंग के दौरान बोरियत से बचने के लिए नसीरुद्दीन शाह ने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी. संयोग से उसी वक्त उन्होंने लैपटॉप खरीदा और उसे चलाना भी सीखा था. बोरियत से बचने के लिए जब अपनी कहानी लिखने लगे, तो फिर एक सिलसिला चल पड़ा. कई बार तो लिखने और पेनड्राइव में सेव करने के चक्कर में कई–कई पन्ने उड़ गए, जिन्हें फिर से लिखा. अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को लिखकर सहेजते रहे.

एक दिन नसीर ने अपना लिखा हुआ अपने मित्र रामचंद्र गुहा को पढ़ने को दिया. गुहा मशहूर लेखक एवं इतिहासकार हैं. गुहा ने जब नसीर की अधूरी कहानी पढ़ी, तो उन्होंने नसीर को अपनी यह आत्मकथा पूरी करने के लिए प्रेरित किया और दबाव भी बनाया. इस तरह यह किताब सामने आ सकी. नसीरुद्दीन शाह की इस किताब में एक खास बात है, वह है ईमानदार लेखन. आम तौर पर आत्मकथाओं में अपने आपको हीरो साबित करने की एक ललक दिखाई देती है, अपने संघर्षों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश करने की कोशिश दिखाई देती है, अपनी मुफलिसी के दिनों को शहीदाना अंदाज़ में पेश करने की जुगत भी रेखांकित की जा सकती है. लेकिन, नसीर ने अपनी इस किताब में इन तमाम कोशिशों एवं जुगतों का इस्तेमाल नहीं किया और बिल्कुल ही ईमानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को पाठकों के सामने पेश कर दिया. इस ईमानदारी को कई आलोचक रूखा और मुंहफट करार दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नसीर ने ज़िंदगी के कच्चे यथार्थ को बगैर किसी रंग–रोगन के पेश किया है.

नसीर ने जिस बेबाकी से लिखा है, उससे बहुधा यह भ्रम पैदा होता है कि वह लिखते–लिखते असभ्य हो जाते हैं. अगर देखा जाए, तो इस किताब में हिट मसाला फिल्म के सारे फॉर्मूले यानी ड्रामा, एक्शन एवं रोमांस आदि हैं, लेकिन किताब पढ़ते वक्त ये सारे प्रसंग बेहद सहजता से सामने आते हैं. नसीरुद्दीन शाह के अपने पिता से रिश्ते बेहतर नहीं थे. नसीर के पिता प्रशासनिक अधिकारी थे, लिहाजा नियमित अंतराल पर उनका तबादला होता रहता था. नसीर अपनी अम्मी के बेहद क़रीब थे और बचपन की पूरी कहानी में अम्मी या फिर उनकी याद बार–बार आती है. अपनी अम्मी के दुपट्टे के कोने और उसकी खुशबू को नसीर अपनी सबसे बड़ी थाती मानते थे. पिता को लेकर नसीर के मन में हमेशा से एक विद्रोह का भाव रहा है, चाहे वह सरधाना का प्रसंग रहा हो या फिर उनके

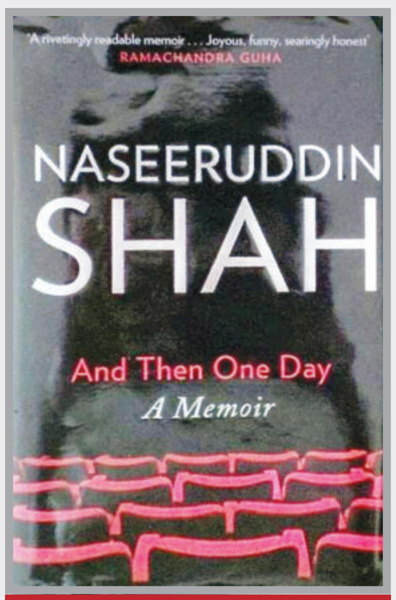

समीक्ष्य कृति : एंड देन वन डे
लेखक : नसीरुद्दीन शाह
प्रकाशक : पेंग्विन बुक्स, नई दिल्ली
मूल्य : 699 रुपये

पढ़ाई में कमजोर होने के बाद घर के माहौल का चित्रण हो. नसीर जब नवीं कक्षा में फेल हो जाते हैं, तो उनके पिता खफा होते हैं. जायज भी था. उनके पिता तो इस बात पर भी बुरी तरह से खफा हो जाते हैं कि नसीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई से ज़्यादा रंगकर्म को तवज्जो देते हैं. हर मां–बाप की तरह नसीर के पिता की भी इच्छा थी कि वह आला सरकारी मुलाजिम बनें.

नसीर ने इस किताब में लिखा है कि जब वह बाप बने, तो उन्हे पिता की आकांक्षाओं एवं उम्मीदों का एहसास हुआ. इस बात के संकेत कई जगह हैं कि नसीर अपने पिता से दूर ही रहना चाहते थे, लेकिन जब वह अपने पिता की मौत के बाद उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सके, तो नसीर का दर्द भी छलक आता है. यह पूरा प्रसंग पाठकों को उस दर्द का एहसास कराता है. नसीर ने खुलकर इस बात को स्वीकारा है कि उन्हें अपनी पहली पत्नी से पैदा हुई बेटी हबीबा से बारह वर्षों तक अलग रहने का खासा अफ़सोस है. दरअसल, उन्नीस साल की उम्र में ही नसीर ने अपने से क़रीब पंद्रह साल बड़ी पाकिस्तानी महिला पुरवीन से शादी कर ली थी. पुरवीन उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डॉक्टरी पढ़ रही थीं. नसीर उस वक्त रंगकर्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते थे और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी, जो पुरवीन ने उन्हें दिया. दोनों के बीच यह रिश्ता लंबा नहीं चल सका. शादी के दस महीने के अंदर पुरवीन ने नसीर की बेटी को जन्म दिया. इस बीच नसीर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली पहुंच गए.

> **अभिनय के इसी सूत्र के वर्णन को देखते हुए कहा जा सकता है कि नसीरुद्दीन शाह की यह किताब अभिनय की दुनिया में क़दम रखने वालों को अवश्य देखनी चाहिए. अभिनय के बाद हर पृष्ठ पर आप लेखक की बेबाकी से भी रूबरू होते हैं. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट तक में गांजा और नशे को लेकर नसीर ने अपनी ज़िंदगी के वे सारे पन्ने खोल दिए हैं, जिन्हें लेकर आम तौर पर सामान्य आदमी भी घबराता है.**

नसीर ने माना है कि उस दौर में वह बेहद असुरक्षित महसूस करते थे, जिस वजह से उनका यह रिश्ता लंबा नहीं चल पाया. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचने के बाद नसीर को शादी और बच्चा, दोनों बोझ लगने लगे थे, लिहाजा उन्होंने पुरवीन से दूरी बनानी शुरू कर दी. नसीर को लगता था कि उनके करियर में शादी और बच्चे, दोनों बाधा हो सकते हैं. नसीर का यह रुख उनके व्यवहार में भी दिखने लगा था, जिसकी परिणति दोनों के अलगाव में होती है. थोड़े ही समय बाद पुरवीन अपनी बच्ची को लेकर लंदन चली गईं और फिर नसीर बारह वर्षों तक उससे नहीं मिल सके. नसीर ने बेटी से अलग रहने की जो कहानी लिखी है, उस कसक को महसूस करने के लिए आत्मकथा के उन पृष्ठों से गुजरना आवश्यक है, जहां नसीर ने इस पर विस्तार से लिखा है. नसीर की इस कहानी में एक और सूत्र है, जो पूरी किताब को पिरोता है. वह है, हर पृष्ठ पर किसी न किसी रूप में अभिनय की चर्चा. अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने साफ़ लिखा है कि अभिनय या ड्रामा ही उन्हें अपना–सा लगता था और हमेशा यह महसूस होता था कि इसी क्षेत्र में वह कुछ कर सकते हैं.

अभिनय के इसी सूत्र के वर्णन को देखते हुए कहा जा सकता है कि नसीरुद्दीन शाह की यह किताब अभिनय की दुनिया में क़दम रखने वालों को अवश्य देखनी चाहिए. अभिनय के बाद हर पृष्ठ पर आप लेखक की बेबाकी से भी रूबरू होते हैं. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट तक में गांजा और नशे को लेकर नसीर ने अपनी ज़िंदगी के वे सारे पन्ने खोल दिए हैं, जिन्हें लेकर आम तौर पर सामान्य आदमी भी घबराता है. नसीर ने इस किताब में अपने समकालीन कलाकारों पर भी टिप्पणी की है और एनएसडी एवं फिल्म इंस्टीट्यूट के दौर को बेहद जीवंतता से जिया है. उनकी ज़िंदगी में ओमपुरी के अलावा जसपाल भी उनका खास दोस्त था. जसपाल ने किस तरह नसीर का भरोसा तोड़ने की कोशिश की, उस पर भी बेबाकी से लिखा गया है. नसीर और रत्ना पाठक का प्यार पहली नज़र का प्यार है. एक दिन वह सड़क के किनारे गन्ने के रस की दुकान पर सत्यदेव दुबे से बातें कर रहे थे, वहीं उन्होंने रत्ना को देखा था. उस दौर में नसीर तन्हाई भी झेल रहे थे, लिहाजा प्यार को परवान चढ़ते देर नहीं लगी. नसीर ने अपनी इस किताब में रत्ना पाठक को लेकर कई बेहद दिलचस्प टिप्पणियां की हैं. उन्होंने लिखा कि रत्ना एक मजबूत स्त्री है, जिसने उन्हें कई बार संभाला. नसीर की यह किताब पढ़ने के बाद कहा जा सकता है कि काफी दिनों के बाद एक ईमानदार आत्मकथा पाठकों के सामने आई है. इसके पहले विनोद मेहता ने अपनी आत्मकथा–लखनऊ ब्वॉय में इसी तरह का ईमानदार लेखन किया था. लेकिन नसीर की यह आत्मकथा उनकी उम्र के चालीसवें वसंत पर आकर ख़त्म हो जाती है. उम्मीद की जानी चाहिए कि नसीरुद्दीन शाह अपनी इस अधूरी आत्मकथा को अवश्य पूरा करेंगे. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

प्रेमचंद

त्रिया चरित्र

पिछली बार आपने पढ़ा कि सेठ लगन दास के घर बरसों बाद एक बालक के जन्म ने उनके द्वारा पूर्व में गोद लिए गए बालक मगन दास, जो अब जवान हो चुका था और जिसका विवाह एक नामी सेठ की बेटी से हो चुका था, की सारी हसरतों पर पानी फेर दिया. सैर करने विदेश निकला मगन दास यह ख़बर पाने के बावजूद घर वापस नहीं लौटा. चलते–चलते एक दिन वह अपनी पत्नी के शहर में जा पहुंचा और अनजाने ही उसके बाग में, जहां की मालिन ने उसे उसकी पत्नी का हाल कह सुनाया, जो मगन दास से सर्वथा अपरिचित थी. सारी बातें सुनने के बाद मगन दास ने कहीं और ठिकाना तलाशने का मन बनाया. फिर क्या हुआ? पढ़िए, कहानी के इस हिस्से में...

नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता समाप्त की. यह एक बड़ा गांव था. पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थीं. कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था. इस वक्त प्लेग के बचे–खुचे वे लोग गांव के नौजवान एवं शौकीन जमींदार साहब और हल्के के रोबीले थानेदार साहब थे. उनकी मिली–जुली कोशिशों से गांव मे सतयुग का राज था. धन–दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे. उसे गुनाह की तरह छिपाते थे. घर–घर में रुपये रहते हुए लोग कर्ज ले–लेकर खाते और फटेहाल रहते थे. इसी में निबाह था. काजल की कोठरी थी, सफेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था. हुकूमत और जबर्दस्ती का बाज़ार गर्म था. अहीरों के यहां आंजन के लिए भी दूध न था. थाने में दूध की नदी बहती थी. मवेशी खाने के मुहर्रिर दूध की कुल्लियां करते थे. इसी अंधेर नगरी को मगन दास ने अपना घर बनाया. ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था. इसी झोंपड़ी में वह एक हफ्ते से ज़िंदगी के दिन काट रहा है. उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं. मगर ऐसा मालूम होता है कि उसे अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही. ज़िंदा है, मगर ज़िंदगी रुखसत हो गई है. हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है. टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत नहीं, हिमाकत का काम है.

एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था. एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी. मगन दास को आवाज़ परिचित जान पड़ी. बाहर आकर देखा, तो वही चंपा मालिन थी. कपड़े तार–तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर. बोला, मालिन, तुम्हारी यह क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंककर देखा और पहचान गई. रोकर बोली, बेटा, अब बताओ मेरा कहां ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना–बनाया घर उजाड़ दिया. न उस दिन तुमसे बात करती, न मुझ पर यह बिपत पड़ती. बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनीं. सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी, नाक कटवा लूंगी, मुंह में कालिख लगवा दूंगी, चुड़ैल, कुटनी, तू मेरी बात किसी ग़ैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा क्यों करे? वह क्या तेरा दामाद था, जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया, बकती रही. मुझसे भी न सहा गया, रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी! बोली, बाई जी, मुझसे कुसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूं. छींकते नाक कटती है, तो मेरा निबाह यहां न होगा. ईश्वर ने मुंह दिया है, तो आहार भी देगा. चार घर से मांग लूंगी, तो मेरे पेट को हो जाएगा. उस छोकरी ने मुझे खड़े–खड़े निकलवा दिया.

बताओ, मैंने तुमसे उसकी कौन–सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी. मगर, बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है. अब बताओ, मैं किसकी होकर रहूं? आठ दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं. एक भतीजी उन्हीं के यहां लौंडियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया. तुम्हारी बदौलत, जो कभी न किया था, वह करना पड़ा. तुम्हें

काहे का दोष लगाऊं, किस्मत में जो कुछ लिखा था, देखना पड़ा. मगन दास सन्नाटे में था, आह, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान! उसने मालिन को भरोसा दिलाया कि अगर उसके पास दौलत होती, तो वह उसे मालामाल कर देता. सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है. बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो. अकेले मेरा जी भी नहीं लगता. सच कहो, तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी. अच्छा हुआ तुम आ गईं. मालिन ने आंचल फैलाकर आशीष दिया, बेटा तुम जुग–जुग जियो, बड़ी उम्र हो. यहां कोई घर मिले, तो मुझे दिलवा दो. मैं यहां रहूंगी, तो मेरी भतीजी कहां जाएगी, वह बेचारी शहर में किसके आसरे रहेगी? मगन लाल के खून में जोश आया. उसके स्वाभिमान को चोट लगी कि उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है, उनकी इस आवारागर्दी के लिए ज़िम्मेदार मैं हूं. बोला, कोई हर्ज न हो, तो उसे भी यहीं ले आओ. मैं दिन को यहां बहुत कम रहता हूं. रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ रहा करूंगा. मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ़ न होगी. यहां दूसरा मकान मिलना मुश्किल है. यही झोंपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है. यह अंधेर नगरी है. जब तुम्हारी सुभीता कहीं लग जाए, तो चली जाना. मगन दास को क्या मालूम था कि हजरत–ए–इश्क उसकी ज़ुबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं. क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है?

नागपुर इस गांव से बीस मील की दूरी पर था. चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई. यह उसकी भतीजी का नाम था. उसके आने से झोंपड़े में जान–सी पड़ गई. मगन दास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी, उसका रंभा से कोई मेल न था. वह सौंदर्य नामक चीज का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत, जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा था. उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी एवं गंभीर शान के साथ चमक रहा था. सुबह का वक्त था. मगन दास दरवाजे पर पड़ा ठंडी–ठंडी हवा का मजा उठा रहा था. रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली. मगन दास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा. ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा आंखों में गंभीर सरलता. मगन दास को उसने भी देखा. चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई. प्रेम ने पहला वार किया. मगन दास सोचने लगा, क्या तकदीर यहां कोई और गुल खिलाने वाली है! क्या दिल मुझे यहां भी चैन न लेने देगा? रंभा तू यहां नाहक आई, नाहक एक ग़रीब का खून तेरे सिर पर होगा. मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, दिल का सौदा सोच–समझ कर करना चाहिए. तुम्हें अभी जब्त करना होगा. रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती. तुम्हें क्या ख़बर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं? कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों की दिलबस्तगी के लिए कुछ चाहिए, तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है, जरा संभल कर क़दम रखना. पेशेवर जातियों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है. ■

..क्रमशः

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

कंपनी के अनुसार इससे स्मार्टफोन फोटोग्राफी की क्वालिटी और बेहतर बनाई जा सकेगी. इस सेंसर में जो इमेज फेस डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा में इस्तेमाल की जाती है. इसी के साथ एचडीआर इमेजिंग तकनीक ना सिर्फ 4के वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करती है बल्कि स्टिल इमेज में भी बेहतर क्वालिटी देती है. कंपनी के अनुसार नए इमेज फेस डिटेक्शन से यूजर्स क्विक मूविंग सब्जेक्ट (तेजी से चलने वाली वस्तुएं) जैसे बच्चों की फोटो, भागते हुए जानवरों की फोटो, एथलीट्स की फोटोज खींची जा सकती हैं.

ऐप बताएगा ब्रांडेड कपड़ा असली है या नहीं

हम सभी कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि यह ब्रांडेड है या नहीं, केवल कपड़े पर ब्रांड का नाम लिखा है या ब्रांडेड है भी. अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अब आप ऐप के जरिए पता लगा सकते हैं कि आपका कपड़ा ब्रांडेड है या नहीं. जापानी कंपनी नेक (NEC) कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसकी मदद से आप नकली कपड़े की पहचान कर सकते हैं. यह ऐप क्लोजअप फोटो की सहायता से नकली कपड़ों का पता लगाएगा. आपको बता दें कि जैसे हमारे फिंगर प्रिंट का एक पैटर्न होता है, ठीक उसी तरह ब्रांडेड कपड़ों पर भी एक खास पैटर्न होता है. क्लोज अप फोटो की मदद से ऐप में मौजूद एक खास रिकग्निशन सिस्टम नकली पैटर्न को पहचान लेगा. नेक ने बताया कि कई बड़े ब्रांडों ने इस ऐप में दिलचस्पी दिखाई है. इस ऐप की मदद से ब्रांडेड कपड़ों से टैग और प्लास्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

टू-इन-वन टैबलेट

स्वाइप ने स्वाइप अल्टीमेट नाम से टैबलेट कम लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसे आप लैपटॉप और टैबलेट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 10.1 इंच मल्टी टच आईपीएस डिस्प्ले स्क्रीन दिया गया है साथ ही इसमें जीरो गैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इस डिवाइस में मैग्नेटिक डिअटैचबल की-बोर्ड भी है. इसमें इंटेल एटॉम जेड3735डी, 1.33 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर लगा है और 2 जीबी की रैम टैबलेट को शानदार स्पीड देती है. इस टैबलेट में 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है और यह माइक्रो-यूएसबी स्लॉट की मदद से 1 टेराबाइट तक की एक्सटर्नल हार्डड्राइव को सपोर्ट करता है. यही नहीं टैबलेट के साथ एक साल का मुफ्त लाइसेंस युक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आता है. इस टैबलेट में 5 मेगापिक्सल का रियर और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है. कनेक्टिविटी की बात करें, तो तरह इस्तेमाल वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, माइक्रो एचडीएमआई पोर्ट और माइक्रो यूएसबी स्लॉट भी है. यही नहीं डोंगल की मदद से आप इस टैबलेट में 3जी का भी लुत्फ ले सकते हैं. टैबलेट कम लैपटॉप में लैपटॉप की तरह काम करने के लिए भारी भरकम बैटरी भी दी गई है, ताकि आपको कभी भी बैटरी की कमी महसूस ना हो. इसमें 8000 एमएएच की बैटरी लगी है. इसकी कीमत 19,000 रुपये है. ■

मोबाइल प्रिंट करेगा सेल्फी

एक विदेशी कंपनी स्मार्टफोन के लिए ऐसा कवर बना रही है, जो कुछ ही सेकेंड में ही आपके फोन पर खींची गई सेल्फी को प्रिंट कर देगा. प्रिंट नाम की कंपनी ने यह स्मार्टफोन केस बनाया है जिसके भीतर ही प्रिंटर भी है. यह मोबाइल कवर स्मार्टफोन से ब्लूटूथ से अटैच रहेगा और तकरीबन 50 सेकेंड में फोटो प्रिंट कर देगा. इस प्रिंटर वाले कवर को बनाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही फोटो को प्रिंट करने का समय घटाकर 30 सेकंड कर दिया जाएगा. फिलहाल इस कवर में पेपर की 1 शीट ही आती है और

एक बार में एक फोटो ही प्रिंट हो पा रही है लेकिन जल्द ही इसकी क्षमता बढ़ाकर 30 शीट तक कर दी जाएगी. प्रिंट कंपनी इस स्मार्टफोन कवर पर पिछले एक साल से काम कर रही है और अगले साल जनवरी तक इसे बाजार में उतार देगी. यह कवर अभी 4 इंच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है, लेकिन कंपनी जल्द ही बड़े साइज के स्मार्टफोन के लिए भी प्रिंटर वाले कवर बनाने जा रही है. इसकी कीमत लगभग 6,000 रुपये रखी गई है. ■

मित्सुबिशी ने लॉन्च की पजेरो स्पोर्ट्स ऑटोमैटिक

जापान की जानी मानी कंपनी मित्सुबिशी ने भारत में अपना पजेरो स्पोर्ट्स ऑटोमैटिक एडिशन को नए फीचर्स के साथ लॉन्च कर दिया है. पजेरो के इस एडिशन को कंपनी ने टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन, रियर व्यू कैमरा, स्पोर्टी रियर स्पॉयलर, बॉडी कलर बंपर मड गार्ड जैसे नए फीचर के साथ लॉन्च किया है. 2.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो इंजन वाली ये कार 176 बीएचपी की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करती है. कार 4x4 फीचर में भी उपलब्ध है, जिसे जरूरत के हिसाब से 4x2 भी किया जा सकता है. 4x4 फीचर ड्राइव में ये कार 3 अलग-अलग मॉडल्स में मौजूद है. इसका स्टीयरिंग लैदर से कवर है, जिस पर ऑडियो कंट्रोल भी उपलब्ध हैं. पजेरो में स्पेस की दिक्कत कभी नहीं रही थी और इस ऑटोमैटिक वैरिएंट में भी इसकी कोई कमी नहीं है, भले ही बात पैरों के पास के स्पेस की करें या फिर गाड़ी की छत की हो. गाड़ी की तीसरी लाइन की सीटों को फोल्ड किया जा सकता है, जिससे सामान रखने के स्पेस को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलती है. इसकी कीमत लगभग 23.55 लाख रुपये है. ■

स्मार्टफोन में मिलेगी डीएसएलआर जैसी क्वालिटी

सोनी ने अपना नया स्मार्टफोन कैमरा सेंसर आईएमएक्स 230 लॉन्च किया है. इस कैमरा सेंसर की मदद से 21 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन वाली फोटो खींची जा सकती है. कंपनी ने इस सेंसर में भी स्टैक डिजाइन का इस्तेमाल किया है. इसमें उपलब्ध सेंसर का ऑटोफोकस 192 प्वाइंट्स का है. इसी के साथ ये सेंसर 4के (4096 गुणा 2160) रेजोल्यूशन के वीडियोज रिकॉर्ड कर सकता है. स्टिल इमेज के एचडीआर फंक्शन उपलब्ध है. कंपनी के अनुसार इससे स्मार्टफोन फोटोग्राफी की क्वालिटी और बेहतर बनाई जा सकेगी. इस सेंसर में जो इमेज फेस डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा में इस्तेमाल की जाती है. इसी के साथ एचडीआर इमेजिंग तकनीक ना सिर्फ 4के वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करती है बल्कि स्टिल इमेज में भी बेहतर क्वालिटी देती है. कंपनी के अनुसार नए इमेज फेस डिटेक्शन से यूजर्स क्विक मूविंग सब्जेक्ट (तेजी से चलने वाली वस्तुएं) जैसे बच्चों की फोटो, भागते हुए जानवरों की फोटो, एथलीट्स की फोटोज खींची जा सकती हैं. 192 ऑटोफोकस प्वाइंट्स इमेज क्वालिटी पर काम करते हैं. ■

इस एप से जाने गर्लफ्रेंड के मन की बात

अगर आप गर्लफ्रेंड के मन की बात जानना चाहते हैं तो एक एप आपकी मदद कर सकता है. जी हां, अगर गर्लफ्रेंड से चैट करते हुए वह काफी लंबे वक्त तक कुछ टाइप कर रही है, लेकिन आखिर में केवल ओके लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट करके रिटाइप किया है. इससे आप जान नहीं

पाते हैं कि वह क्या कहना चाहती है. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एप गर्लफ्रेंड की दिल की बात जानने में आपकी मदद करेगा. इस एप का नाम बीम मैसेंजर है. इससे आप यह जान पाएंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने क्या टाइप किया था. यह एप टोरंटो बेस्ड प्रोपल्सन लेब ने बनाई है, जो यह दर्शाती है कि जिससे आप चैट कर रहे हैं वह क्या टाइप कर रहा है. बीम मैसेंजर अपनी तरह की पहली ट्रू रियल टाइम कम्यूनिकेशन एप है. जो आपको बताती है कि आपके दोस्त ने क्या टाइप किया है. इस एप से आप वह मैसेज भी पढ़ सकते हैं जो आपके पार्टनर ने टाइप तो किया, लेकिन उसे सेंड करने की बजाए डिलीट कर दूसरा मैसेज भेज दिया. बीम मैसेंजर एंड्रॉयड फोन के लिए फ्री उपलब्ध है. इसे गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है. ■

हेलमेट, लगाते ही बढ़ेगी बाइक की स्पीड!

बाजार में एक ऐसा हेलमेट उपलब्ध है जिसे लगाते ही बाइक की स्पीड बढ़ जाएगी. एरिस के इन नए हेलमेट्स की सबसे खास बात ये है कि इन्हें नासा तकनीक पर बनाया है. दूसरी सबसे खास बात ये है कि जबरदस्त तकनीक होने के बावजूद कंपनी ने इन्हें बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक कीमत में उतारा है. इसके अलावा इसमें आकर्षक डिजायन और ग्राफिक्स दिए गए हैं जो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं. इनमें दी तकनीक और शानदार विजिबिलिटी के चलते बाइक चलाने वालों को परेशानी नहीं होती. इन हेलमेट्स को इटली में डिजायन किया गया है और भारत में 2999 रुपये से 3999 रुपये के बीच में लॉन्च किया है. इनमें मैट्ट फिनिश स्टाक, सकुल, डेनिम और डेविल जैसे मॉडल शामिल है. इन सभी हेलमेट्स में अन्दर की तरफ पीयू-फोम मेटेरियल दिया गया है जिससे काफी सॉफ्ट है. ये हेलमेट एंटीथेफ्ट रिंग, एयर एंड वाटर टाइट स्प्रेक्ट्रा गार्ड जैसे फीचर्स से लैस है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

सरिता देवी ने सच की लड़ाई लड़ने के लिए अपने करियर को दांव पर लगा दिया. लेकिन भारत सरकार और खेल मंत्रालय कहीं भी सरिता देवी का बचाव करता नज़र नहीं आया. खेल मंत्रालय ने आईबा को भेजे जाने वाले जवाब को तैयार करने में मदद करने का आश्वासन दिया था. इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम. अंततः सरिता देवी पर आईबा ने दो साल का प्रतिबंध लगा दिया. इस वजह से वह 19 नवंबर से दक्षिण कोरिया में हुई विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाईं. अब वह अगले दो साल तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी. इस वजह से उनका करियर ख़तरे में पड़ गया है.

सिर्फ नाम का खेल मंत्रालय

भारत सरकार का खेल मंत्रालय केवल नाम का मंत्रालय बनकर रह गया है. ऐसा लगता है पुरस्कार और खिलाड़ियों को अनुदान देने के अलावा उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है. वह सरिता देवी के साथ हुए भेदभाव पर कड़ा विरोध दर्ज करने में असफल रही है. मैच फिक्सिंग पर रोक लगाने और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए क़ानून का इंतजार देश पिछले डेढ़ दशक से कर रहा है. यूपीए-2 सरकार ने खेल बिल लाकर खेल प्रसानिक संस्थानों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने और कई बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक दवाव के कारण यह कोशिश सफल नहीं हो सकी. मोदी सरकार खेल बिल शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रही है लेकिन मैच फिक्सिंग पर रोक लगाने को लेकर कुछ होता नहीं दिख रहा है.

नवीन चौहान

महिला मुक्केबाज सरिता देवी ने सितंबर माह में इंचीयोन में हुए एशियाई खेलों में 60 किग्रा. स्पर्धा की कांस्य पदक जीता था. स्पर्धा के सेमीफाइनल मुक़ाबले में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद प्रतिद्वंदी कोरियाई मुक्केबाज को निर्णायकों ने विजेता घोषित कर दिया था. सरिता ने फैसले के खिलाफ अपील की लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया. इसके बाद पदक वितरण समारोह के दौरान वह पोडियम में गईं लेकिन पदक लेने से इंकार कर दिया. बाद में विरोध स्वरूप उन्होंन अपना पदक दूसरी खिलाड़ी पार्क जि ना के गले में डाल दिया, जिनके खिलाफ उन्हें हारा घोषित किया गया था. समारोह के दौरान वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकीं और फूट-फूट कर रोईं. अंत में वह अपना पदक पोडियम पर ही छोड़ कर चली गईं. इस घटना पर बहुत विवाद हुआ. इसके बाद सरिता ने पोडियम पर किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी. बावजूद इसके बॉक्सिंग की वैश्विक संस्था आईबा ने उनके खिलाफ अनुशासात्मक कार्रवाई करते हुए दो साल का प्रतिबंध लगा दिया.

सरिता देवी ने सच की लड़ाई लड़ने के लिए अपने करियर को दांव पर लगा दिया. लेकिन भारत सरकार और खेल मंत्रालय कहीं भी सरिता देवी का बचाव करता नज़र नहीं आया. खेल मंत्रालय ने आईबा को भेजे जाने वाले जवाब को तैयार करने में मदद करने का आश्वासन दिया था. इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम. अंततः सरिता देवी पर आईबा ने दो साल का प्रतिबंध लगा दिया. इस वजह से वह 19 नवंबर से दक्षिण कोरिया में हुई विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाईं. अब वह अगले दो साल तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी. इस वजह से उनका करियर खतरे में पड़ गया है.

निलंबन का सामना कर रहीं सरिता देवी के करियर पर आंच आती देख मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उनका समर्थन किया है. उन्होंने इस संबंध में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है और उनसे सरिता का साथ देने का आग्रह किया गया है ताकि उनके करियर को बीच में ही खत्म होने से बचाया जा सके. सचिन ने खेलमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तत्काल इस मामले पर गौर करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें भरपूर सहयोग मिले ताकि उनका करियर खतरे में न पड़े. सचिन ने पत्र में यह भी लिखा है कि एक देश के रूप में हमें इसके लिए हर तरह के प्रयास करने चाहिए कि उन्हें माफ किया जाए और उन्हें उच्च स्तर पर मुक्केबाजी का कौशल दिखाने की अनुमति मिले. सचिन ने खेलमंत्री से आईबा के सामने सरिता का मामला रखने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ और मुकक्केबाज़ी महासंघ के सीनियर अधिकारियों के टास्क फोर्स का गठन करने का भी आग्रह किया है. उन्होंने लिखा है, वर्तमान प्रक्रिया की सीमित जानकारी होने के कारण मैं आपकी अगुवाई में भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के क़ानूनी जानकारी रखने वाले सीनियर अधिकारियों का एक टास्क फोर्स गठित करने का आग्रह करता हूं. इस टास्क फोर्स का उद्देश्य सरिता के बचाव में उचित तर्क पेश करके मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था द्वारा उनके करियर को किसी तरह के नुकसान पहुंचाने के संभावित प्रयास को रोकना होना चाहिए. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सरिता देवी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करने में गर्व महसूस करते हैं. वह भारत सहित विभिन्न सहयोगियों से हर तरह के समर्थन की हकदार हैं.

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि अगर खेल के मैदान में खेल भावना में बहकर उठाया कोई कदम सही नहीं है तो रेफरी के गलत निर्णय की सजा किसी खिलाड़ी को देना भी सही नहीं है. यह कहां का इंसाफ है. खासकर तब जब सच पूरी दुनिया के सामने है. भले ही सरिता को आईबा ने निलंबित कर दिया हो, लेकिन इस मसले पर सारा देश उनके साथ है. खिलाड़ियों का हर कदम पर साथ देने से मेडल मिलते हैं. मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को पैसे दे देने से सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती. सरकार और देश हर कदम पर उनके साथ खड़ा है. खिलाड़ियों के मन में ऐसा विश्वास जगाये बगैर मेडल जीत पाना संभव नहीं है. अगर दुनिया भारत को एक बाजार के रूप में देखती है तो भारत को भी अपने बाजार की ताकत पहचाननी चाहिए. यदि आप अच्छी तरह यह जानते हैं कि हमारे खिलाड़ी की कोई

गलती नहीं है. ऐसे में खिलाड़ी के बचाव में सरकार और खेल प्रशासकों को खुलकर सामने आना चाहिए. लेकिन सरकार ने सरिता के मामले में ऐसा नहीं किया. यदि दूसरे देश खेल आयोजनों का बॉयकॉट कर सकते हैं. तो भारत भेदभाव होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं कर सकता. खिलाड़ियो के हित के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे भेदभाव को ध्यान में रखकर सरकार को कड़े से कदम उठाने चाहिए. सरिता देवी ने कोई गलत काम नहीं किया है इसलिए सरकार को आईबा और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के साथ बैठकर इस बात की तसदीक करनी चाहिए कि सरिता सही थीं, या रेफरी गलत. इसके लिए वीडियो

सरिता देवी के करियर पर आंच आती देख मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उनका समर्थन किया है. उन्होंने इस संबंध में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है और उनसे सरिता का साथ देने का आग्रह किया गया है ताकि उनके करियर को बीच में ही खत्म होने से बचाया जा सके. सचिन ने खेलमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तत्काल इस मामले पर गौर करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें भरपूर सहयोग मिले ताकि उनका करियर खतरे में न पड़े. सचिन ने पत्र में यह भी लिखा है कि एक देश के रूप में हमें इसके लिए हर तरह के प्रयास करने चाहिए कि उन्हें माफ किया जाए और उन्हें उच्च स्तर पर मुक्केबाजी का कौशल दिखाने की अनुमति मिले.

फुटेज उपलब्ध है इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी करना आसान है.

दूसरी तरफ खेल मंत्रालय अभी तक खेलों में फिक्सिंग पर रोक लगाने के लिए किसी तरह के कदम उठाती नहीं दिखा है. फिलहाल जो भी कानून देश में मौजूद हैं उनेक अंतर्गत केवल आईपीसी की धारा 120 बी, 420 के तरह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. 1999 में जब मैच क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का मामला सामने आया था तब से लेकर अब तक पंद्रह साल गुजर गए हैं. तब भी देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी. आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है. इन पंद्रह सालों में स्पॉट फिक्सिंग और फिक्सिंग से जुड़े कई मामले सामने आए, लेकिन सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई कानून बनाने की पहल नहीं की. ऐसा लग रहा है इन्हीं वजहों से लग रहा है कि खेल मंत्रालय केवल नाम का मंत्रालय बनकर रह गया है. इसकी जिम्मेदारी केवल अर्जुन, द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कार देने तक ही सीमित रह गई है.

क्रिकेट में फैले भ्रष्टाचार की वजह से दुनिया भर में भारत की इज्जत दांव पर लगी है. बीसीसीआई प्रमुख का दामाद मैच फिक्सिंग में लिप्त हो और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा होने की संभावना बेहद कम है. इसके बावजूद बीसीसीआई श्रीनिवासन के बचाव में उतर आया है. सरकार का मुह बंद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर थे. उनके सहयोगी और वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर थे. वर्तमान में गुजरात क्रिकेट की कमान अमित शाह के हाथों में है. ऐसा लग रहा है कि देश में भ्रष्टाचार को खत्म करके अच्छे दिन लाने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार खेलों को खासकर क्रिकेट को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करना चाहती है. अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री मोदी अरुण जेटली और अमितशाह जैसे दिग्गज इसकी पहल करते. भाजपा के कई नेता क्रिकेट प्रशासन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग भी खेल प्रशासन से जुड़े रहे हैं. ऐसे में सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे नज़र आते हैं.

वक्त बदल रहा है. वक्त के साथ खेलों की भूमिका भी बदल रही है. खेलों के जरिए डिप्लोमेसी हो रही है. ऐसे में खेलो को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है. यदि सरकार खेलों और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए कदम नहीं उठाएगी तो खेलों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा. खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाना कि आप ईमानदारी से बेहतर प्रदर्शन करें तो सरकार हर कदम पर आपके सहयोग के लिए खड़ी है. ऐसा करके ही विश्व में भारत खेलों में अपनी पहचान बना पाएगा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अपनी मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा.■

navinonline2003@gmail.com

रोहित का रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किलः लारा

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कहा है कि रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, उसे पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा. रोहित ने कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेलते हुए वनडे मैचों का सबसे लंबी पारी खेलकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था. रोहित दो मौकों पर 200 रनों की पारियां खेल चुके हैं. लारा ने कहा कि हमने सर विवियन रिचर्ड्स के 189 रनों के रिकॉर्ड को काफी लंबे समय तक जिया है. हम जानते हैं कि इस तरह का रिकॉर्ड बनाने के लिए बल्लेबाज को किस तरह से गेंदबाजों पर विजय पाना होता है. मैं तो यही मानता था कि 200 रनों का रिकॉर्ड संभव है, लेकिन अब मैं मानता हूं कि रोहित के 264 रनों को पार कर पाना काफी मुश्किल होगा. यह लाजवाब प्रदर्शन है. यह एक खास पारी थी और मेरी नजर में उसे पार पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होगा. लारा के नाम टेस्ट इतिहास की सबसे लंबी पारी है. लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 400 रनों की नाबाद पारी खेली थी इसके अलवा प्रथम श्रेणी क्रिकेट की सबसे लंबी(501 नाबाद)पारी भी उनके नाम दर्ज है.■

साइना और श्रीकांत ने चाइना ओपन का खिताब जीता

भारत की स्टार शटलर साइना नेहवाल और युवा खिलाड़ी के. श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है. साइना ने फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया जबकि श्रीकांत ने चीन के दो बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन को सीधे सेटों में मात दी. फाइनल में साइना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापानी खिलाड़ी को सीधे सेटों में 21-12, 22-20 से मात दी. यह साइना का साल का तीसरा खिताब है. उन्होंने जून में ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज और इस साल के शुरू में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय ग्रां प्री गोल्ड का खिताब जीता था. यह उनका कुल आठवां प्रीमियर सुपर सीरीज खिताब है. श्रीकांत के करियर का यह पहला सुपर सीरीज खिताब है. आंध्र प्रदेश के इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने पांच बार के विश्व चैंपियन लिन डैन के खिलाफ 21-19, 21-17 से जीत दर्ज की. पिछले साल थाईलैंड ओपन ग्रां प्री जीतने वाले श्रीकांत इस साल इंडिया ओपन ग्रां प्री में उप-विजेता रहे थे जबकि वह मलेशियाई ओपन के क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचे थे. सुपर सीरीज और प्रीमियर टूर्नमिंट शुरू किए जाने के बाद यह किसी भारतीय पुरुष शटलर द्वारा जीता गया पहला सुपर सीरीज खिताब है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

फिल्मी कलाकारों की भी पर्सनल लाईफ होती है

नरगिस फाखरी

नरगिस के बारे में यह अफवाह उड़ी थी कि उनका अभिनेता और फिल्म निर्माता उदय चोपड़ा के साथ अफेयर चल रहा है. रितिक रोशन के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया. लेकिन नरगिस ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया. नरगिस ने इन अफवाहों के बारे में कहा कि मेरा मानना है जब आप इस लाइन में हो तो आपको ऐसी खबरों से रू-ब-रू होना होगा.

अभिनेत्री नरगिस फाखरी का कहना है कि फिल्मी हस्तियों की भी पर्सनल लाईफ होती है वे भी निजता और गोपनीयता के हकदार हैं. मीडिया की ओर से लगातार उनके रिश्ते के बारे में सवाल पूछे जाने से नरगिस नाराज हैं. वे चाहती हैं कि पर्सनल लाईफ को पर्सनल ही रखा जाना चाहिए. नरगिस ने फिल्म रॉकस्टार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. फिल्म रॉकस्टार में दर्शकों ने रणबीर और नरगिस की जोड़ी को खासा पसंद किया था. इसके बाद नरगिस के बारे में यह अफवाह उड़ी थी कि उनका अभिनेता और फिल्म निर्माता उदय चोपड़ा के साथ अफेयर चल रहा है. रितिक रोशन के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया. लेकिन नरगिस ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया. नरगिस ने इन अफवाहों के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा मानना है जब आप इस लाइन में हो तो आपको ऐसी खबरों से रू-ब-रू होना होगा. लेकिन इन खबरों को नजरअंदाज कर चलना ही समझदारी है. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्मी सितारों को भी गोपनीयता अच्छी लगती है. वो भी आम इंसान ही हैं.

उनकी भी पर्सनल लाइफ है. किसी के साथ नाम जोड़े जाने और झूठी अफवाहें फैलाने से फिल्मी कलाकारों को परेशानी होती है. ■

रोबोट-2 में आमिर खलनायक बनेंगे

रोबोट के निर्माण से पहले इसके निर्देशक एस शंकर ने आमिर खान के पास मुख्य भूमिका निभाने का प्रस्ताव भेजा था. उस वक्त आमिर ने मना कर दिया था. इसके बाद उस भूमिका में रजनीकांत को लिया गया था. इस फिल्म से पहले आमिर ने धूम-3 में निगेटिव रोल अदा किया था.

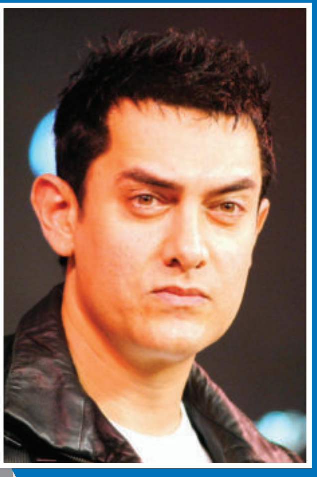

बॉलीवुड के मिस्टर परफैक्शनिस्ट आमिर खान के पास रोबोट-2 में काम करने का ऑफर आया है. यदि आमिर खान ने इसके लिए हामी भर दी तो रोबोट-2 रजनीकांत वाली रोबोट से भी ज्यादा सफल हो सकती है. इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आमिर किसी भी फिल्म में जिस किसी भूमिका में आते हैं वह उसे पूरी तरह सजीव करने की क्षमता रखते हैं. आमिर इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं. हाल ही में उनकी रिलीज होने वाली फिल्म पीके में अपने किरदार को सजीव करने के लिए उन्होंने एक दिन में 50 से 60 पान तक खाए. वहीं, फिल्म गजनी में उन्होंने अपने किरदार के लिए कई दिनों तक जिम में घंटों पसीना बहाया. फिल्म रोबोट के निर्माण से पहले इसके निर्देशक एस शंकर ने आमिर खान के पास मुख्य भूमिका निभाने का प्रस्ताव भेजा था. उस वक्त आमिर ने मना कर दिया था. इसके बाद उस भूमिका में रजनीकांत को लिया गया था. इस फिल्म से पहले आमिर ने धूम-3 में निगेटिव रोल अदा किया था. इससे यह जाहिर है कि वह निगेटिव भूमिका निभाने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं है. रोबोट मे बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ की कमाई की थी. आमिर के सामने इसे पार करने की भी चुनौती होगी. ■

फिल्मी हिंसा की वजह से अमिताभ बने एंग्री यंग मैन: हाई कोर्ट

फिल्मों में दिखाई जा रही हिंसा और मारधाड़ पर रोक लगाने के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने गुजरात हाईकोर्ट इंकार कर दिया. हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीएम सहाय और न्यायाधीश आरपी ढोलरिया ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर फिल्मों में हिंसा न दिखाई जाती, तो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि कभी नहीं बन पाती. पर्दे पर उनकी जो छवि बनी है, वह केवल उस हिंसा की वजह से ही बनी है, जो फिल्मों का हिस्सा था. सूरत निवासी हेमंत जोगी ने डर्टी पिक्चर और जिस्म टू जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए फिल्मों में अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी. इसके साथ ही उन्होंने टेलिविजन कार्यक्रमों के लिए एक अलग सेंसर बोर्ड का गठन करने की मांग की थी. उनका कहना था कि हिंदी फिल्में में हिंसा को काफी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है. लेकिन, हाईकोर्ट ने उनकी हर बात को दरकिनार करते हुए कहा कि फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा को सेंसर करने के लिए एक सरकारी संस्था केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पहले से मौजूद है. इस संस्था में फिल्मों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं. एक अदालत उनके फैसले को जज नहीं कर सकती. याचिकाकर्ता ने फिल्मों में दिखाए जाने वाले धूम्रपान के दृश्यों पर भी आपत्ति की थी, लेकिन इसपर कोर्ट ने कहा कि जब भी फिल्मों में ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं तो साथ में पर्दे पर धूम्रपान से दूर रहने का संदेश भी लिखा रहता है. ■

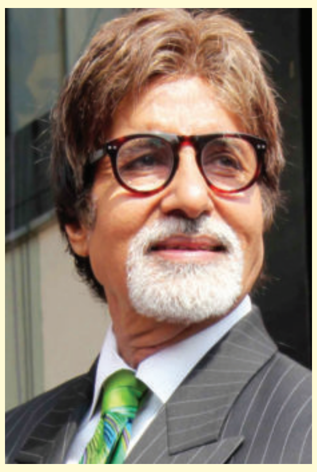

हैप्पी न्यू ईयर ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल हुई

अभिनेता शाहरुख खान की हालिया प्रदर्शित फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के स्क्रीन प्ले को ऑस्कर लाइब्रेरी के कलेक्शन में शामिल किया गया है. फिल्म ने 350 करोड़ की कमाई कर एक नया मुकाम हासिल किया है. फिल्म का निर्देशन फराह खान ने किया है. हैप्पी न्यू ईयर को लाइब्रेरी द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज के कोर कलेक्शन्स में जगह दी गई है. अब इस फिल्म का स्टोरी बोर्ड, इससे जुड़ी प्रेस क्लिपिंग्स, रिव्यू, रिलीज और अवार्डस से जुड़ी सारी जानकारियां इस लाइब्रेरी में रखी जाएंगी. यह पहला मौका नहीं है जब शाहरुख की कोई फिल्म ऑस्कर लाइब्रेरी तक पहुंची है. इससे पहले देवदास और चक दे इंडिया के स्क्रीन प्ले को भी लाइब्रेरी में जगह दी गई थी. दुनियाभर की चुनिंदा फिल्मों को ऑस्कर की ओर से हमेशा के लिए कोर कलेक्शन में रखा जाता है. इस कलेक्शन के जरिए सिनेमा से जुड़े कलाकार, निर्माता और लेखक अपनी रिसर्च कर सकते हैं. इस फिल्म को दर्शकों ने खासा पसंद किया था. इस फिल्म में काम कर चुके अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कहा है कि फराह खान पर हैप्पी न्यू इयर का सीक्वल बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ईश्वर ने चाहा तो राजनीति में आऊंगा: रजनीकांत

सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का संकेत देते हुए कहा है कि अगर भगवान ने चाहा तो वह राजनीति में आकर लोगों की सेवा करेंगे. रजनीकांत ने यह बात अपनी आगामी ऐक्शन थ्रिलर फिल्म लिंगा के ऑडियो और ट्रेलर लांच मौके पर बताई. रजनीकांत ने बताया कि हर कोई चाहता है कि मैं राजनीति में आऊं.मैं राजनीति की गहराई और जोखिम से वाकिफ हूं. मैं राजनीति में आने से डरता नहीं हूं, लेकिन इसे लेकर थोड़ी सी हिचक है. यह मेरे हाथ में नहीं है. अगर ईश्वर ने चाहा, तो मैं लोगों की सेवा करूंगा. उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से सामाजिक संदेश वाली फिल्में करना भी एक तरह की समाजसेवा ही है. फिल्में बनाना और राजनीति में आना बहुत आसान है, लेकिन दोनों में विजेता बन पाना बेहद मुश्किल. उनकी फिल्म लिंगा 12 दिसंबर को रिलीज हो रही है. ■

सुपर स्टार रजनी के साथ काम कर बेहद खुश हूं- सोनाक्षी

तमिल फिल्म में काम के अपने अनुभव पर बताया कि मैं यहां एक नई अभिनेत्री हूं. मुझे यहां ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. रजनीकांत की नायिका बनना मेरे लिए बड़ी बात है.

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा तमिल फिल्म लिंगा में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करके बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि यह उनकी पहली तमिल फिल्म है. उन्हें सबसे ज्यादा खुशी रजनीकांत की नायिका बनकर है. सोनाक्षी ने पहली बार तमिल फिल्म में काम किया है. उन्होंने तमिल फिल्म में काम के अपने अनुभव पर बताया कि मैं यहां एक नई अभिनेत्री हूं. मुझे यहां ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. रजनीकांत की नायिका बनना मेरे लिए बड़ी बात है. फिल्म के बारे में सोनाक्षी ने बताया है कि लिंगा दो युगों में बंटी फिल्म है. फिल्म में मैंने गांव की लड़की की भूमिका निभाई है जो कि 1940 के दशक की प्रेमिका है. वहीं अनुष्का शर्मा ने रजनीकांत की वर्तमान युग की जोडीदार की भूमिका निभाई है. इसके अलावा सोनाक्षी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म तेवर को लेकर भी खासा व्यस्त हैं. तेवर में सोनाक्षी के साथ अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है. इसके अलावा सोनाक्षी अजय देवगन के साथ फिल्म एक्शन जैक्सन में भी दिखाई देंगी. ■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

01 सितंबर-07 सितंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

बिहार झारखंड

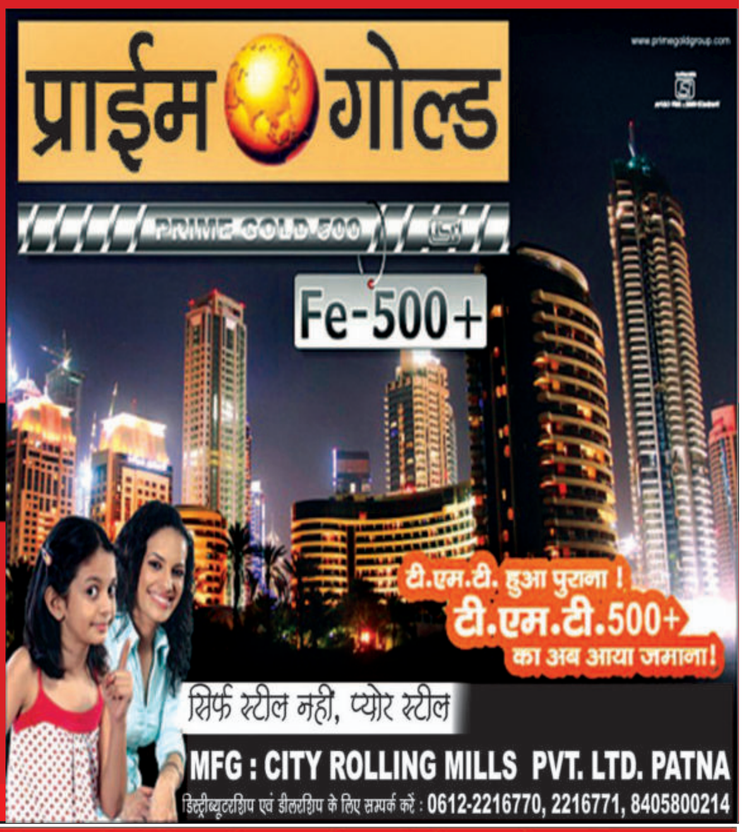

नरेंद्र सिंह

बिजेंद्र कुमार यादव

नीतीश कुमार

अपने ही डूबो रहे हैं मांझी की नैया

जीतन राम मांझी

जीतन राम मांझी की यही सादगी और बिंदास बोल सरकार के भीतर और बाहर कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है. सरकार के अंदर का पहला अंतरविरोध उस समय सामने आया जब कृषि मंत्री ने यह कहकर मुख्यमंत्री के बयान को काट दिया था कि राज्य में अभी सूखे के हालात नहीं हैं और अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह बिल्कुल सही है. गौरतलब है कि मांझी ने मौके का मुआयना करके यह बात कही थी कि अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं दी है इसलिए सूखे के संबंध में दोबारा रिपोर्ट दी जाए. इसी तरह सरकार के अंदर का दूसरा अंतर विरोध उस समय सामने आया जब दलितों को स्कूल में उपस्थिति की सीमा में नहीं बांध कर पोशाक आदि देने की फाइल को विजेंद्र यादव ने लौटा दिया.

सरोज सिंह

बिहार में जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बनना निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था. नीतीश कुमार के इस फैसले ने बड़े-बड़े राजनीतिक पंड़ितों को भी चौंका दिया था. खुद जीतन राम मांझी भी मानते हैं कि मैंने कभी सपने में भी मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं सोची थी. वह कहते हैं कि जब नीतीश कुमार ने मुझे बुलाया और अपनी कुर्सी पर बैठने को कहा तो मैंने कहा कि कहीं आप दशरथ मांझी की तरह तो हमें नहीं बैठा रहे हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि, नहीं अब यहां से बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप के कंधों पर है. लोकसभा चुनाव में हार के बाद तेजी से बदलते घटनाक्रम में जहां नीतीश कुमार ने इस फैसले को अपने त्याग और महादलित प्रेम के तौर पर पेश किया तो विपक्ष ने इसे सत्ता की मजबूरी करार दिया. खैर जीतन राम मांझी की पारी शुरू हुई तो न केवल आलोचकों व विश्लेषकों की इस पर पैनी नजर थी बल्कि उनके समर्थकों के लिए उनका हर कदम जिज्ञासा के दायरे में आ गया. आम धारणा बनने लगी कि जीतन राम मांझी की कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी. यह सोच इसलिए भी बन रही थी कि विजेंद्र यादव और नरेंद्र नारायण यादव जैसे दावेदारों के बीच में से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मौका दिया. यह सच है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का बेहद सम्मान करते हैं. एक बातचीत में उन्होंने बताया कि बिहार के दो नेताओं ने मुझे सही तरह से परखा और मैं मानता हूं कि दोनों ही नेताओं ने बिहार की समस्याओं को सही तरीके से समझा और इस राज्य को आगे ले जाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया. इन नेताओं में उन्होंने चंद्रशेखर सिंह और नीतीश कुमार का नाम लिया. नीतीश कुमार की कार्यशैली के भी जीतन राम मांझी कायल हैं. लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों का बारीक विश्लेषण करें तो यह राय बनाने में आसानी होगी कि सरकार के अंदर मुख्यमंत्री को पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए. यहां यह बात काबिलेगौर है कि जीतन राम मांझी सभी दलों के विधायकों से बिना किसी तामझाम के मिलते हैं और उनकी समस्याओं को गौर से सुन समाधान का आश्वासन देते हैं. आपको याद होगा कि नीतीश राज में विधायक कौन कहे मंत्रियों तक की शिकायत रहती थी कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है. पार्टी का आम कार्यकर्ता तो नीतीश कुमार से मिलने का ख्वाब देखना तक भूल गया था. लेकिन मांझी ने इस कल्चर को बदला है. अपने दल के लोग तो उनसे मिलते ही है विपक्ष के विधायक व नेता भी उनसे बेहिचक मिल रहे हैं. ताज्जुब तो यह है कि जदयू के बागी विधायकों का डेरा भी मांझी के यहां अक्सर रहा लगा रहता है. जीतन राम मांझी कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का काम ही है लोगों की समस्याओं को सुनना और नियम कानून के मुताबिक इसका यथासंभव समाधान निकालना . मैं तो बस एक जनप्रतिनिधि का अपना दायित्व निभा रहा हूं. यही वजह है कि विधायकों और नेताओं के दिलों में मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान काफी बढ़ता जा रहा है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे पास समय कम है इसलिए रात दिन मेहनत करके हमें बिहार का विकास करना है. मांझी बिंदास बोलते हैं और पारदर्शी तरीके से शासन चलाने में विश्वास करते हैं. भ्रष्टाचार को लेकर भी वह बेहद सख्त हैं. कहते हैं कि मेरा एटीएम तो मेरा जेब ही है. कोई बैंक बैलेंस नहीं है. मेरे शपथग्रहण समारोह के दिन भी मेरी पत्नी को गांव में अपने घर में रखे अनाज की चिंता सता रही थी. अपने कर्म और भगवान पर मेरा पूरा भरोसा है. एक महादलित का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मांझी की ऐसी ही खासियतें उनके लिए कुछ कांटे भी पैदा कर रही हैं.

जीतन राम मांझी की यही सादगी और बिंदास बोल सरकार के भीतर और बाहर कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है. सरकार के अंदर का पहला अंतरविरोध उस समय सामने आया जब कृषि मंत्री ने यह कहकर मुख्यमंत्री के बयान को काट दिया था कि राज्य में अभी सूखे के हालात नहीं हैं और अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह बिल्कुल सही है. गौरतलब है कि मांझी ने मौके का मुआयना करके यह बात कही थी कि अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं दी है इसलिए

जीतन राम मांझी की यही सादगी और बिंदास बोल सरकार के भीतर और बाहर कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है. सरकार के अंदर का पहला अंतरविरोध उस समय सामने आया जब कृषि मंत्री ने यह कहकर मुख्यमंत्री के बयान को काट दिया था कि राज्य में अभी सूखे के हालात नहीं हैं और अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह बिल्कुल सही है. गौरतलब है कि मांझी ने मौके का मुआयना करके यह बात कही थी कि अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं दी है इसलिए सूखे के संबंध में दोबारा रिपोर्ट दी जाए. इसी तरह सरकार के अंदर का दूसरा अंतर विरोध उस समय सामने आया जब दलितों को स्कूल में उपस्थिति की सीमा में नहीं बांध कर पोशाक आदि देने की फाइल को विजेंद्र यादव ने लौटा दिया.

सूखे के संबंध में दोबारा रिपोर्ट दी जाए. इसी तरह सरकार के अंदर का दूसरा अंतर विरोध उस समय सामने आया जब दलितों को स्कूल में उपस्थिति की सीमा में नहीं बांध कर पोशाक आदि देने की फाइल को विजेंद्र यादव ने लौटा दिया. काफी जद्दोजहद के बाद इसमें बीच का रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है. यह सब चल ही रहा था कि इस दौरान मांझी के दो तीन बयानों ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी. झारखंड में उन्होंने कहा कि अगर बिहार विधानसभा के चुनाव में जीत हुई तो नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे. एक दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक प्रयोग की तरह है और यह आगे चलेगा या नहीं इसका फैसला उपचुनाव के नतीजे के बाद होगा. इन बयानों के बाद उनका तीसरा सबसे विस्फोटक बयान आया कि नीतीश राज में विकास तो हुआ पर भ्रष्टाचार भी फैला. मुझे खुद बिजली बिल के सटेलमेंट में पैसे देने पड़े. शुरू के दो बयानों को तो जदयू के शीर्ष रणनीतिकरों ने आई गई बात कह कर भूला दिया पर नीतीश राज में भ्रष्टाचार बढ़ने की बात वे पचा नहीं पा रहे हैं. उनकी सोच है कि नीतीश कुमार की पूंजी ही सुशासन है. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने ही नीतीश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी. बेदाग छवि और भ्रष्टाचार मुक्त शासन ने ही नीतीश कुमार को देश के दूसरे नेताओं से अलग श्रेणी में रखा. लेकिन जब राज्य के मुखिया ने ही भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कुबूल कर ली तो जदयू के खेमे में हड़कंप मच गया. सूत्र बताते हैं कि खुद नीतीश कुमार भी मांझी के इस बयान से खुश नहीं थे. लेकिन जब तीर कमान से निकल जाए तो क्या कहा जा सकता है? यही वजह रही कि जब मांझी के बेटे पर गया के होटल प्रकरण में आरोप लगा तो पार्टी तुरंत बचाव में सामने नहीं आई. पार्टी से जिस मदद की उम्मीद मांझी को थी उसमें कमी दिखी. आखिरकार मुख्यमंत्री ने खुद ही मोर्चा लेते हुए अपने बेटे का पक्ष रखा और बहुत ही खुलकर आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने यहां तक कहा कि महादलित का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बन गया यह बात पता नहीं कुछ लोग क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जदयू की जो भूमिका रही उसे लेकर मांझी दुखी हैं. मांझी कहते हैं कि मैंने तो बिहार के लिए काम करने का सकंल्प लिया हुआ है इसलिए आरोप व प्रत्यारोप से मैं घबराने वाला नहीं हूं. नीतीश कुमार और बिहार की जनता ने मेरे कंधे पर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका ईमानदारी से निर्वाह करना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं इसी काम में लगा हूं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मांझी अपने काम में लगे हैं अब इन कामों का साइडइफेक्ट जदयू या फिर नीतीश कुमार के वर्चस्व पर पड़ रहा है तो इसमें मुख्यमंत्री का क्या दोष? उपचुनाव के नतीजों के बाद यह दिक्कतें और भी बढ़ने के आसार हैं. पार्टी के अंदर जीतन राम मांझी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है. यह बात नीतीश समर्थकों को अखरेगी. इसलिए सब ठीक रहे इसके लिए जरूरी है कि पार्टी और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करें. अगर मुख्यमंत्री के फैसलों पर सवाल उठेंगे तो सत्ता के दो केंद्र बनना तय है और ऐसी स्थिति न तो जदयू के लिए अच्छी है और न ही नीतीश कुमार के लिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

राष्ट्रध्वज को दी सलामी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीतामढ़ी जिले में अलग–अलग स्थानों पर उत्साहपूर्ण माहौल में राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गयी. जिला मुख्यालय डुमरा स्थित परित्यक्त हवाई अड्डा मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में जिला प्रभारी मंत्री राम लखन राम रमण ने परेड गारद का निरीक्षण कर झंडा फहराया. समाहरणालय परिसर में डीएम डॉ. प्रतिमा, पुलिस लाइन मैदान में एसपी नवल किशोर सिंह, जिला परिषद कार्यालय परिसर में अध्यक्ष इन्द्र रानी देवी, ने झंड फहराये. अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ महेंद्र कुमार, जिला कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष विमल शुक्ला, राजद कार्यालय में मो शफीक खां, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में चेयरमैन प्रो. नरेंद्र कुमार, एवं कृषि विज्ञान केंद्र में पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने झंडा फहराया. **– वाल्मीकि**

जल सत्याग्रह का आयोजन

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस से महज एक दिन पूर्व संघर्ष यात्रा के अध्यक्ष शशि शेखर ने लखनदेई नदी की अवरुद्ध जलधारा में एक दिवसीय उपवास सह सत्याग्रह किया. सीतामढ़ी में लखनदेई नदी की धारा में जल प्रवाह को लेकर आयोजित कार्यक्रम में लक्ष्मणा गंगा स्वच्छ जल प्रवाह अभियान समिति का गठन किया गया. दिनेशचंद्र द्विवेदी को समिति का अध्यक्ष एवं मनोज शक्ति को संयोजक बनाया गया. उपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रो. किशोरी दास, नरोत्तम व्यास, राम शरण अग्रवाल, हरिओम शरण अग्रवाल, अरुण चौधरी, संजीव कुमार सिंह, नागेंद्र सिंह, बालेश्वर प्रसाद यादव, रवींद्र राम, बाला जी, संजय यादव, चंदन सिंह सम्राट, ठाकुर चंदन कुमार सिंह, गोपेशनंदन सिंह व डॉ. अमरनाथ गुप्ता समेत अन्य थे. **– विम्मी**

शहीदों को श्रद्धांजलि

सीतामढ़ी शहर स्थित प्रेस क्लब के सभागार में जिला जदयू के तत्वावधान में एक समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें 11 अगस्त 1998 को सीतामढ़ी समाहरणालय के समक्ष पुलिस की बर्बर कार्रवाई में शहीद हुए पांच कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गयी. कार्यक्रम में पूर्व सांसद नवल किशोर राय, जदयू जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद, भरत प्रसाद, राणा रंधीर सिंह चौहान, शंकर बैठा, सेवा दल के जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, भाग्यनारायण यादव, सुरेश यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किया. **– देवेंद्र**

काव्य उत्सव आयोजित

मोतिहारी के जिला स्कूल के प्रेक्षागृह में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर काव्य उत्सव आयोजित किया गया. मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया. विशिष्ट अतिथि के रूप में बीआरएबीयू के पूर्वडीन एवं प्रसिद्ध गीतकार प्रो. डॉ. रविन्द्र कुमार रवि, विधायक प्रमोद कुमार, अरेराज एसडीओ एसएस पाण्डेय, मुख्य नगर पार्षद प्रकाश अस्थाना, प्रकाश चौधरी, केबीसी विजेता सुशील कुमार, पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर सिंह, मंजरी वर्मा, डॉ. लालबाबू प्रसाद आदि उपस्थित थे. अतिथियों का स्वागत प्राचार्या शशिकला व उप प्राचार्य उमेश कुमार सिंह ने पुष्प गुच्छ से किया. उत्सव की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि योगेन्द्र नाथ शर्मा ने की तथा संचालन वरीय रंगकर्मी कवि प्रसाद रत्नेश्वर ने किया. डॉ. रवि ने हास्य–व्यंग से सराबोर इन पंक्तियों को पढ़ा आपन पॉलिटिक्स हम बेची बजरिया में, अइसन मजा नइखे कवनो नोकरिया में. एसपी सुधीर कुमार सिंह की कविताओं पर सभी श्रोता फिदा हो गए. जब उन्होंने कहा हे भगवान अब जल्दी करो हम पे एहसान. गुलरेज शहजाद ने नौजवानों की बेबसी और लाचारी को इन शब्दों में रखा 'सब कहे रास्ते का पत्थर हूं तू मेरी जात गंगाजल कर दे'. मौके पर एसएस पाण्डेय, एमएन अख्तर, धनुषधारी कुशवाहा, लोकेश कुमार पाण्डेय, मिथिलेश घायल, रुहुल हक हमदम, अकील अहमद शाद, मजिस्टर मांझी, प्रो. जगदीश विद्रोही, अशदुल्लाह असर की रचनायें भी खुब सराही गयीं. अन्त में अध्यक्षीय कविता योगेन्द्र नाथ शर्मा ने पढ़ी. **– इन्तेजारुल हक**

बक्सर

बिहार तथा यूपी के लाइफ लाइन पर संकट

बिहार तथा यूपी के बड़े-बड़े शहरों में माल का गमनागमन इसी पुल के सहारे चलता है. प्रतिदिन इस पुल से होकर लगभग दो हजार ट्रक दोनों राज्यों के बीच समानों को ढोते हैं. वित्त वाणिज्य कर विभाग को प्रतिमाह लाखों रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है. इसके अलावा दोनों राज्यों के यात्रियों को लेकर भी छोटे तथा बड़े वाहन भी चलते हैं.

जय मंगल पाण्डेय

बिहार तथा यूपी के लाइफ लाइन बक्सर के वीर कुंवर सिंह सेतु में आयी खराबी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गयी है तथा प्रतिमाह वित्त वाणिज्य विभाग को लाखों रुपये राजस्व की क्षति भी हो रही है. पुल की मरम्मत कराने में विलम्ब के कारण इसका लागत खर्च भी पांच गुना अधिक बढ़ गया. बिहार तथा यूपी को जोड़ने वाले बक्सर में गंगा नदी पर लम्बे पुल का निर्माण केन्द्र सरकार की पहल पर 1975 में कराया गया था. इस पुल के बन जाने से दोनों राज्य परिवहन से जुड़ गये. बिहार तथा यूपी के बड़े–बड़े शहरों में माल का गमनागमन इसी पुल के सहारे चलता है. प्रतिदिन इस पुल से होकर लगभग दो हजार ट्रक दोनों राज्यों के बीच समानों को ढोते हैं. इससे वित्त वाणिज्य कर विभाग को प्रतिमाह लाखों रूपये राजस्व की प्राप्ति होती है.

इसके अलावा दोनों राज्यों के यात्रियों को लेकर भी छोटे तथा बड़े वाहन भी चलते है. लगभग आठ महीने पूर्व वीर कुंवर सिंह सेतु में तकनीकी खराबी आ गयी. पुल का स्पैन तथा प्लेट खीसक गया और इसमें कई दरारे आ गयीं. ट्रकों के आने जाने पर पुल हिलने लगा. पुल की खतरनाक स्थिति को देखकर जिला प्रशासन ने बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी. जिला प्रशासन की पहल पर राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जांच के बाद पुल की मरम्मत में लगभग दस लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया. चूंकि एन.एच. 84 से पुल जुड़ा हुआ है और इसे फोरलेन करने की जिम्मेदारी एनए–चएआई को सौंपी गयी है. लिहाजा इस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी इसी केन्द्रीय एजेंसी को दी गयी. इस एजेंसी द्वारा मरम्मत के लिए 15 लाख रूपये खर्च होने का आंकलन किया गया. लेकिन राज्य सरकार तथा विभागीय अधिकारियों में टालमटोल के कारण विलम्ब होते गया. फिर तो रोहतास तथा भोजपुर जिले से बालु लदे ओवर लोडेड ट्रकों के यूपी में जाने से पुल की स्थिति बेहद जर्जर होकर अधिक खतरनाक हो गयी. बिहार के बालू यूपी के शहरों में जाकर सोना बन जाते हैं. इसके बाद तो ओवर लोडेड ट्रकों के परिचालन को रोकने में प्रशासन की अक्षमता से पुल की समस्या और भी बड़ी हो गई है व लागत खर्च 50 लाख रुपये तक पहुंच गया. जानकार बताते है कि एनएचएआई द्वारा निर्माण कार्य में विलंब के कारण दोनों राज्यों में हाय तौबा मची हुई है. अभी तक पुल का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो सका. जाहिर है कि विभागों के बीच औपचारिकता निभाने में विलंब के कारण लागत खर्च के और अधिक बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. प्रतिदिन करोड़ों रूपये का कारोबार पर न जाने कब तक ग्रहण लगा रहेगा लेकिन रात के अंधेरे में सब कुछ हो रहा है. इस पुल के कारण ही बिहार तथा यूपी के लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक रिश्ते गहराई तक जुड़े हुए है. एक अहम सवाल यह है कि मरम्मती के बाद पुल अपनी क्षमता के अनुसार बड़े वाहनों का बोझ सह ले. लेकिन ओवरलोडेड ट्रकों के परिचालन को सह पाएगा या कि इसकी स्थिति और बिगड़ जाएगी. इसी संभावना पर पुल का भविष्य निर्भर करेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

मॉडल के बदले खंडहर बना बक्सर स्टेशन

जय मंगल पाण्डेय

रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण मॉडल स्टेशन बनाने के बदले बक्सर का रेलवे स्टेशन खंडहर बन गया. संवेदक द्वारा आधा काम कर छोड़ दिया गया. लगभग तीन साल तक काम बंद रहने के बाद फिर से निमार्ण कार्य शुरू हुआ है. विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि छह साल पहले मॉडल स्टेशन बनाने का काम शुरू हुआ और आज तक पूरा नहीं हुआ. बारिश और धूप की त्रासदी झेलते हुए बक्सर में गमनागमन करने के लिए हजारों यात्री विवश है. बिहार के अंतिम सीमा क्षेत्र पर स्थित बक्सर एक ऐसा स्टेशन है जहां से बिहार के अलावा यूपी से बड़ी संख्या में यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं. दानापुर रेल मंडल का यह स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला है और दोनों राज्यों के हजारों यात्री यहीं से आते–जाते हैं. यहां पर कई महत्वपूर्ण ट्रेन रुकती हैं. यात्रियों की संख्या तथा राजस्व प्राप्ति को देखते हुए रेलवे मंत्रालय द्वारा बक्सर को मॉडल स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया. इसके विकास के लिए एक करोड़ 55 लाख रुपये खर्च करने की योजना स्वीकृत की गई. वर्ष 2008 में बक्सर को मॉडल स्टेशन बनाने का कार्य शुरू हुआ. निमार्ण कार्य शुरू होते ही संवेदक द्वारा सुस्ती बरती गई. लिहाजा कछुए की चाल से काम होता रहा और तीन साल में अधूरा ही काम हुआ. विभागीय अभियंताओं तथा संवेदकों की लापरवाही से मनमानी काम होता रहा. फिर तीन साल में निर्माण सामग्री महंगी होने का तर्क देकर 2011 में निर्माण कार्य संवेदक द्वारा छोड़ दिया गया. लगभग 550 वर्ग फीट काम करने के बदले आधा अधूरा काम कराया गया और इस पर लगभग 70 लाख खर्च हो गये. संवेदक द्वारा हाथ खड़े कर दिये जाने के बाद तीन साल तक स्टेशन का निर्माण कार्य रुका रहा. एक तो आधे–अधूरे काम और कई जगह तोड़–फोड़ कर दिये जाने के बाद बक्सर स्टेशन इस समय खंडहर में तब्दील हो गया है. स्टेशन की स्थिति इतनी बदतर है कि गर्मी तथा बारिश में बैठने तथा सिर छिपाने की जगह नहीं मिलती है. मामूली बारिश में पूरा स्टेशन पानी–पानी हो जाता है. अधिकारियों के विभाग भी इधर से इधर होते रहते है. तीन साल के बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी यहां के लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि बक्सर मॉडल स्टेशन बन जायेगा. वैसे भी ग्रेड ए स्टेशन का दर्जा प्राप्त बक्सर रेलवे पर कई तरह महत्वपूर्ण सुविधाएं नदारद है. पेयजल तथा बैठने के अलावा सही सूचना पाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. वर्षों से पटना–रांची, पटना–टाटा, गंगा दामोदर तथा हावड़ा–दानापुर एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार बक्सर तक करने की मांग की जाती रही है. रेलवे बोर्ड द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल भी की गई थी लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने बक्सर में टर्मिनल बनाने के लिए जगह की कमी होने का तर्क देकर ट्रेनों की विस्तार योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया. ऑल इंडिया पैसेंजर वेलफेयर एसोशिएसन के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि स्टेशन की दक्षिण तरफ रेलवे की 110 एकड़ की जमीन है और इस पर टर्मिनल बनाने की मांग 1998 से ही की जा रही है. रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को इससे अवगत भी कराया गया है इस मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज तक इस पर अमल नहीं होने के कारण महत्व–पूर्ण ट्रेनों का विस्तार बक्सर तक नहीं हुआ. गाजीपुर में मनोज सिन्हा के रेल राज्य मंत्री बनने से लोगों को इम्मीद जग गई है. क्योंकि इनके संसदीय क्षेत्र के लोग बक्सर स्टेशन से ही गमनागमन करते है और इनके क्षेत्र का लंबा हिस्सा हावडा दिल्ली भाया बक्सर मेन लाईन से जुड़ा हुआ है. इसी प्रकार रघुनाथपुर स्टेशन पर मगध तथा श्रमजीवी एक्सप्रेस के ठहराव का मामला खटाई में पड़ा गया. जदयू नेता अजय इपाध्याय बताते है कि पूर्व रेलमंत्री येदुरस्पा ने यह आदेश दिया था. तब रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन विस्तार के बाद इस पर अमल करने का आश्वासन दिया था लेकिन स्टेशन का विस्तार होने के बाद भी इस महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ. जिले के डुमरांव, टुड़ीगंज, चौसा स्टेशनों पर कई तरह की समस्याएं तथा यात्री सुविधाओं के अभाव के बाद भी विभाग द्वारा व्यवस्था नहीं की गई. ■

> **स्टेशन की स्थिति इतनी बदतर है कि गर्मी तथा बारिश में बैठने तथा सिर छुपाने की जगह नहीं मिलती है. मामूली बारिश में पूरा स्टेशन पानी–पानी हो जाता है. अधिकारियों के विभाग भी इधर से उधर होते रहते है. तीन साल के बाद फिर से निमार्ण कार्य शुरू होने के बाद भी यहां के लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि बक्सर मॉडल स्टेशन बन जायेगा.**

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी

हजयात्रियों के साथ भेदभाव क्यों

पिछले कई दशकों से हो रहे भेद-भाव व अमानवीय व्यवहार की शिकायत यह सोचकर हजयात्री नहीं कर पाते हैं कि हज के सफर में परेशानी झेलना भी सबाब हैं और शरीयत इस मामले में सब्र करने का हुकम देती हैं. किन्तु हर चीज की एक सीमा होती हैं और जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करना भी शरीयत के खिलाफ हैं. जानकार बताते हैं कि सामान्य दिनों में जेद्दा जाने व आने का किराया करीब चालीस से पैंतालीस हजार रुपये लगता हैं जबकि हाजियों को एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ रूपये खर्च करना पड़ता हैं और इसमें भी सरकार कहती हैं कि हाजियों को सब्सिडी दी जा रही हैं.

इन्तेजारुल हक

बिहार समेत पूरे हिंदुस्तान से प्रतिवर्ष हज यात्रा पर कई दशकों से जाने वाले लाखों हजयात्रियों के साथ बेदर्दी से होने वाले शोषण के जिम्मेदार कौन हैं? केंद्र की सरकार या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया. आखिर कब तक इन यात्रियों के साथ दोहरी नीति अपनाई जाती रहेगी और भेड़–बकरियों की तरह इन्हें ले जाया जाता रहेगा. कब तक इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता रहेगा और प्रशासन व सरकारें खामोश तमाशा देखती रहेंगी. पूर्वी चंपारण के वरीय अधिवक्ता अल्हाज रागिब आजम द्वारा पटना के उच्च न्यायालय में हज कमेटी ऑफ इंडिया समेत छह विभागों के अधिकारियों के खिलाफ इस बाबत पीआईएल दायर किये जाने के बाद इस मुद्दे पर एक गर्म बहस शुरू हो गयी है और लोग तरह–तरह के सवालात खड़े करने लगे हैं. पिछले कई दशकों से हो रहे भेद–भाव व अमानवीय व्यवहार की शिकायत यह सोचकर हजयात्री नहीं कर पाते हैं कि हज के सफर में परेशानी झेलना भी सबाब है और शरीयत इस मामले में सब्र करने का हुकम देती है. किन्तु हर चीज की एक सीमा होती है और जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करना भी शरीयत के खिलाफ है. जानकार बताते हैं कि सामान्य दिनों में जेद्दा जाने व आने का किराया करीब चालीस से पैतालीस हजार रुपये लगता है जबकि हाजियों को एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ रुपये खर्च करना पड़ता है और इसमें भी सरकार कहती है कि हाजियों को सब्सिडी दी जा रही है. प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर यह कैसी सबसिडी है कि सामान्य दिनों की अपेक्षा दो गुना से भी अधिक किराया लगता है?

इसके अलावा बिहार से जाने वाले हाजियों को अरब में खर्च करने के लिए जो राशि दी जाती है इसमें भी काफी भेद–भाव होता है. बिहार के हाजियों को 1900, गुजरात के हाजियों को 2500 व यूपी के हाजियों को 2100 रियाल खर्च करने के लिए मिलते हैं. जब कि श्रीनगर (एक लाख 63 हजार 350रूपये) के बाद सब से अधिक राशि बिहार के हजयात्री अदा करते हैं. वहीं यात्रा पर जाने के तीन दिन पहले चयन की सूचना दी जाती है. सीट की भी सूचना उसी समय दी जाती है जब जाने का समय काफी कम रहता है. जब हजयात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया की सारी शर्तें मानकर हज यात्रा करते हैं तो फिर उनकी सुविधाओं में कटौती नहीं होनी चाहिए और सभी के साथ एक बराबर व्यवहार होना चाहिए. ऐसी परिस्थिति में लोग कोई शिकायत भी नहीं कर पाते हैं. हजयात्री के लिए सरकारी खर्च पर विभागीय रसूखदारों के रिश्तेदारों को खुद्दाम बनाकर भेजा जाता है जिनका मकसद खिदमत करना नही बल्कि नाजायज तौर पर तफरीह मात्र होता है. कुछ खादिम कथित आकाओं के चहेतों को मिलते है. दिगर हजयात्रियों का कोई पुरसान–ए–हाल भी नही होता. इधर अधिवक्ता अल्हाज इस मामले में हज कमेटि ऑफ इंडिया को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि हाजियों को यहां ठगने व उनका दोहन करने की परंपरा सी हो गयी है. उनका मानना है कि सरकार अगर इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराती है तो अनेक चौंकाने वाले तथ्य सामने आयेंगे और हज कमेटी के कई अधिकारी बेनकाब होंगे. दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध समाजिक कार्यकर्ता व शबाब संस्था के संस्थापक अध्यक्ष साजिद रजा इस मुद्दे पर सरकार की नीति का दोष बताते हैं और कहते हैं कि सरकार केवल झूठ बोलकर मुसलमानो को गुमराह करती है.

अगर पूर्व में सरकार ने इस पर ध्यान दिया होता तो तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता और इस तरह से हज यात्री शोषण का शिकार नही होते. वहीं प्रसिद्ध शायर व पत्रकार गुलरेज शाहजाद व ओजैर अंजुम इस मामले में पूर्व की सरकारों की व्यवस्था पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हज यात्रियों की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है और उन्हें जान–बूझ कर परेशान किया जाता रहा है. हालाकि इस बार भी हज यात्रा की तैयारी जोरों पर है और टीकाकरण का काम चल रहा है. केन्द्र में व्यवस्था बदली है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री हैं. नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हज यात्रियों के साथ होने वाले भेद–भाव व अमानवीय व्यवहार में कमी आती है या सारी व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी, यह बात देखने वाले होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी : आंदोलन का केंद्र बन रहा नगर परिषद कार्यालय

तकरीबन एक सौ तीस साल पूर्व सन 1882 में जब सीतामढ़ी नगरपालिका की नींव पड़ी थी, तो आम नागरिकों की सुविधा का भरपुर ख्याल रखा गया था, लेकिन आज नगर परिसद का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी यह जन समस्याओं का निदान कर पाने में विफल साबित हो रही है. 28 वार्डों में संपन्न सीतामढ़ी नगर परिषद के कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल खडा किए जाते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन शायद ही कभी मामले को गंभीरता से लिया है. आलम यह है कि अब शहर की जनता सभापति, उपसभापति व कार्यपालक पदाधिकारी का घेराव तक करने से परहेज नही कर रही है ...

वाल्मीकि कुमार

सड़क, नाला, रोशनी, पेयजल, शौचालय एवं शिक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य माना गया है. सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रति वर्ष मोटी रकम व्यय की जाती है. कोई ऐसा साल नहीं जब उक्त योजनाओं के तहत कार्य नहीं कराया जाता हो. बावजूद इसके सीतामढ़ी नगर परिषद क्षेत्र की जनता को समस्या निदान के लिए जिला प्रशासन से लेकर नगर परिषद तक का परिक्रमा और उसके साथ आंदोलन करने की विवशता बनी है. और बातों को छोड़ भी दें, तो शहर से जल निकासी की समस्या पिछले तकरीबन डेढ़ दशक से गंभीर चुनौती बनी है. समस्या निदान की कवायद में प्रति वर्ष लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, लेकिन कमीशन–खोरी व भ्रष्टाचार के पहिया पर सवार नगर परिषद कार्यालय किसी भी योजना का सही कार्य करा पाने में सफल नहीं हो पा रही है. समय कर का भुगतान करने वाली जनता शहर में रह कर भी देहात से बदतर जीवन जीने को विवश है. प्रति वर्ष बरसात आने के साथ ही शहर के गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों का जहां जीना मुहाल हो जाता है, वहीं व्यवसायी वर्ग के लिए सामानों का रख रखाव मुश्किल साबित होने लगता है. मासूम बच्चों की पढ़ाई एवं वृद्धों का इलाज तक मुश्किल हो जाता है. कारण कि शहर के कुछ वार्डों में दो से ढ़ाई फीट तक जल जमाव आम बात हो गई है. ऐसा भी नहीं है कि यह मसला जिला प्रशासन अथवा नगर परिषद कार्यालय तक ही सिमटा है.

बताया जाता है कि करीब दो साल पूर्व भाजपा के विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद ने जब मामले को परिषद के सदन में उठाया था, तब सरकारी फरमान पर जिला प्रशासन व नगर परिषद भी हरकत में आ गया था, लेकिन मामले को टालने में माहिर प्रशासनिक तंत्र की लापरवाह कार्यशैली का आलम है कि अब तक सरकारी फरमान पर अमल नहीं किया जा सका है. अब एक नजर विधान परिषद के फरमान पर डालना जरूरी है. बात फरवरी 2012 की है. विधान पार्षद ने परिषद में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सीतामढ़ी नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत स्थित नासी नाला के अतिक्रमण का सवाल उठाया था. तब बिहार सरकार के तत्कालीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रमई राम ने महज दो माह के अंदर नासी नाला को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश सीतामढ़ी डीएम को देने की जानकारी 27 फरवरी 2012 को विधान पार्षद को दी थी. 28 फरवरी को विभाग के प्रधान सचिव डॉ सी अशोकबर्द्धन ने डीएम सीतामढ़ी को एक पत्र प्रेषित कर नासी नाला के अतिक्रमित भाग को दो माह के अंदर मुक्त करा कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा था. इसकी प्रतिलिपी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सीतामढ़ी को भी दी गयी थी.

12 मार्च 2012 को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता सीतामढ़ी को एक पत्र प्रेषित कर नासी नाल के अतिक्रमित भाग के मापी के लिए एक अमीन की प्रतिनियुक्ति कराने का आग्रह किया था, लेकिन अमीन की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई, लेकिन कागजी प्रक्रिया का दौर जारी रहा. 20 मार्च 2012 को जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी ने अपर समाहर्ता सीतामढ़ी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर को पत्र देकर 31 अक्टूबर 2009 को संपन्न मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की जिला संचालन समिति की बैठक में अतिक्रमण मुक्ति को लेकर लिए गए निर्णय के आलोक में नासी नाला को अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधी पत्र जारी किया था. निर्देश अनुपालन में हो रहे विलंब को गंभीरता से लेते हुए 25 अप्रैल 2012 को समाहर्ता ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को पत्र देकर अतिक्रमण हटाने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की थी. जिसके लिए सरकार से स्मार पत्र भी प्राप्त होना बताया गया था. 3 अप्रैल 2012 को एसडीओ सदर ने भी कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र देकर मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के जिला संचालन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में शहर के जानकी स्थान के समीप से लखनदेई नदी तक नासी नाला स्थल का नापी एवं सीमांकन करा कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने को कहा था. तब 23 जून 2012 को कार्यपालक पदाधिकारी ने एसडीओ सदर को पत्र के माध्यम से बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार पब्लिक लैंड इनक्रौचमेंट एक्ट का हवाला देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी को अतिक्रमण हटाने हेतु अधिकृत नहीं किए जाने की जानकारी देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था. साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश मांगा था.

6 अगस्त 2012 को कार्यपालक पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी डुमरा को एक पत्र भेज कर उक्त निर्देश के आलोक में अतिक्रमित भू–भाग को खाली कराने की सूचना नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिये जाने की जानकारी दी. साथ ही आगे की कारवाई का आग्रह करते हुए नापी प्रतिवेदन व नक्शा भी भेजा था. इसकी जानकारी अपर समाहर्ता व एसडीओ सदर को भी दी थी. बताया जाता है कि 28 अप्रैल 2012 से लेकर 19 जून 2012 तक नगर परिशद कार्यालय द्वारा शहर के करीब आधा दर्जन वार्डों के 51 अतिक्रमणकारियों की सूचि सौंपते हुए तकरीबन पौने 6 हजार वर्ग फीट नासी नाला की जमीन का अतिक्रमण किया जाना बताया था. यह भी बताया गया था कि वार्ड संख्या 8 में नासी नाला की जमीन पर ही सुलभ शौचालय है. वार्ड संख्या 11 एवं 16 में विन्ध्यवासिनी देवी व सुभद्रा देवी ने नासी की जमीन को सर्वे में अपने नाम पर करा लिया है. जबकि वार्ड संख्या 16 में ही नासी की जमीन को सर्वे में रैयती कर दिया गया है, लेकिन उक्त जमीन के अंदर सरकारी हयूम पाईप अब भी मौजूद है. उतना के बाद लगभग यह साफ हो गया है कि नापी प्रक्रिया के दो साल बाद तक इस दिशा में पहल का मौका अंचल अधिकारी नहीं निकाल सके है. जबकि प्रति वर्ष बरसात के दिनों में शहर के कई वार्डों में लोगों का रहना मुहाल हो रहा है. समस्या की गंभरता को लेकर अक्सर आक्रोशित लोगों की भीड़ नगर परिशद कार्यालय से लेकर शहर की सडकों तक प्रदर्शन से बाज नही आ रहे है. पिछले दिनों व्यवसायी संघ सीतामढी के तत्वावधान में नगर परिषद कार्यालय पर एक दिवसीय धरना–प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. संघ के अध्यक्ष निर्मल कुमार वियाहुत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संरक्षक राधे श्याम शर्मा, उपाध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद, गौरी शंकर प्रसाद, सचिव रितेश कुमार सिकारिया, सह सचिव जगदीश चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिल भावसिंका व मीडिया प्रभारी कैलाश हिसारिया के अलावा जर्नादन भरतिया, डॉ विजय सर्राफ, आलोक कुमार, नंदकिशोर प्रसाद, अरविंद कुमार व नरोत्तम व्यास ने गुदरी बाजार एवं गोला रोड के करीब 3 सौ व्यवसायियों ने प्रदर्शन के बाद मांग पत्र नगर परिषद के सभापति सुवंश राय, उप सभापति युगल किशोर प्रसाद व कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण मुरारी को सौपा. व्यवसायियों ने एक माह के अंदर जल जमाव की समस्या का निदान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी. व्यवसायी संघ के सदस्य व नगर परिषद के पदाधिकारियों के बीच चल रही वार्ता के क्रम में सभापति व कार्यपालक पदाधिकारी के बीच मतभेद का झलक भी लोगों को देखने को मिला था. तब जब सभापति सुवंश राय ने साफ लहजे में कार्यपालक पदाधिकारी पर नकारा होने का आरोप लगा दिया. हैरत की बात तो यह कि कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ कर लोगों को बता दिया कि कार्यालय में कोई फाईल ही नहीं है. अब ऐसे में एक सवाल लोगों के जेहन में कौंधने लगा है कि आखिर फाईल किसके आलमारी में आराम फरमा रहा है.

प्रदर्शन करते शहर के व्यावसायी

अब देखना यह है कि सरकारी फरमान के बाद पिछले दो सालों से थमी प्रशासनिक प्रक्रिया को अंचल अधिकारी गति दे पाते हैं अथवा लोगों को अगले आंदोलन की तैयारी का मौका मिलता है. इतना तो तय लगने लगा है कि गंभीर बन चुकी जल जमाव की समस्या से निजात को लेकर शहर के लोग कभी भी उग्र तेवर अख्तियार कर प्रशासन की बेचैनी बढ़ा सकते है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना

मां वैष्णों देवी सेवा मंडल के तत्वावधान में सात दिवसीय तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया. इसमें सीतामढ़ी जिले के करीब एक सौ से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. सेवा मंडल के अध्यक्ष विशाल कुमार ने बताया कि 19 अगस्त को तीर्थ यात्रियों का जत्था वैष्णों देवी यात्रा के लिए निकला है. सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक जानकारी दे दी गयी है. बताया कि जिले में अमन व खुशहाली के साथ राष्ट्र की मजबूती के लिए तीर्थ यात्री माता के दरबार में अपना फरियाद करेंगे. सेवा मंडल प्रति वर्ष श्रद्धालुओं को माता के दरबार में हाजिर करने का हर संभव प्रयास करता रहेगा. **– विम्मी**

महादलितों को बासगीत परचा

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें जदयू विधायक गुड्डी देवी ने 41 महादलित परिवारों के बीच बासगीत परचा का वितरण किया. मौके पर विधायक ने कहा कि पूर्व सीएम नीतीष कुमार के सोंच का परिणाम है कि आज पिछडे वर्ग को वाजिब हक की प्राप्ति हो रही है. राज्य सरकार गरीबों के हित में हर संभव कदम उठा रही है. वरिष्ठ जदयू नेता राजेश चौधरी ने कहा कि आजादी के साढ़े छह दशक बाद भी गरीबों को वाजिब हक नही मिल सका था. परंतु पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब सभी के लिए रास्ता बना दिया है. सीओ समीर कुमार ने भरोसा दिलाया कि इंदिरा आवास से वंचित लोगों को योजना का लाभ दिलाया जायेगा. कार्यक्रम में जगतु मांझी, बबीता देवी, कमला देवी, इनरदेव मांझी, हरेंद्र मांझी, जयमन देवी, पार्वती देवी, सीता देवी, पुतुल देवी, अनिता देवी व आरती देवी समेत अन्य लाभार्थी व आम लोग मौजूद थे. **– विभा**

वक्फ संपत्ति पर मंत्री सख्त

राज्य में वक्फ की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करायी जायेगी. इसकी शुरुआत सासाराम से होगी. वक्फ की संपत्ति को कोई जबरन दखल करता है, तो इससे वक्फकर्ता की आत्मा दुखी होती है. उक्त विचार स्थानीय शाह जुमा मुहल्ला में जिला औकाफ कमेटी रोहतास और शेरशाह सूरी मेमोरियल ऑर्गनाईजेशन के संयुक्त तत्वाधन में ईद मिलन, आवामी इर्दू निफाज़ तथा वक्फ संपत्ति संरक्षण विषयों पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नौशाद आलम ने व्यक्त किये. उन्होंने ने कहा कि हाल ही में वक्फ के नियम के कुछ नवीन संशोधनों के बाद अब वक्फ की संपत्ति कोई हड़प नहीं सकेगा. चाहे भूमि रजिस्ट्री हो जाए. अधिगृहित हो जाए तब भी वक्फ को वापिस हो जायेगी. यहां तक के वक्फ की भूमि पर सरकार भी दखल नहीं रख सकती. अगर अत्यावश्यक अनिवार्य कारणों से भूमि अधिग्रण करना भी हो तो, इसके लिये बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना से अनुमति लेना अनिवार्य है. मंत्री ने कहा कि सासाराम में अरबों रुपये की जायदाद पर अतिक्रमण कार्यों ने अवैध कब्जा कर लिया है. **–अशरफ अस्थानवी**

हुंडई की नई कार लांच

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने नई एलिट आई 20 को बाजार में पेश कर दिया है. प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों में पैमाना स्थापित करने के उद्देश्य से एलिट आई 20 का देश में वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया गया. यह वाहन पेट्रोल एवं डीजल इंजनों के विकल्प के साथ उपलब्ध है. इसकी पेट्रोल एवं डीजल इंजनों के विकल्प के साथ उपलब्ध है. इसकी पेट्रोल इंजन की क्षमता 1,977 सीसी शक्ति 83 पीएस एवं 11.7 टार्ग (केजीएम) है. इसके डीजल इंजन की क्षमता 1,396 सीसी, 90 पीएस एवं 22.4 टार्क (केजीएम) है. एलिट आई 20 को पेश करते हुए एचएम आईएल के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बीएस सेव ने कहा कि एलिट आई 20 एक विश्वस्–तरीय उत्पाद है. जिसे बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है. साथ ही उच्चस्–तरीय इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया ताकि उम्मीदों से परे इसकी वैल्यू वसूल की जा सके. **–चित्रा भारती**

सभी वर्गों के लिए टीवीएस जूपिटर

दो चक्का वाहन में टीवीएस स्कूटी देश की एक प्रतिष्ठित ब्रांड है. टीवीएस स्कूटी पर आम धारणा यह है कि ये महिलाओं के लिए है लेकिन कंपनी ने यह चैलेंज किया है कि टीवीएस जूपिटर सभी वर्गो के के लिए हैं चाहे वह किसी भी उम्र के क्यों न हों. कंपनी के अधिकारी के अनुसार टीवीएस जूपिटर अन्य से बेहतर है. इसकी इंडीकेटर लाइट काफी आकर्षक है. इसमें 110 सीसी का पेट्रोल इंजन है. इसका पावर 8 पीएस एवं टॉर्क 8 एन एम है. इसका माइलेज 62 किलो प्रति लीटर है. **– निक्की सिंह**

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मना

पूर्वी चंपारण जिले में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर हिन्दू धर्मावलम्बियों के घरों में भगवान श्री कृष्ण की झांखी निकाली गयी और झूला सजाकर इनकी पूजा की गयी. मधुबन प्रखण्ड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस अवसर पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये. सीआरपीएफ कैंप में श्री कृष्ण पूजनोत्सव के साथ–साथ भण्डारा का आयोजन किया गया. घनश्याम दास मंदिर परिसर में वृन्दावन के कलाकारों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गयीं और रंगा–रंग कार्यक्रमों की धूम मची रही. वहीं श्री रामजानकी मंदिर में राजेश सलमपुरिया के सौजन्य से व वाजितपुर स्थित श्री राम जानकी परिसर में पूजा अर्चना की गयी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ–साथ मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ. ग्रामीणों ने बताया कि मटकीफोड़ कार्यक्रम में तीस फीट की उंचाई पर एक मटका टांगा गया था जिसे मानव श्रृंख्ला बनाकर फोड़ा गया. मानव श्रृंख्ला में रविरंजन झा, उमेश प्रसाद, रौशन, अजय, सुजीत, चंदन, रविन्द्र, कंचन झा, दीनदयाल आदि ने हिस्सा लिया. **– इन्तेजारुल हक**

पावर स्टेशन का निर्माण अधर में

चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड में वर्षों से पावर सब स्टेशन का कार्य अधर में लटका है. प्रखंड के ग्रामीणों को कहना है कि विधायक अपना गृह प्रखण्ड में एक पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा सकें . आजसू के चतरा विधान सभा प्रभारी अशोक गहलोत ने बताया कि बरबा कोचवा के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है. ■

– अमरेन्द्र प्रताप

महाबोधि मंदिर देश के उन चार मंदिरों मे शामिल हो गया है, जिसकी आमदनी सर्वाधिक है. आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी, जम्मू के माता बैष्णों देवी और शिरडी के साई बाबा के बाद सबसे अधिक दान प्राप्त करने वाला बन गया है महाबोधि मंदिर. महाबोधि मंदिर को इस वर्ष 106 करोड़ 99 लाख रुपये की आमदनी हुई.

सीतामढ़ी : पथ परिवहन निगम का हाल हुआ खस्ता

वाल्मीकि कुमार

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सीतामढ़ी इकाई अब बंदी के कगार पर पहुच गयी हैं. महज तीन दर्जन कर्मियों के भरोसे पर आधा दर्जन बसें ही जिले में चलायी जा रही हैं. सड़कों का जाल बिछाने वाले प्रतिनिधियों की सजगता का आलम है कि सरकारी राशि से निर्मित तकरीबन सभी सड़कों पर निजी बसों का संचालन ही नियमित कराया जा रहा है. निगम के पास पर्याप्त बस नहीं होने के कारण सभी रूट निजी वाहनों से भरे हैं, वहीं विभाग को प्रति माह लाखों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है...

आम-आवाम को बेहतर सुविधा मुहैया कराने एवं सरकारी राजस्व में बढोत्तरी का लक्ष्य तकरीबन सभी सरकार की प्रमुखता सूचि में रही है. लक्ष्य प्राप्ति को लेकर विभागीय व सरकारी स्तर पर कवायद की जाती है, परंतु सार्थक पहल का अभाव होने के कारण सबकुछ बेकार साबित होने लगा है. तकरीबन दो दशक पूर्व तक सीतामढ़ी जिले में पथ परिवहन विभाग की स्थिति बेहतर मानी जाती रही. वर्ष 2004 के करीब सरकारी निर्णय के आलोक में विभागीय स्तर पर सीतामढ़ी डीपो को एक दर्जन से अधिक नई बसों को मुहैया कराया गया. तब कई रूटों पर सरकारी बस दौड़ने लगी हैं. बाद में हाल ऐसा होना शुरू हुआ कि अब मुश्किल से आधा दर्जन सरकारी बसें ही जिले में रह गयी हैं. विभागीय कर्मियों की मानें तो फिलहाल सीतामढ़ी डीपो में 6 चालू हालत में और 18 बस ठप पडी है. इनमें बेला-पटना, बेला-मुजफ्फरपुर रूट पर एक-एक, सीतामढ़ी- पटना पर एक और सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रूट पर महज 3 बसों का परिचालन ही नियमित कराया जा रहा है. नतीजतन आम यात्रियों को निजी बसों से यात्रा करनी पड़ रही है. सीतामढ़ी डीपो के सही संचालन में कुल 34 कर्मियों की तैनाती की गयी है. इसमें चालक दल के 9 सदस्य भी शामिल हैं. जिसमें संविदा पर नियुक्त 7 चालक हैं. प्रतिष्ठान अधीक्षक व फोरमैन अधिकतर मुजफ्फरपुर में ही रहा करते हैं. बताया जाता है कि सरकारी व विभागीय स्तर पर पथ परिवहन निगम को निजीकरण के क्षेत्र में भेजने की तैयारी की जा रही है. जिसके कारण डीपो के नाजुक होते हालात को नजरअंदाज किया जा रहा है. कर्मियों का कहना है कि अगर विभागीय स्तर पर सीतामढ़ी डीपो को कम से कम 50 बस मुहैया करा दी जायेगी, तब बेहतर राजस्व की प्राप्ति संभव है. वहीं दूसरी ओर जिले के अलग-अलग स्थानों से आवागमन करने वालों को भारी राहत भी मिल सकती है.

अब सवाल यह उठता है कि कभी एक साथ दर्जनों बसों का संचालन कराने वाली सीतामढ़ी जिला स्थित डीपो का हाल ऐसा हुआ कैसे? बताया जाता है कि पिछले तकरीबन एक दशक से विभागीय स्तर पर पथ परिवहन निगम को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है. नतीजा है कि एक ओर सरकारी राजस्व का व्यापक नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर गांव के गरीबों को आवागमन की गंभीर चुनौती का सामना करने की विवशता बनी है. अधिकांश रूटों पर सरकारी बस उपलब्ध नहीं रहने के कारण आम लोगों को निजी वाहन संचालकों की मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. पूर्व में जिले में सड़कों की स्थिति बेहतर नहीं थी, तब बहुत ही कम रूटों में पर्याप्त वाहनों का परिचालन हुआ करता था. जब सड़के बेहतर हुईं तो छोटे-बड़े वाहनों की संख्या में इजाफा होने लगा. शायद ही कोई ऐसा रूट होगा जिसमें वर्तमान में कम से कम टेंपो का परिचालन भी नहीं हो रहा हो. आवागमन को लेकर अब से पहलेतक स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस दिशा में समुचित पहल नहीं की. सड़क, नाला, पुल, पुलिया समेत अन्य निर्माण का शिलान्यास व उद्घाटन ही प्रतिनिधियों का अहम दिनचर्या रही है. किसी ने भी सड़क निर्माण के साथ आवागमन की सुविधाओं पर ध्यान देना मुनासिब नही समझा. जिसके कारण जिले के अधिकांश रूटों पर निजी वाहन चालकों का दबदबा कायम है. जानकारों की मानें तो अगर विभागीय स्तर पर जर्जर हो चुकी बसों की नीलामी कर दी जाती है तो दो फायदे हो सकते हैं. एक तो यह कि स्थानीय डीपो में बर्बाद हो रही बसों से कुछ नयी बसों की खरीदारी की जा सकती है. वहीं दूसरी ओर सोनबरसा, भिट्ठा मोड़ व बैरगनिया समेत अन्य स्थानों से नियमित आवागमन करने वाले लोगों को नीजि वाहन संचालकों की मनमानी से निजात भी मिल जायेगा. बताया जाता है कि नीलामी को लेकर विभागीय स्तर पर बात तो चलती है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का सार्थक पहल होता नही दिख रहा है. जहां तक कर्मचारियों की स्थिति का सवाल है तो अब तक उन्हें को चतुर्थ श्रेणी वेतन का ही भुगतान किया जा रहा है. इसके कारण बिहार राज्य पथ परिवहन में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति बदतर बनी है.

डीपो में बेकार होती बसें

भारत- नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी जिले से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अन्य स्थानों के लिए आवागमन करते हैं. मिनट दर मिनट वाहनों का परिचालन हो रहा है. परंतु अधिकांश रूट पर अब तक लोगों को सरकारी बस की सुविधा नसीब नहीं हो सकी है. नतीजतन निजी वाहनों से यात्रा की विवशता बनी है. आम लोगों का मानना है कि भले ही निजी वाहन संचालकों द्वारा किराये की वसूली मनमानी की जा रही है. परंतु ससमय यात्रा के लिए फिलहाल निजी बस ही सहारा है. अगर सरकार निजी क्षेत्र के हवाले ही परिवहन निगम को करने की सोच रही है तो उसे इस क्षेत्र में ही बिना समय गंवाये फैसला लेना चाहिए, ताकि लोगों को सभी स्थानों से नियमित बस सेवा सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर निर्धारित किराये के साथ उपलब्ध हो सके. अगर ऐसा नहीं तो फिर खस्ताहाल हो चुकी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को सरकारी स्तर पर विभागीय संजीवनी देकर नये अंदाज में सड़क पर बसों को लाना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

फिर विवाद में महाबोधि मंदिर

बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की आय से बोधगया में अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की मांग की हैं. उन्होने कहा हैं कि भारत के दूसरे बड़े मंदिरो की समिति की ओर से दान मे मिली राशि से कल्याणकारी कार्य हो रहा हैं. महाबोधि मंदिर की आय में बढ़ोतरी तो हो रही हैं.

सुनील सौरभ

दुनियाभर के बौद्ध धर्म अनुयायियों के आस्था केन्द्र वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि मंदिर को लेकर पिछले एक साल में काफी विवाद रहा है. गत वर्ष जुलाई माह में महाबोधि मंदिर में सिरियल बम ब्लास्ट की घटना हुई. इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर मंदिर के सामने से हटाई गई दुकानों दुकानों को लेकर काफी हंगामा होता रहा. लेकिन ताजा विवाद का कारण महाबोधि मंदिर की एक बड़ी उपलब्धि को लेकर है. महाबोधि मंदिर देश के उन चार मंदिरों मे शामिल हो गया है, जिसकी आमदनी सर्वाधिक है. आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी, जम्मू के माता वैष्णों देवी और शिरडी के साई बाबा के बाद अधिक दान प्राप्त करने वाला यह चौथा मंदिर बन गया है. महाबोधि मंदिर को इस वर्ष 106 करोड़ 99 लाख रुपये की आमदनी हुई. परन्तु इतनी आमदनी के बावजूद महाबोधि मंदिर की ओर से जनसरोकार या धर्मार्थ कोई कार्य नहीं किये जाते हैं, विवाद का कारण यही है. तिरुपति बाला जी की आय 650 करोड़ सलाना है, माता वैष्णो देवी की 500 करोड़, साई बाबा शिरडी की 250 करोड़ रुपये सालाना की आमदनी है. इन मंदिरो की ओर से बड़ी-बड़ी धर्मशालाएं, अस्पताल, शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ जनसरोकार से जुड़े अनेक कार्य किये जा रहे हैं. लेकिन महाबोधि मंदिर की आमदनी से देसी-विदेशी पर्यटकों के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. देष के बड़े मंदिरो की बात तो छोड़ दें तो पटना के महावीर मंदिर की ओर से ही महावीर आरोग्य संस्थान के अलावा अन्य धर्मार्थ कार्य किये जा रहे हैं. जिसका लाभ समाज के सभी तबके के लागों को मिल रहा है.

महाबोधि मंदिर की दान में प्राप्त राशि का उपयोग मंदिर प्रबंध कारणी समिति की ओर से किया जाता है. लेकिन इस समिति को बोधगया आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की कोई चिन्ता नहीं रहती है. समिति की ओर से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए भी न ही किसी धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान का संचालन किया जाता है. मंदिर प्रबंध कारणी समिति के परिसर मे सिर्फ दिखावे के लिए एक अस्पताल का संचालन किया जाता है. लेकिन यहां कोई स्थायी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है. बताया

महाबोधि मंदिर की दान में प्राप्त राशि का उपयोग मंदिर प्रबंध कारणी समिति की ओर से किया जाता है. लेकिन इस समिति को बोधगया आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की कोई चिन्ता नहीं रहती है. समिति की ओर से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए भी न ही किसी धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान का संचालन किया जाता है. मंदिर प्रबंध कारणी समिति के परिसर मे सिर्फ दिखावे के लिए एक अस्पताल का संचालन किया जाता है.

जाता है कि एक दानदाता ने लोगो की निशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक एंबुलेंस दी थी लेकिन मंदिर प्रबंध कारणी समिति इसका भी उपयोग नहीं कर सकी. बताया जाता है कि दानदाता किसी मंदिर में इसलिए दान देते हैं कि इस राशि से धर्मार्थ एवं जन कल्याण का कार्य हो. विदेशी पर्यटकों का मानना है कि महाबोधि मंदिर में श्रद्धालुओं को वैसी सुविधा नहीं मिलती है, जैसी की उसकी ख्याति है. कई बार महाबोधि मंदिर प्रबंध कारणी समिति की ओर से बोधगया में सुपर स्पेसिएलिटी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके अलावा बैठक मे अनेक प्रस्ताव पारित होते हैं. लेकिन अमल नहीं हो पाता है. देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया है कि यहां ठहरने के लिए कोई धर्मशाला नहीं बनी है, जहां कम खर्च में श्रद्धालु ठहर सकें. होटल काफी मंहगे होने के कारण लोग महाबोधि मंदिर मे दर्शन कर तुरंत लौट जाते हैं. काफी दूर से आने के कारण एक रात गुजारने की उनकी इच्छा रहती है, किन्तु मंहगे होटल के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है. महाबोधि मंदिर को दान मे मिली राशि का उपयोग सरकारी तथा गया जिला प्रशासन के कार्यक्रम में किया जाता है. प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले बौद्ध महोत्सव में कुछ राशि खर्च होती है. समिति की ओर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका से लेकर प्रशासनिक बैठकों में नाश्ता, खाना पेयजल आदि का खर्च प्राप्त दान राशि में से दिखाया जाता है. जबकि कई आयोजनों मे किसी देश के दानदाता राशि खर्च करते हैं. जनसरोकार के कार्यों में महाबोधि मंदिर समिति की उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 17वें करमापा उज्ञेय त्रिनले दोरजी ने बोधगया में अस्पताल बनाने के लिए महाबोधि मंदिर प्रबंध समिति को सहयोग करने को कहा था. लेकिन प्रबंध समिति ने इस बड़े कार्य के लिए पहल ही नही की. 2007-08 मे महाबोधि मंदिर की आमदनी साढ़े छह करोड़ थी. 2014 मे यह राशि बढ़कर करीब 20 करोड़ हो गयी. जिसमें 4.19 करोड़ चैरिटी चेक से, 4.70 करोड़ रसीद द्वारा डोनेशन से, 2.2 करोड़ कैमरा, बटरलैम्प,रेन्ट मेडिटेशन से, 38 लाख बैंक सूद से तथा 9 करोड़ रुपया अन्य माध्यम सें प्राप्त हुआ है. वहीं थाईलैंड के राजा भूमिवोल अदुल्यादेज की ओर से महाबोधि मंदिर के गुम्बद पर लपेटने के लिए 289 किलो स्वर्णपत्र दान में दिया गया. जिसकी कीमत 86 करोड़ 70 लाख रुपये आंकी गयी. इस प्रकार महाबोधि मंदिर की आमदानी इस वर्ष 106 करोड़ 99 लाख हो गयी. लोगों की मांग है कि देश के अन्य मंदिरो की तरह महोबोधि मंदिर को भी जनसरोकार के कार्य करने चाहिए.

बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की आय से बोधगया में अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की मांग की है. उन्होने कहा है कि भारत के दूसरे बड़े मंदिरो की समिति की ओर से दान मे मिली राशि से कल्याणकारी कार्य हो रहा है. महाबोधि मंदिर की आय में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन तीर्थयात्रियों, पर्यटकों व स्थानीय लोगो के लिए कोई अस्पताल और न ही कोई शिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

01 दिसंबर-07 दिसंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार अचानक सक्रिय

सरकारी आदेश सियासी चाल है

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में अब नए किस्म का साम्प्रदायिक बखेड़ा शुरू होने वाला है. 2009 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर किए गए धार्मिक प्रकृति के अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है. ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्देश 2014 के आखिरी में जारी किया है जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तकरीबन दो-ढाई साल ही शेष बचे हैं. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि कहीं सोचे-समझे इरादे से यह निर्देश तो नहीं जारी किया जा रहा! इस निर्देश का अगर प्रदेश में अक्षरशः पालन शुरू हो गया तो यूपी में फिर से साम्प्रदायिक तनाव के सृजन को आप सुनिश्चित मानिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्देश जारी करते हुए प्रशासन को किसी भी समुदाय के साथ तनाव में नहीं पड़ने की खास हिदायत देने की औपचारिकता भी निभाई है, लेकिन प्रशासन के ही आला अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक प्रकृति का अतिक्रमण हो या व्यवसायिक प्रकृति का, उसे हटाने के लिए बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा और इससे पैदा होने वाले तनाव को टाला नहीं जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले के अनुपालन का 2014 में निर्देश जारी करने की वजह भी प्रशासनिक अधिकारियों को समझ में नहीं आ रही है.

बहरहाल, पहले उत्तर प्रदेश सरकार का वह आदेश देखते चलें कि उसमें कहा क्या गया है. प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन की तरफ से 14 नवंबर 2014 को निर्देश जारी किया गया है. उसमें सभी मंडलायुक्तों, जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रकृति के अतिक्रमण को हटाए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट 29 सितम्बर 2009 के फैसले का वे अनुपालन सुनिश्चित कराएं. शासन ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध धार्मिक अतिक्रमण की पहचान करने के लिए टीमें गठित करने और अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित करने को कहा है. टीम में राजस्व, पुलिस एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा. टीम द्वारा चिन्हित किए गए अवैध धार्मिक अतिक्रमणों का सत्यापन कराने के बाद उन अवैध धार्मिक अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि अवैध धार्मिक निर्माण के ध्वस्तीकरण के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि प्रशासन एवं सम्बद्ध समुदाय के बीच यथासम्भ वटकराव की स्थिति न पैदा हो. अतिक्रमण हटाए जाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल आवश्यक उपकरणों और संसाधनों से लैस होकर तैनात हो. सरकारी निर्देश की इन पंक्तियों के मर्म आप अच्छी तरह समझ सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में अवैध धार्मिक स्थलों की जिलावार संख्या देखते चलें, लेकिन उसके पहले यह समझते चलें कि यह सरकारी आंकड़ा है, यानी सरकार को पहले से पता है कि प्रदेश में अवैध धार्मिक अतिक्रमणों की संख्या कितनी है. फिर नए निर्देश के पीछे कोई सियासी तिकड़म नहीं है, तो फिर इसका औचित्य क्या है. अवैध धार्मिक स्थलों के निर्माण में सिद्धार्थनगर जिला अव्वल है, जहां 4706 अवैध धार्मिक स्थल हैं.

अवैध धार्मिक अतिक्रमणों की शिनाख्त करने के लिए टीमें गठित करने और उसके लिए तमाम जद्दोजहद करने की नए सिरे से भूमिका बनाने वाली सरकार के पास पहले से प्रदेशभर के अवैध अतिक्रमणों की सूची है, चाहे वह धार्मिक अतिक्रमण हो या व्यवसायिक. केंद्र से लेकर प्रदेश तक की खुफिया एजेंसियां समय-समय पर सरकार को खास तौर पर अवैध धार्मिक अतिक्रमणों की जानकारी देती रही हैं. अतिक्रमण कर कितने मंदिर बने या कितनी अवैध मस्जिदें खड़ी हुईं, इसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास पहले से है. कई बार अदालतों ने राज्य सरकार से प्रदेश में हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमणों का ब्यौरा भी लिया है. सरकार ने कई बार वह ब्यौरा अदालत के समक्ष प्रस्तुत भी किया है. लेकिन प्रदेश में अलग किस्म का सियासी नाटक खड़ा करने की सस्ती सियासत के लिए इस तरह का नया आदेश जारी करने का उपक्रम किया गया है. इस प्रसंग में विचित्र पहलू यह भी है कि कुछ ही दिन पहले इसके पहले के मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने मंडलायुक्त व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दो अलग-अलग समितियां गठित कर धार्मिक अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया था. लेकिन किसी भी जिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. तब जिला प्रशासनों की तरफ से शासन को यह इत्तिला की गई थी कि अवैध धार्मिक स्थल हटाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. इसे देखते हुए सरकार ने अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, या यह भी कह सकते हैं कि इसे चुनाव नजदीक आने तक के लिए मुल्तवी कर दिया था.

अभी कुछ अर्सा पहले हाईकोर्ट की तरफ से पूछे जाने पर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया था कि प्रदेश में अवैध धार्मिक स्थलों की संख्या 45,152 है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल बाद उसके अनुपालन के लिए 12 अक्टूबर 2010 को सर्कुलर जारी किया गया और कहा गया कि सार्वजनिक भूमि, सड़क व पार्क में 4 फरवरी 2010 के बाद निर्माण रोक दिए जाएं. लेकिन निर्देश के अनुपालन की दिशा में कोई काम नहीं हुआ, नतीजतन प्रदेशभर में अंधाधुंध अवैध धार्मिक निर्माण हुए. 2014 तक स्थिति भयावह हो चुकी है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी जारी ही है. अगर कुछ साल पहले के आधिकारिक आंकड़े को ही सामने रखें, तो सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थलों पर बने 45 हजार से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को अब तक क्यों नहीं हटवा पाई. क्या इसे 2015 के लिए रोक कर रखा गया था. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही ऐसे अवैध धार्मिक स्थलों की संख्या 971 है. सबसे अधिक 4706 अवैध धार्मिक स्थल सिद्धार्थनगर में हैं. सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर जब अवैध निर्माण हो रहा था तब तो प्रशासन चुप्पी साधे रहा, अब सुप्रीमकोर्ट के पांच साल पुराने आदेश के बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है. सुप्रीमकोर्ट ने 2009 में ही यह आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अथवा अन्य किसी धार्मिक ढांचे के निर्माण की अनुमति न दी जाए. सरकार ने इस निर्देश पर क्या कार्रवाई की, इसे बताने के लिए शासन का कोई नुमाइंदा आगे नहीं आ रहा. सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर पूरे पांच साल प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अवैध धार्मिक अतिक्रमणों का ब्यौरा कोर्ट को दे दिया और फिर निश्चिंत बैठ गई. विडम्बना यह है कि तब भी शासन के प्रमुख सचिव आलोक रंजन ही थे, जो आज प्रदेश के मुख्य सचिव हैं. वे फिर से पांच साल बाद वही आदेश क्यों जारी कर रहे हैं और इसके पीछे के सियासी निर्देश क्या हैं, ये तो वही बता सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में अवैध धार्मिक स्थलों की जिलावार संख्या देखते चलें, लेकिन उसके पहले यह समझते चलें कि यह सरकारी आंकड़ा है, यानी सरकार को पहले से पता है कि प्रदेश में अवैध धार्मिक अतिक्रमणों की संख्या कितनी है. फिर नए निर्देश के पीछे कोई सियासी तिकड़म नहीं है, तो फिर इसका औचित्य क्या है. अवैध धार्मिक स्थलों के निर्माण में सिद्धार्थनगर जिला अव्वल है, जहां 4706 अवैध धार्मिक स्थल हैं. इस तरह के अवैध धार्मिक निर्माणों की संख्या बनारस में 949, प्रतापगढ़ में 244, बस्ती में 456, बरेली में 929, आगरा में 536, फिरोजाबाद में 111, मैनपुरी में 133, मथुरा में 205, अलीगढ़ में 455, एटा में 426, हाथरस में 729, आजमगढ़ में 747, बलिया में 425, मऊ में 433, कांशीरामनगर में 361, इलाहाबाद में 381, फतेहपुर में 443, कौशांबी में 38, बदायूं में 804, पीलीभीत में 287, शाहजहांपुर में 253, चित्रकूट में 159, बांदा में 202, हमीरपुर में 236, महोबा में 457, बहराइच में 620, बलरामपुर में 122, संत कबीर नगर में 214, गोंडा में 1008, श्रावस्ती में 302, फैजाबाद में 1417, बाराबंकी में 511, अंबेडकरनगर में 867, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में 199, सुल्तानपुर में 174, गोरखपुर में 405, देवरिया में 448, महराजगंज में 84, कुशीनगर में 89, जालौन में 135, झांसी में 1101, ललितपुर में 835, इटावा में 295, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) में 227, कानपुर नगर में 1490, कानपुर देहात में 271, कन्नौज में 226, औरैया में 162, हरदोई में 311, लखीमपुर खीरी में 160, लखनऊ में 971, रायबरेली में 521, उन्नाव में 825, सीतापुर में 431, बागपत में 155, बुलंदशहर में 701, गाजियाबाद में 693, गौतमबुद्धनगर में 349, मेरठ में 1415 और बिजनौर में अवैध धार्मिक अतिक्रमणों की संख्या 1198 है. अवैध धार्मिक अतिक्रमणों की इस सूची में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों का स्पष्ट ब्यौरा है. लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता की वजह से हम उसका अलग-अलग ब्यौरा पेश नहीं कर रहे हैं. लेकिन प्रदेश सरकार इसी संवेदनशीलता का सियासी फायदा उठाने के इरादे से अभी अचानक इस मसले पर सक्रिय हो गई है. ■

तो क्या अखिलेश ऐसा कर पाएंगे..!

अवैध धार्मिक अतिक्रमणों का शिकार उत्तर प्रदेश कोई अकेला प्रदेश नहीं है. लेकिन दो साल के बाद चुनाव तो उत्तर प्रदेश में ही होने हैं. अवैध धार्मिक अतिक्रमणों में तमिलनाडु अव्वल है, जहां 77,450 अवैध धार्मिक स्थल हैं. राजस्थान में यह संख्या 58,253 है. मध्य प्रदेश में 51,647 अवैध धार्मिक स्थल हैं तो छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 30,000 है. गुजरात में 15,000 धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर बने हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दर्जनों धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करा कर अतिक्रमण हटवाने का आदेश दिया था. उत्तर प्रदेश सरकार के नए निर्देश से यह सवाल तो उठता ही है कि जब कट्टर छवि के नरेंद्र मोदी ने अवैध धार्मिक स्थलों को हटवाने से परहेज नहीं किया था तो क्या धर्मनिरपेक्ष छवि के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अवैध तरीके से बने मंदिर-मस्जिद ध्वस्त करा पाएंगे..?

feedback@chauthiduniya.com

मुलायम का बयान

एक से सरकार नाराज, दूसरे से मुसलमान

दीनबंधु कबीर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के दो यथार्थ बयानों ने फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया. एक विवाद पार्टी के अंदर शुरू हुआ तो दूसरा पार्टी के बाहर. पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो खुद को विवाद से अलग रखते हैं और समाधान की हिमायत करते हैं. उनका कहना है कि नेता जी बात तो सही कहते हैं, लेकिन उनकी बातों पर सुधार के बजाय विवाद करने और मुंह बिचकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है. पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी मुलायम ने कहा था कि अखिलेश सरकार के मंत्री गलत गतिविधियों में लगे हैं, तो इस पर कार्रवाई करने के बजाय गुटबाजी शुरू हो गई और कुछ निर्दोष बकरे हलाल कर दिए गए. खैर, अभी का विवाद यह है कि सपा के अभिभावक मुलायम सिंह यादव ने कह दिया कि सरकार बनते ही अखिलेश यादव ने लैपटॉप बेतहाशा बांट दिए, लेकिन उसकी तकनीक का फायदा नरेंद्र मोदी ने उठा लिया और लोकसभा चुनाव में बाजी मार ले गए. मुलायम ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता की वकालत करते हुए कहा कि पर्दा प्रथा महिलाओं के विकास में बाधा है और जो महिलाओं को पर्दे में रखता है, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए. मुलायम के ये दो बयान अलग-अलग हलकों में चर्चा में आ गए. जो निष्पक्षता से सोचते-समझते हैं, उन्होंने मुलायम के इन दोनों बयानों का मर्म समझा और जिन्हें केवल विवाद ही आता है, उन्होंने इसे विवाद के ही रूप में खड़ा भी किया.

तकरीबन आठ साल बाद हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महिला सम्मलेन में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे. उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा बांटे गए लैपटॉप को लोकसभा चुनाव में हार का कारण बताया. मुलायम ने कहा कि हम लैपटॉप के कारण चुनाव हार गए. मैंने अखिलेश से कहा था कि लैपटॉप मत बांटो. मोदी ने बड़ी चालाकी से इसी लैपटॉप पर अपनी तकरीरें और तस्वीरें डलवा दीं. हमने लैपटाप बांटा था, लेकिन उसमें चतुराई से मोदी के भाषण और फोटो डलवा दिए गए. इसकी वजह से चुनाव पर असर पड़ा. सपा सुप्रीमो का इशारा तकनीक के साथ-साथ सोशल मीडिया के मोदी द्वारा किए गए बेहतर इस्तेमाल की तरफ था. मुलायम के इस बयान पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा भी कि मुलायम सिंह यादव ने वास्तविकता स्वीकार कर ली है. लोगों को लैपटॉप तो दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें वोट के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है. कांग्रेसी सांसद संदीप दीक्षित ने भी कहा कि सपा ने लोगों को सुविधाएं तो उपलब्ध करा दीं, लेकिन उन्हें अपनी तरफ खींच नहीं सके.

उसी सम्मेलन में मुलायम ने महिलाओं की तरक्की में पर्दा प्रथा को बहुत बड़ी बाधा बताया. मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी के अभिभावक ने ऐसे बयान से उनकी नाराजगी का खतरा भी मोल ले लिया. हालांकि मुलायम ने कहा कि बदलाव के इस दौर में औरतों को पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका देने के लिए ऐसी कुरीतियां खत्म होनी चाहिए. समाज में आज भी महिलाओं का ही सबसे ज्यादा शोषण होता है. घर में भेदभाव अब भी कायम है. मुलायम ने कहा कि महिलाओं में हीनता की भावना दूर करनी होगी. महिलाओं में पर्दा एक गलत परंपरा है और इसे खत्म करना चाहिए. पुराने युगों में यह प्रथा नहीं थी. क्या सीता जी ने कभी पर्दा किया, क्या द्रौपदी कभी पर्दा करती थीं. बीच में कुछ हालात ऐसे बने कि महिलाओं को पर्दा करना पडा. मुलायम बोले कि अब तो महिलाएं वर्दी पहनकर सामने आ रही हैं. इस पर्दे की प्रथा के बारे में अब आप ही तय करें. ये कुरीतियां खत्म होनी चाहिए. पर्दा प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए. मुलायम ने पर्दा प्रथा को कुप्रथा बताते हुए इसे रोकने के लिए महिलाओं से अपील की.

लैपटॉप वाले बयान पर पार्टी के अंदर तो खूब चर्चाएं हुईं और पार्टी की नव-जमात ने मुलायम के बयान पर अपनी नाखुशी भी जाहिर की, लेकिन कोई बात सार्वजनिक नहीं हुई. लेकिन पर्दा प्रथा के खिलाफ मुलायम ने जो कहा, उसके खिलाफ फौरन ही मुस्लिम समुदाय के रूढ़िवादी विचारधारा का वहन करने वालों ने निंदा प्रस्ताव जारी करना शुरू कर दिया. जबकि मुलायम के बयान पर बुद्धिजीवियों और महिलाओं ने जमकर अपनी खुशी जताई और पर्दा प्रथा को पूरी तरह हटाए जाने की जरूरत पर जोर दिया. बनारस के मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने मुलायम के बयान को मर्यादा तोड़ने वाला बयान बता दिया और कहा कि उन्हें इसका अधिकार नहीं है. नोमानी ने कहा कि मुलायम जो कुछ बोल रहे हैं वह मजहब के दस्तूर के खिलाफ है. नोमानी का मानना है कि मजहब के दायरे और दस्तूर में रहकर भी तरक्की की जा सकती है. कई महिलाओं ने पर्दे में रहकर भी तरक्की हासिल की है. सुन्नी धर्मगुरु मौलाना इरफान मियां फरंगी महली ने भी कहा कि इस्लाम में पर्दे के जरिए मुसलमान औरतों की हिफाजत होती है. उन्होंने कहा कि मुलायम चाहते हैं कि मुसलमान औरतें भी सबके सामने आएं. उन्हें उनकी हिफाजत से क्या लेना देना, उन्हें तो सियासत से लेना देना है.

जबकि इसके विपरीत ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने कहा कि वाकई पर्दा प्रथा महिलाओं के विकास में बाधा है. महिलाओं को खुद पता है कि उन्हें अपनी मर्यादा कैसे बना कर और बचा कर रखनी है. महिलाओं पर इसे जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए. पर्दा थोपने भर से महिलाओं की कोई हिफाजत नहीं हो जाती. महिलाओं की हिफाजत दरअसल समाज के लोगों को अपनी सोच बदलने से होगी. महिलाओं को पर्दे में ढंक कर, उन्हें बंद कर रखना मध्यकालीन सोच का परिचय देता है, विकासशील बुद्धि का इससे परिचय नहीं मिलता. सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने भी मुलायम के बयान पर अपनी सहमति दर्ज करते हुए कहा कि पर्दा प्रथा पूरी तरह खत्म होनी चाहिए. इसे समाज को ही सोचना और तय करना चाहिए कि क्या पर्दा प्रथा सही है या विकास के मौजूदा दौर में यह बहुत बड़ी अड़चन है. मनकामेश्वर मंदिर की महिला महंत स्वामी देव्या गिरी ने कहा कि पर्दा प्रथा निश्चित तौर पर महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है. पर्दा प्रथा कहीं से भी स्वस्थ समाज की तस्वीर पेश नहीं करती. महिलाओं के प्रति पुरुषों के नजरिए का प्रतीक है पर्दा. पुरुष अपनी आंखों पर मर्यादा का पर्दा नहीं लगा सकते तो महिलाओं का मुंह ढंक देते हैं. वरिष्ठ पत्रकार अजमत जमील सिद्दीकी कहते हैं कि पर्दा-प्रथा कोई परम्परा नहीं है, यह तो एक मजबूरी थी. यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, यह विदेशी आक्रांताओं के आतंक और अत्याचार का सिम्बॉलिक निशान है, जिसे अब समाज से खत्म किया जाना अत्यंत जरूरी है. पर्दा-प्रथा औरत को वस्तु या प्रॉपर्टी बनाती है सहभागी नहीं बनाती. यह प्रथा औरतों को आत्महीनता और अविश्वास की तरफ ले जाती है. इसे अज्ञान या गंवारूपन की निशानी भी मान सकते हैं. ■

लेकिन छोटी बहू तो मोदी की मुरीद हैं

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहे जितना भला-बुरा कहें, पर उनकी छोटी बहू मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकतीं. अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव मोदी की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से करती हैं. पार्टी लाइन से अलग हटकर अपर्णा की सक्रियता से समाजवादी पार्टी को कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है. इसके पहले भी जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सपा हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, तब अपर्णा न केवल गोरखनाथ पीठ गईं, बल्कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी और उनकी सार्वजनिक प्रशंसा भी की थी. इस बार फिर अपर्णा यादव ने सार्वजनिक मंच पर मोदी के प्रति झुकाव जाहिर कर चर्चाओं को तेज कर दिया. उन्होंने ऑल इंडियन राइट्स आर्गनाइजेशन (एआइआरओ) के एक कार्यक्रम में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अच्छी पहल है. यह महात्मा गाधी के आदर्शों का रूप ले रहा है. अपर्णा ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए मोदी की तारीफ की और मोदी के व्यक्तित्व और उनके लोगों पर असर की तुलना महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया से की. अपर्णा ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें रोल मॉडल भी बता दिया. अपर्णा ने कहा कि मोदी के उठाए गए कदमों का आम आदमी पर असर दिख रहा है. लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद में आज उनकी ओर देख रहे हैं. इस तरह के अभियान की वजह से दुनिया में भारत की छवि साफ करने में बड़ा योगदान करेगा. अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि अच्छी चीजों की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है. अपर्णा का यह बयान ऐसे समय में आया जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने भाषणों के जरिए नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आड़े हाथों ले रहे हैं. इस वजह से अचानक ही अपर्णा का बयान चर्चा में आ गया, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने इस पर चुप्पी साधे रखी. अपर्णा ने समाजवादी सरकार की कथित बड़ी उपलब्धियों में शुमार डायल 1090 योजना की उपेक्षा करते हुए डायल-100 को मजबूत करने पर जोर दिया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सपा सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नंबर 1090 का जिक्र तक नहीं किया. अपर्णा ने कहा कि यूपी सरकार को अपने कामकाज के रवैये में बदलाव लाना होगा. सीएम को मोदी जी की तरह काम करना होगा. वह सभी के लिए रोल मॉडल बन गए हैं. सभी को ऐसे काम करने चाहिए, जो दूसरों को प्रेरित कर सकें. ■

मजदूरों का शोषण

काम बारह घंटे और भुगतान आठ घंटे का

डॉ. पंकज सिंह/नरेन्द्र कुशवाहा

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित फिरोज गांधी नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन आज पूरी तरह से राजनीति का शिकार हो चुका है. जिसका खामियाजा वहां काम कर रहे मजदूरों को भोगना पड़ रहा है. सन 1981 में स्थापित एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना का उद्देश्य रायबरेली जनपद के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और साथ ही किसानों के लिए समुचित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना था. जिससे रायबरेली के किसानों को समय पर बिजली मिल सके और वे उनसे कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ा सके. लेकिन यह महज एक सपना ही रह गया. न तो रायबरेली जनपद को एनटीपीसी से विद्युत आपूर्ति ही हो पाई और न ही बेरोजगारों को रोजगार ही मुहैया हो पाया. बताते चलें कि एनटीपीसी लिमिटेड की पूरे देश में कोयला आधारित 16, गैस एवं तरल आधारित सात, दो नवीकरण ऊर्जा प्रोजेक्ट और सात ज्वाइंट वेंचर पावर प्लांट स्थापित हैं. जिसमें रायबरेली स्थित पावर प्लांट की कुल क्षमता 500 मेगावाट है. जिसकी सप्लाई रायबरेली छोड़ कर पूरे देश में होती है. शुरूआती दौर में जो भी एनटीपीसी में काम के लिए आया तो काम जरूर मिला, लेकिन बीसों साल की नौकरी करने के बाद भी उन्हें आज तक दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की श्रेणी में ही रखा गया है. जबकि वहीं कर्मचारी एनटीपीसी के ब्वॉयलर जैसे घातक यूनिटों में काम कर विद्युत के उत्पादन में सहायक साबित हो रहे हैं. एनटीपीसी के अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से वहां संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है. इस समय एनटीपीसी में पांच यूनिटें चल रही हैं और प्रति यूनिट 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी हो रहा है और यह उत्पादित विद्युत उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से होकर दिल्ली हरियाणा जैसे प्रदेशों में बेची जा रही है. एनटीपीसी प्रतिवर्ष अपना मुनाफा भी दिखा रही है लेकिन एनटीपीसी मैनेजमेंट और उसके बिचौलिये मिलकर गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं. पिछले 25 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों से ट्रेंड कर्मचारी जैसा ही काम लिया जा रहा है, लेकिन एक अक्टूबर 2013 को सरकार की तरफ से आए निर्देश के अनुसार भी उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है. लिहाजा इस महंगाई में गरीब मजदूरों को अब परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है. इतना ही नहीं इन मजदूरों को न तो साप्ताहिक अवकाश का भुगतान किया जाता है और न ही सार्वजनिक अवकाश में भी छुट्टी दी जाती है. यदि त्यौहारों पर कोई कर्मचारी नहीं आता है तो उसके दैनिक वेतन से कटौती कर ली जाती है. किसी घटना दुर्घटना पर इन मजदूर कर्मचारियों के लिए कोई भी मेडिकल की सुविधा नहीं दी गई है. परिवार के लिए मेडिकल सुविधा की तो बात ही छोड़ दें. सबसे हास्यास्पद तो यह है कि 25 साल से काम कर रहे कर्मचारियों का एनटीपीसी प्रशासन के पास न तो कोई रिकार्ड है और न ही उन्हें कोई पहचान पत्र ही दिया गया है. अगर कुछ है तो उन बिचौलिये ठेकेदारों के पास जो हरदम संविदा कर्मचारियों को अपने रहमो-करम पर रहने का अहसास कराते रहते हैं.

गौरतलब है कि एनटीपीसी प्रतिवर्ष इन संविदा कर्मचारियों के लिए ठेकेदारी प्रथा नीति के अनुसार टेंडर निकालती है. जिसमें

जो ठेकेदार पास होता है वह संविदा कर्मचारियों का भविष्य निर्धारण करता है. कहने को तो एनटीपीसी भारत सरकार का उपक्रम है लेकिन यहां अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से गरीबों को और भी गरीब बनाने की मुहिम छिड़ी हुई है.

संविदा कर्मचारी पस्त, नियमित मस्त, ठेकेदार मदमस्त

नियमित कर्मचारियों की तुलना में संविदा कर्मचारियों की हालत पस्त है उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है. जबकि नियमित कर्मचारियों से अधिक संविदा कर्मचारियों से काम लिया जाता है. जहां कुल संविदा कर्मचारियों की संख्या दो हजार से अधिक है वहीं नियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 600 ही है. एक अक्टूबर 2013 को सरकार की तरफ से आए निर्देशों के अनुसार अकुशल (अनस्किल्ड) कर्मचारियों को 244 रुपये 70 पैसे, अर्द्धकुशल (सेमी-स्किल्ड) को 269 रुपये 17 पैसे, कुशल (स्किल्ड) को 309 रुपए तथा उच्च कुशल(हाइली-स्किल्ड) संविदा कर्मचारियों को 363 रुपये प्रतिदिन देने का प्रावधान है. जबकि इन कर्मचारियों को मात्र 130 रुपये से 150 रुपये के बीच में ही भुगतान किया जा रहा है. जबकि नियमित कर्मचारियों में निम्न कर्मचारी (चपरासी, हेल्पर आदि) का वेतनमान 45 से 50 हजार रुपये प्रतिमाह, सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों का वेतनमान लगभग 80 हजार रुपये प्रतिमाह तथा अधिकारी स्तर का वेतनमान एक लाख से ऊपर का निर्धारित है. इन नियमित कर्मचारियों की तुलना में संविदा कर्मचारियों का वेतन ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है. सूत्रों के अनुसार इन कर्मचारियों को मिलने वाले पीएफ का हिस्सा तो काट लिया जाता है लेकिन प्रतिष्ठान की ओर से उसे जमा नहीं किया जाता है और अभी तक अधिकतम कर्मचारियों को इसकी रसीद भी नहीं मिली है. सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व सीएसई आदि विभागों में काम करने वाले लगभग एक हजार संविदा कर्मचारी प्लांट के अंदर हैं जो विद्युत उत्पादन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं.

भवानी पेपर मिल भी कर रहा है मजदूरों का शोषण

रायबरेली शहर स्थित भवानी पेपर मिल में मजदूरों को बीते अप्रैल माह से वेतन नहीं मिल पाया. जिससे दीपावली पर भी उनके घरों में दीये नहीं जले. यहां भी स्थिति ऐसी ही है कि यदि कर्मचारी मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं तो उन्हें किसी न किसी बहाने बाहर का रास्ता दिखा ही दिया जाता है. बलवंत सिंह 1986 से यहां ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे हैं. जबकि लेटर उन्हें हेल्पर का मिला हुआ है. वेतनमान मात्र 43 सौ रुपये प्रतिमाह है. आशाराम मिश्रा 1987 से मैकेनिकल फिटर के पद पर कार्यरत हैं, पर उनका वेतनमान मात्र 42 सौ रुपये है. इसी तरह के सैकड़ों कर्मचारी भवानी पेपर मिल में कार्यरत हैं, जिन्हें बीते छह-सात महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है. इसके लिए संघर्ष भी हुआ, प्रशासनिक हस्तक्षेप भी हुआ, लेकिन नतीजा यही निकला कि कुछ लोगों को एक दो महीनों का वेतन मिला, शेष कर्मचारियों का मामला उसी तरह लटका पड़ा है. विरोध करने वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. ■

आसुओं से भरी है इनकी जिंदगी

जब संविदा कर्मचारियों से उनकी समस्याओं का जिक्र किया जाता है तो बरबस ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. रामसजीवन 22 साल से, नंदकिशोर 16 साल से और पांच साल से काम कर रहे मनीष कुमार मौर्य जैसे दर्जनों कर्मचारी टीएमडी मेंटिनेंस टरबाइन पर 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिमाह मात्र 45 सौ रुपये ही वेतन मिलता है. दशरथ मौर्य ब्वॉयलर हाउस कीपिंग का 12 घंटे काम करते हैं, जबकि उनको वेतन मात्र 36 सौ रुपये प्रतिमाह मिलता है. रामकिशोर, सूरजपाल, रामलखन, छोटेलाल, अभयराज, शंकर वर्मा, मुस्तकीम, आरके मौर्या, भुल्लन, जगतनारायण आदि कर्मचारी भी इसी तरह शोषित हो रहे हैं. जब रामसजीवन ने जीविकोपार्जन के लिए पेमेन्ट बढ़ाने की बात कही तो उन्हें निकालने की धमकी के साथ उन्हें सजा के तौर पर कबाड़ उठाने के लिए नियुक्त कर दिया गया. जबकि इसके पहले रामसजीवन सेंट्री फ्यूल मशीन, पोरटेबल मशीन, बीएफपी मशीन, मेन कन्ट्रोल वाल आदि का मेंटिनेंस का काम करते थे.

इसी तरह 1985 से कार्यरत मास्टर प्लम्बर रामबरन एनटीपीसी के विश्वासपात्र प्लम्बर माने जाते थे. 18 जुलाई 2012 तक यूपीएल के अधीनस्थ टेंडर था, जिसकी देखरेख दशरथ सिंह के पुत्र मनोज सिंह करते थे. रामबरन उन्हीं की देखरेख में काम करते थे. जब स्वयं दशरथ सिंह के नाम पर टेंडर हो गया तो वह इन्हीं लोगों का वेतन कम करने लगे. जब इसका कर्मचारियों ने विरोध किया तो एनटीपीसी जनरल मैनेजर के साथ मिलकर ठेकेदार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. तब से रामबरन दर-दर की ठोकरें खा रहा है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है. उसका परिवार भुखमरी के कगार पर है. इस अत्याचार और आतंक का दारोमदार प्रतिष्ठान में काम कर रहे कुछ पुरोधा कर्मचारी नेताओं व अधिकारियों का है. भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा विष्णु शुक्ल इन कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं. कर्मचारियों की पीड़ा की जानकारी एएलसी अमित कुमार मिश्रा से लेकर अन्य अधिकारियों तक पहुंची है. दयनीय हालत में पहुंच चुके कर्मचारियों की तकलीफ के बारे में सरकार तक जानकारी पहुंचे, उसकी व्यवस्था की जा रही है.

इस बारे में जब एनटीपीसी के डीजीएम अजीत कुमार सिंह से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने टालने वाले अंदाज में कहा, मैंने तो अभी जल्दी ही इस पद पर ज्वाइन किया है. मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है. जब उनसे उनकी ज्वाइनिंग की तारीख या साल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, दो साल. ऐसे डीजीएम से संविदा कर्मचारियों की समस्यायें कितनी दूर होंगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए यूपी चुनाव पर निशाना

संतोष कुमार नागर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए क्षेत्रीय व जातिगत सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह साधने का प्रयास तो किया पर उसे सही ढंग से साध नहीं पाए. मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के 2016 और उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनावों के मद्देनजर जातिगत समीकरण साधने का प्रयास करने के बावजूद भाजपा की वास्तविक सोच से हट कर नरेन्द्र मोदी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग लगभग उपेक्षित ही रह गया. कहने को भले ही मंत्रिमंडल में कुर्मी, कोयरी, कुर्बा, कोली, केवट, निषाद, यादव, जाट, गूजर, लिंगायत, बोक्कालिगा आदि पिछड़े वर्ग की जातियों को शामिल किया गया है, पर किसी अतिपिछड़े को मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं मिला. भाजपा का मिशन यूपी का सियासी चौसर बिछाने के लिए जातियों को साधने की कवायद में तेजी से जुटी है. मिशन-2017 के लिए उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, अतिपिछड़ों का भरपूर सहयोग मिले बिना भाजपा को सत्ता की चाभी मिलनी कठिन है.

बिहार में 2016 में विधानसभा का चुनाव होना है. ऐसे में लालू यादव के हनुमान राम कृपाल यादव, भाजपा के सहयोगी दल के उपेन्द्र कुशवाहा तथा यूपी में पिछड़े वर्ग की जातियों में सर्वाधिक 12 प्रतिशत संख्या वाली निषाद समाज की साध्वी निरंजन ज्योति निषाद, 3.5 प्रतिशत से अधिक संख्या वाले संतोष गंगवार सहित जाट समाज के तीन और गूजर समाज (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा) से मात्र एक राज्यमंत्री बनाकर पिछड़ों का हितैषी व राजनीतिक सम्मान देने का पक्षधर होने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया. पिछड़े वर्ग से 66 मंत्रियों में मात्र उमा भारती को कैबिनेट में स्थान दिया गया है. यूपी से पांच और मध्य प्रदेश से एक लोधी सहित छह लोधी सांसद हैं, इसी तरह यूपी से तीन, गुजरात से पांच, गोवा और ओड़ीशा से दो-दो, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, दादरा नगर हवेली से एक-एक निषादवंशीय सांसद होने के बावजूद केवल निरंजन ज्योति को मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के तौर पर स्थान मिला है. भाजपा को अच्छी तरह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में निषाद, मछुआरा समुदाय की मल्लाह, केवट, बिन्दु, धीवर, कहार, रायकवार, मांझी, बाथम, गोड़िया आदि की आबादी पिछड़े वर्ग में अन्य सभी जातियों यहां तक कि यादव से भी अधिक है, ऐसे में निरंजन ज्योति को आगे करना राजनीतिक दृष्टि से काफी फायदेमंद रहेगा.

उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में सर्वाधिक निषाद मछुआरा-12 प्रतिशत से अधिक और दूसरे नम्बर पर यादव-8.6 प्रतिशत, गड़ेरिया/पाल- 2.65 प्रतिशत, कुर्मी- 3.5 प्रतिशत, कुशवाहा/मौर्य- लगभग 5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जातियां 1-2 प्रतिशत के बीच हैं. जिनमें राजभर, चौहान, तेली, जाट, बढ़ई/लोहार, प्रजापति आदि जातियां आती हैं. 2017 के चुनाव के संदर्भ में अतिपिछड़े वर्ग के सामाजिक चिन्तक चौधरी लौटन राम निषाद ने बताया कि 2017 के चुनाव में अत्यन्त पिछड़े वर्ग की परिवर्तन की दृष्टि से मुख्य भूमिका होगी. उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण में हिन्दू/मुस्लिम स्वर्ण जातियां- 20.94 प्रतिशत, अहिर/यादव- 8.6 प्रतिशत, सभी मुस्लिम-14 प्रतिशत, दलित- 25 प्रतिशत, अतिपिछड़ी जाति जाट, गूजर, कलवार, कुर्मी, अरक, सोनार, गोसाई, लोधी आदि-10.22 तथा अत्यन्त पिछड़ी निषाद, कश्यप, पाल, बघेल, प्रजापति, राजभर, चैहान, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी किसान, तेली, नाई, विश्वकर्मा आदि 33 प्रतिशत से अधिक हैं, ऐसे में अत्यन्त पिछड़े वर्ग की भूमिका सबसे खास होगी.

भाजपा 2017 के विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अभी से लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति की कवायद में जुट गई है और बसपा भी अपने मूल वोट बैंक दलित को साधने का काम कर रही है. उत्तर प्रदेश में अतिपिछड़ा वर्ग अपने को राजनीतिक रूप से काफी उपेक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि अतिपिछड़े के नाम पर राजेन्द्र चौधरी (जाट) राजनीतिक पेंशन व राम मूर्ति वर्मा (कुर्मी), दुग्ध विकास जैसे महत्वहीन विभाग के मंत्री हैं. हां, अत्यन्त पिछड़े वर्ग से गायत्री प्रसाद प्रजापति को काफी महत्व मिला, जिनकी बिरादरी का किसी भी विधानसभा में 5-10 हजार भी मत नहीं होता. कहार जाति में शंख लाल मांझी, लोधी, किसान समाज के राममूर्ति सिंह वर्मा, मान पाल सिंह वर्मा, पाल समाज के विजय बहादुर पाल को राज्यमंत्री बनाकर इन जातियों को उपेक्षित किया गया है. फिर भी उत्तर प्रदेश में अत्यन्त पिछड़े ही चुनाव में सबसे खास भूमिका निभाने की स्थिति में हैं. भाजपा में लौटन राम निषाद को पिछड़े वर्ग की आवाज समझा जाता था. राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भाजपा में सामाजिक न्याय मोर्चा का गठन उन्हीं के प्रस्ताव पर किया था. निषाद ने लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को कम से कम 25 सीटें देने की मांग की थी. भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को 26 टिकट दिए जिसमें से 24 प्रत्याशी चुनाव जीत गए जो उत्तर प्रदेश के अब तक के चुनावों में रिकार्ड है.

श्री निषाद ने कहा कि सामाजिक न्याय व सामाजिक धर्म उनके लिए अधिक सर्वोपरि है. यदि भाजपा सरकार मझवार, तुरैहा, गौड़, सिल्पकार, पासी, बेलदार जातियों को परिभाषित कर दे, मल्लाह, केवट, मांझी, बिन्द, धीवर, धीमर, कहार, गोड़िया, धुरिया, रायकवार, कुम्हार, नोनिया, भर आदि को अनुसूचित जाति का आरक्षण दे दे, रेणके कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के साथ वीर एकलव्य पुरस्कार, राम सखा निषाद राज की जयंती पर चैत्र शुक्ल पंचमी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दे और फरक्का बैराज में फिश गेट बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय मछुआरा आयोग और अन्तरराष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा विवाद निवारण परिषद गठित कर दे तो भाजपा को खुद व खुद एक व्यापक जन समुदाय का साथ मिल जाएगा. भारतीय जनता पार्टी को इसका असर न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में देखने को मिलेगा. ■

व्यापक निषाद समुदाय को नष्ट करने में लगी भाजपा: लौटन राम

गंगा-गोमती के निर्मलीकरण के नाम पर भाजपा व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राजनीति अतिपिछड़े निषाद, केवट, मल्लाह, धीवर, कश्यप समाज को भ्रमित करने की है. राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव व समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद ने कहा कि नदियों की सफाई व उसमें अविरल जल का प्रवाह जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर राजनीति करना उचित नहीं. उन्होंने केन्द्र सरकार से फरक्का बैराज में फिश गेट बनाने की मांग के साथ-साथ गंगा पुत्रों के उत्थान व विकास के लिए कारगर कदम उठाने की मांग की है. निषाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अतिपिछड़ों की बदौलत अप्रत्याशित जीत हासिल करने वाली भाजपा अब अतिपिछड़ों को हर स्तर पर उपेक्षित करने व दरकिनार करने का काम कर रही है. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भाजपा कोटे से भेजे जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब पार्रिकर उत्तर प्रदेश के मतदाता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जाना कहां तक उचित था. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल वोट बैंक के लिए पिछड़ों, अतिपिछड़ों व दलितों की बात करती है, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के बाद धीरे-धीरे उन्हें दरकिनार करने के काम में जुट जाती है. उन्होंने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी, मोदी मंत्रिमंडल व प्रदेश प्रभारियों में केवल 10 प्रतिशत संख्या वालों का ही वर्चस्व है, एक भी अतिपिछड़े को इसमें स्थान नहीं दिया गया. मनोहर पार्रिकर (ब्राह्मण) को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजकर स्वर्ण कार्ड खेलते हुए भाजपा ने पिछड़ों अतिपिछड़ों को नकार दिया है. 2017 के विधानसभा चुनाव में यह उपेक्षित वर्ग भाजपा को सबक सिखा देगा. लौटन राम ने कहा कि निषाद जाति के किसान भाजपा व वाजपेयी की दृष्टि में किसान नहीं हैं. मथुरा के गोकुल बैराज भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की दृष्टि में निषाद जाति के किसान, किसान नहीं है. भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री कुंअर सिंह निषाद एडवोकेट भी गोकुल बैराज प्रकरण को लेकर किसानों के साथ अन्दोलन में शामिल हुए थे और 56 निषाद किसानों के साथ जेल में बन्द हैं, लेकिन कोई भाजपा नेता उनका हाल चाल पूछने तक नहीं गया. भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष राय व कुछ अन्य लोग जो कुंअर सिंह निषाद से मिलने गए थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की फटकार सुननी पड़ी. उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर अतिपिछड़ा विरोधी व तुच्छ जातिवादी होने का आरोप लगाया. उल्लेखनीय है कि 16 वर्ष पूर्व गोकुल बैराज के नाम पर भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही औरंगाबाद, दामोदरपुरा, बीसनगंज, हंसगंज, मुर्शीदपुर, मथुरा खागर, मिर्जापुर, माधवपुर, मई, रावल आदि गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी. उनमें 90 प्रतिशत किसान निषाद ही हैं, जिनका 450 करोड़ मुआवजा अब तक बकाया है. मुआवजे की मांग पर ही किसान आन्दोलन कर रहे थे, जिनपर पुलिस ने लाठियां चलाईं और फायरिंग की थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

बसपा को दलित-ब्राह्मण वोट का सहारा

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से अपने लगातार घटते जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के भीतर खासी छटपटाहट नजर आ रही है. अपने पुराने जनाधार को आधार बना कर दलित-ब्राह्मण वोट के सहारे बसपा की हाथी एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ने की जद्दोजहद में लगी है. बसपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन को उत्तराखंड में एक बार फिर से शक्ति कायम करने के लिए कहा है. इसके लिए वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर पार्टी की रणनीति तैयार की जा रही है. बसपा सुप्रिमो मायावती की मंसा है कि पार्टी अब मैदान ही नहीं, बल्कि पर्वतीय जिलों में भी संगठन को मजबूत किया जाए. उत्तराखंड की राजनीति में तीसरे सबसे बड़े दल की हैसियत रखने वाली बसपा को पिछले कुछ वर्षों में सियासी अपने ही आत्मघाती फैसले के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा है. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ तीन सीटों पर ही जीत मिली, जबकि इससे पूर्व विधानसभा में पार्टी विधायकों की संख्या आठ तक जा पहुंची थी. 2012 के चुनाव के बाद बनी राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से बसपा को महज तीन विधायकों के बूते सरकार में भागीदारी का अवसर जरूर मिला, इन परिस्थितियों में भी बसपा को फायदे की बजाय नुकसान ही अधिक झेलना पड़ रहा है. बसपा के तीन में से दो विधायकों को पार्टी मुखिया मायावती की कसौटी पर खरा न उतरने के कारण पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है. कुछ ऐसे ही हालात बसपा के प्रदेश संगठन में भी पैदा हुए. पार्टी नेताओं के बीच बढ़ती गुटबाजी व अंतर्कलह सांगठनिक तौर पर भी बसपा को लगातार कमजोर करती चली गई. पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में बसपा को इन विपरीत हालात से बाहर निकालने के लिए प्रदेश संगठन में कुछ माह पूर्व ही बड़ा फेरबदल किया. इसके लिए 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर ठोस रणनीति भी तैयार की जा रही है. पार्टी के प्रदेश प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दिकी पार्टी को सिर्फ मैदानी जिलों में सिमटने की बजाय पर्वतीय क्षेत्रों में भी संगठन को मजबूत करने के निर्देश दे चुके हैं. प्रदेश अध्यक्ष सीपी सिंह इसी रणनीति के तहत इन दिनों पर्वतीय जिलों के दौरे पर हैं. बसपा सुप्रिमों मायावती हर हाल में वर्ष 2017 में सत्ता की चाभी बसपा के हाथ में हो इसी मंसा से बनाए अपने रणनीति पर काम कर रही हैं. ■

भाजपा विधायक की मौजूदगी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं

रुद्रपुर तहसील का लोकार्पण कार्यक्रम अराजकता की भेंट चढ़ गया और मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा दिया. उसके बाद मुख्यमंत्री ने बवाल कर रहे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया. वहीं भाजपा विधायक ठुकराल व कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ भी सीएम के सामने आपस में भिड़ गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कांग्रेस मुक्त राजनीति करने की मंसा से हरियाणा से शुरूआत की है उसका दुस परिणाम उत्तराखंड में दिखा. कांग्रेस के नेता भी अब मंच पर भाजपाईयों को बर्दास्त करने को तैयार नहीं हैं. यह घटना इसी का उदाहरण है. मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कार्यकर्ता अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए उत्पात मचाने लगे. इससे सभास्थल पर अफरातफरी मच गई. मुख्यमंत्री ने इस पर ऐतराज जताया और उन्होंने जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट से कहा कि जिन कांग्रेसियों ने कार्यक्रम में उपद्रव मचाया है उनकी सूची बनाकर दी जाए. पार्टी ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी. कार्यक्रम में काबीना मंत्री इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी नाराजगी जताते हुए कार्यकर्ताओं को मंच से हटा दिया. वहीं कार्यक्रम में विधायक राजकुमार ठुकराल और बीज प्रमाणीकरण संस्था के अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ में किसी बात पर मुख्यमंत्री के सामने कहासुनी हो गई. विधायक ठुकराल मंच से उतरकर नीचे दरी पर बैठ गए. कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने विधायक को मनाने का प्रयास किया, लेकिन ठुकराल नहीं माने. मामला बढ़ने पर ठुकराल मंच छोड़कर चले गए. विधायक ठुकराल ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक होने के चलते उन्हें कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया था. उन्होंने कहा कि साजिश के तहत कांग्रेसियों ने उन्हें अपमानित किया. वह शालीनता से संबोधन कर रहे थे. मंच पर कांग्रेसियों ने अव्यवस्थाएं फैला रखी थीं. इसके चलते उन्हें बीच में संबोधन रोकना पड़ा. कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष उनसे गाली गलौज के साथ मारपीट करने की कोशिश की. भाजपा विधायक ठुकराल के साथ हुई नोक-झोंक के चलते विधायक प्रवक्ता आशीष छाबड़ा ने इसका विरोध किया तो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे हाथापाई करने पर उतारू हो गए. तहसील के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे लोगों और पुलिसकर्मियों में धक्का-मुक्की हुई. ■